



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2019/श्रावण 31, 1941

No. 259]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2019/SHRAVANA 31, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2019

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. से अट्राजिन टेक्निकल के आयातों से संबंधित सब्सिडीरोधी जांच।

क. इस मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 6/19/2018.—डी जी ए डी : सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है (इसके पश्चात “अधिनियम” के रूप में भी संदर्भित), तथा उसके सीमा प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिकारी शुल्क की पहचान आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 जिसे समय समय पर संशोधित किया गया (इसके पश्चात “नियमावली” अथवा “प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/ सी वी डी नियमावली” के रूप में भी संदर्भित”) के संबंध में;

- जबकि, मैसर्स मेघमणि इंडस्ट्रीज लिमि. (इसके पश्चात “याचिकाकर्ता” अथवा “घरेलू उद्योग” के रूप में भी संदर्भित) ने चीन जनवादी गणराज्य (इसके पश्चात “संवद्ध देश” के रूप में भी संदर्भित) से “अट्राजिन टेक्निकल” के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके पश्चात “प्राधिकारी” के रूप में भी संदर्भित) के समक्ष मैसर्स इनसेक्टीसाइड्स (इण्डिया) द्वारा समर्थन की गई एक याचिका दायर की है।

2. और, जबकि प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर कथित सब्सिडी के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा सब्सिडीरोधी/ प्रतिकारी शुल्क यदि उसे लगाया जाये, जो घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए समुचित होगा, की सिफारिश करने के लिए नियम 6 के अनुसार संबद्ध जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. 6/19/2018 – डी जी ए डी के संदर्भ में एक आम सूचना जारी की।

ख. प्रक्रिया

3. संबद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का प्राधिकारी द्वारा पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने प्रतिकारी शुल्क नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार इस जांच को आरंभ करने की कार्यवाही करने से पूर्व वर्तमान सब्सिडीरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में चीन के जनवादी गणराज्य के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार इस स्थिति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से विचार विमर्श के लिए चीन जन. गण. की सरकार को आमंत्रित किया। यह विचार विमर्श 11 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ था जिसमें चीन जन. गण. की सरकार (इसके पश्चात् “जी ओ सी” के रूप में भी संदर्भित) के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया था। चीन की सरकार द्वारा स्पष्ट किये गये इन मुद्दों को रिकार्ड पर लिया गया था।

ग. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/ सब्सिडीरोधी जांच आरंभ करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 27 अगस्त, 2018 को एक आम सूचना जारी की।

घ. प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास, चीन जनवादी गणराज्य के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं और घरेलू उद्योग तथा समर्थक, मैसर्स इनसेक्टीसाइड्स (इण्डिया) लिमि. को याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराये गये नाम और पते के अनुसार दिनांक 27 अगस्त, 2018 के जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत करायें।

इ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 7(3) के अनुसार भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को भारत ने ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास को आवेदन के अगोपनीय पाठ एक प्रति उपलब्ध कराई।

ज. भारत में चीन जनवादी गणराज्य के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने देशों के निर्यातकों/ उत्पादकों को प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गये पत्र और प्रश्नावली के एक प्रति भी चीन जनवादी गणराज्य से ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।

क्ष. प्राधिकारी ने विभिन्न योजना/ कार्यक्रमों के संबंध में संगत तथ्यों/ सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से चीन की सरकार (चीन सरकार) को प्रश्नावली भेजी जहां प्रतिसंतुलनकारी लाभ चीन की सरकार द्वारा दिया जा सकता था।

ज. इसके अलावा, नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार चीन की जनवादी सरकार में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :

- i. झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि.
- ii. शानडॉग विन्नोग टेक्नोलाजी कं., लिमि.
- iii. शानडॉग वेफंग रेनबो केमिकल कं., लिमि.

- iv. झेजियांग प्रोविन्स चेंगसिंग फ्रस्ट केमिकल कं., लिमि.
- v. शानडॉग विकम ग्रीनलैंड केम कं., लिमि.
- vi. लियोनिंग तियांगी पेप्सीसाइड्स केमिकल कं., लिमि.
- vii. जिनन केसर्ई एरोकेम कं., लिमि.
- viii. शानडॉग कियोचांग केमिकल कं., लिमि.
- ix. इसके उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र में निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर (ई क्यू आर) प्रस्तुत किया :

 - i. सियांगशुई झोंगशन बायोसाइंस कं., लिमि.
 - ii. झोजियांग झोंगशन केमिकल्स इंडस्ट्री ग्रुप कं., लिमि.
 - iii. अनहुई झोंगशन केमिकल्स इंडस्ट्री कं., लिमि.

- x. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ उपभोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजीं :

 - i. राल्लिस इंडिया लिमि.
 - ii. विजयालक्ष्मी इनसेक्टीसाइड्स पेप्सीसाइड्स लिमि.
 - iii. पल इंडस्ट्रीज लिमि.
 - iv. वेनटेक केमिकल्स लिमि.
 - v. सुदर्शन कंसोलिडेटिड लिमि.
 - vi. नागार्जुना कंसोलिडेटिड लिमि.
 - vii. जी एस पी क्रॉप साइंस प्रा. लिमि.
 - viii. बेस्ट एग्रोकेम प्रा. लिमि.
 - ix. एच पी एम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमि.

- xi. उत्तर में, भारत के निम्नलिखित आयातकों ने निर्धारित प्रपत्र में आयातक की प्रश्नावली का उत्तर (आई क्यू आर) प्रस्तुत किया :

 - i. ए डी ए एम ए इंडिया प्रा. लिमि.;
 - ii. क्रस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमि.;
 - iii. कृषि रसायन एक्सपोर्ट प्रा. लिमि.

- xii. ऊपर में उल्लेख किये गये प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के अलावा, मैसर्स चीन क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसो. (सी सी पी आई ए) की ओर से कुछ कानूनी अनुरोध प्राप्त हुए हैं।
- xiii. प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य/ किये गये निवेदनों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।

द. वाणिज्यिक सूचना एवं सांचियकीय महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से यह अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए (पी ओ आई) संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन देन वार व्यौरा उपलब्ध करायें जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था। प्राधिकारी ने इन लेन-देन की उचित जांच करने के बाद आयातों की मात्रा की गणना और अपेक्षित विश्लेषण के लिए जहां भी आवश्यक हुआ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ए. उत्पादक की लागत और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु का निर्माण करने और इसकी विक्री करने के लिए लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एन आई पी) निर्धारित की गई है जिससे कि यह पता चल सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन की तुलना में कमतर प्रतिकारी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का मौके पर सत्यापन के माध्यम से भौतिक निरीक्षण उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जहां भी लागू हुआ आवश्यक संशोधनों के साथ केवल इस प्रकार की सत्यापित सूचना पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।

थ. उत्तर देने वाले उत्पादकों/ नियर्तिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया गया है जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया और इन पक्षकारों द्वारा जिस सीमा तक इस प्रकार की सूचना और साक्ष्य निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराया गया उस पर वर्तमान जांच परिणाम के उद्देश्य से विश्वास किया गया है।

द. वर्तमान सब्सिडीरोधी जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पी ओ आई) अप्रैल 2017 से मार्च 2018 (12 महीने) तक है। हालांकि, क्षति की जांच की अवधि को 2014-15, 2015-16, 2016-17 से तथा जांच की अवधि (पी ओ आई) तक की अवधि के रूप में माना गया है।

ध. इस नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी दिया कि वे दिनांक 15 फरवरी, 2019 को हुई सुनवाई में अपने विचारों को मौखिक रूप से प्रस्तुत करें। उन सभी पक्षकारों जिन्होंने मौखिक सुनवाई में भाग लिया था, को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किये गये इन विचारों को लिखित निवेदनों के रूप में प्रस्तुत करें। इन पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की प्रतियां प्राप्त करें और उनके खंडन/ प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

न. इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए लिखित निवेदनों/ प्रति उत्तरों में दिये गये तर्कों पर उस सीमा तक वर्तमान जांच परिणाम में विचार किया गया है जिस सीमा तक उसे वर्तमान उद्देश्यों से संगत और आवश्यक माना गया।

प. जहां भी संगत और वास्तविक पाया गया, इस जांच की अवधि के दौरान इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये निवेदनों का निवारण प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है।

फ. इन हितबद्ध पक्षकारों गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, जहां भी आवश्यक हुआ प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किये गये के रूप में माना गया है। जहां भी संभव हुआ गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें।

ब. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की अवधि के दौरान आवश्यक सूचना देने से इनकार किया है अथवा अन्य प्रकार से उपलब्ध नहीं कराया है अथवा अविश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराई है, इस जांच में काफी हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने इस प्रकार के पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम में दर्ज किया है।

भ. प्रकटन विवरण हितबद्ध पक्षकारों को 9 अगस्त, 2019 को जारी किया गया था जिसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्य निहित थे और प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 16 अगस्त, 2019 तक का समय दिया गया था। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा लिया गया विनिमय दर यू.एस.डॉलर 1 = 65.33 है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच शुरूआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा नीचे दिये गये अनुसार की गई है :

“विचाराधीन उत्पाद विभिन्न प्रशुल्क उपशीर्षक सं. 38089299, 38089390 और 38089990 के अंतर्गत वर्गीकरण किये जाने लायक “अट्राजिन टेक्निकल” है। अट्राजिन के लिए वैज्ञानिक 6- क्लोरो-एन-एथिन- (1-मेथिलेथिल) - ट्राइजिन-2, 4 – डाइमाइन है।”

5. अट्राजिन टेक्निकल सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाले तृणनाशक है। यह एक क्रमिक ट्राइजिन तृणनाशक है जिसे बड़े पक्के वाले अपतृण और धासदार अपतृण के विकास होने के पहले और उसके बाद उसे नियंत्रित करने के लिए पंजीकृत किया गया है। विशुद्ध अट्राजिन सफेद चूंन होता है जिसमें कोई गंध नहीं होती है और जो परिवर्तनशील, प्रतिक्रियाशील अथवा ज्वलनशील नहीं होता है। इसे प्रयोगशाला में बनाये गये रासायनिक फैक्ट्री में संश्लेषित किया जाता है और यह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं होता है। इसका अधिकांश उपयोग गन्ने, मकई, अनानास, ज्वार और मेकाडामिया नट्स जैसे फसलों पर खेतों में उपयोग किया जाता है और इसके साथ ही राजमार्ग और रेल मार्ग दोनों के मार्ग अधिकारों पर बढ़ने से इन धासों को रोकने के लिए भी किया जाता है। इसका चिट्ठकाव फसलों के विकसित होने से पूर्व खेतों में किया जा सकता है।

6. अट्राजिन टेक्निकल का पदनाम एक प्रतिबंधित उपयोग वाले कीटनाशक (आर.यू.पी) के रूप में रखा गया है और यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। कानूनी तौर पर आर.यू.पी केवल प्रमाणित उपयोग करने वालों अथवा उनके सीधे पर्यवेक्षण के अंतर्गत व्यक्तियों को विक्री के लिए उपलब्ध है और यह उपयोगकर्ता के प्रमाणन द्वारा शामिल किये गये उद्देश्य से ही उपलब्ध कराई जाती है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है जैसे

(क) 6-क्लोरो-एन-एथिन- (1-मेथिलेथिल) - ट्राइजिन-2, 4 – डाइमाइन;

(ख) 2-क्लोरो-4-एथिलामिनो-6- इसोप्रोपाइलामिनो-एस- ट्राइजिन;

(ग) 2-क्लोरो-4- (एथिलामिनो)-6- (इसोप्रोपाइलामिनो) -एस- ट्राइजिन;

(घ) 2-क्लोरो-4- (एथिलामिनो)-6- (इसोप्रोपाइलामिनो) -ट्राइजिन;

(ङ) क्लोरो-4- (प्रोपाइलामिनो)-6- इथीलामिनो-एस- ट्राइजिन;

(च) क्लोरो-4- (प्रोपाइलामिनो)-6- इथीलामिनो-एस- ट्राइजिन, इत्यादि

7. विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र में विचाराधीन उत्पाद के सभी पर्याय शामिल हैं।

घ. 1. घरेलू उद्योग किया गया अनुरोध

8. घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किया गया अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

क. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद “अट्राजिन टेक्निकल” है। अट्राजिन टेक्निकल का उपयोग फार्मा उद्योग में सक्रिय फार्मा संघटक की तरह किया जाता है। इस तकनीकी ग्रेड का उपयोग विभिन्न प्रकारों के

सूत्रीकरण जैसे अट्राजिन – 50 प्रतिशत डब्ल्यू पी, अट्राजिन – 80 प्रतिशत डब्ल्यू पी, अट्राजिन – 50 प्रतिशत एस सी, अट्राजिन – 80 प्रतिशत डब्ल्यू डी जी और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (सी आई बी आर सी) द्वारा यथाअनुमोदित इसके विपणन और विक्री के लिए विभिन्न संयोजन के साथ उत्पादों का निर्माण करने में किया जाता है। इस प्रकार से बनाये गये सूत्रीकरण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है।

ख. विशुद्ध अट्राजिन एक प्रकार का सफेद चूर्ण है, जिसमें गंध नहीं होता है और जो बहुत परिवर्तनशील, प्रतिक्रियाशील अथवा ज्वलनशील नहीं होता है। यह पानी में घुलनशील है। अट्राजिन का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण 3808 91 99, 3808 93 90 और 3808 99 90 के अंतर्गत किया जा सकता है।

घ. भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये और संबद्ध देश से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये उपभोक्ता इन दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं।

ड. यह याचिका स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि विचाराधीन उत्पाद को “अट्राजिन टेक्निकल” के रूप में परिभाषित किया गया है और इसके निर्माण की प्रक्रिया, उपयोग, कच्चा माल, उत्पाद विनिर्देश आदि का उल्लेख किया गया है।

च. इस याचिका में यह उल्लेख है कि सूत्रीकरण किसानों को विक्री किये जाने हेतु भारी मात्रा में अथवा खुदरा पैकिंग में पैक किया जाता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि सूत्रीकरण के उत्पादक अपने निजी ब्रांड नाम के अंतर्गत उसकी विक्री करते हैं। इस कारण से विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र इस याचिका में स्पष्ट है।

छ. विचाराधीन उत्पाद का कोई एवजी नहीं है क्योंकि अट्राजिन सूत्रीकरण का उत्पादक किसी अन्य उत्पाद का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पायेगा।

ज. यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि अट्राजिन तृणनाशक के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में अलग अलग तृणनाशक अलग अलग फसलों में उपयोग के लिए उपयुक्त हैं।

झ. बढ़ती हुई मांग और आयातों के आधार पर, सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अट्राजिन टेक्निकल के लिए तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से कोई व्यवहारीय प्रतिस्थानापन नहीं है।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

9. निर्यातकों, आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में किया गया अनुरोध और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोध नीचे दिये गये हैं :

क. याचिकाकर्ताओं ने इस उत्पाद के उपयोग के संबंध में सही सूचना उपलब्ध नहीं कराई है और यह उल्लेख किया है कि इसका छिड़काव फसलों पर किया जा सकता है और इसका उपयोग किसानों द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद अट्राजिन टेक्निकल है जिसका सीधा उपयोग किसानों द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसान केवल अट्राजिन सूत्रीकरण का उपयोग सीधे तौर पर कर सकते हैं।

ख. आवेदक उद्योग ने स्पष्ट रूप से यह अनुरोध किया है कि कोई व्यवहारीय एवजी नहीं है। एवजी के बारे में सूचना सी आई बी आर सी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस कारण से, घरेलू उद्योग यह तर्क नहीं ले सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना उन्हें मालूम नहीं थी। इस प्रकार से, इस याचिका में उपलब्ध कराई गई सूचना यह दर्शाती है कि आवेदक उद्योग ने माननीय प्राधिकारी को यह आवेदन प्रस्तुत करते समय पहले से ही स्वीकृत मान लिया है। इस कारण से, यह याचिका नियम 6(3) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

ग. यह याचिका नियम 6(3) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती है क्योंकि आवेदक उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के रूप में अट्राजिन टेक्निकल और सूत्रीकरण दोनों का संदर्भ संबद्ध वस्तुओं के रूप में लिया है। यद्यपि यह याचिका “अट्राजिन टेक्निकल” के संबंध में ही है।

घ. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र और उद्योग में परिवर्तन किया है। विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र और उपयोग घरेलू उद्योग के आवेदन में अलग अलग है जो डी जी टी आर द्वारा जारी की गई जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की तुलना में “अट्राजिन टेक्निकल” के संबंधित भी है। जहां यह जांच “अट्राजिन टेक्निकल” और इसके सूत्रीकरण दोनों के लिए आरंभ किया गया है।

ड. आवेदक उद्योग का सी आई बी पंजीकरण फार्म यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तुओं का उपयोग यह दर्शने के लिए सूत्रीकरण का उत्पादन करने के लिए किया जाता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित विचाराधीन उत्पाद का उपयोग विचाराधीन उत्पाद से प्राप्त सूत्रीकरण “अट्राजिन टेक्निकल” के संबंध में है और न कि “अट्राजिन टेक्निकल” के लिए है। प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि संबद्ध वस्तु किसानों द्वारा सीधे तौर पर फसलों पर उपयोग किये जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। जैसा कि आवेदक उद्योग द्वारा अपनी याचिकाओं में उल्लेख किया गया है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा पेशकश किये जा रहे विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के कायक्षेत्र के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों को नोट किया है। विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद जैसा कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में परिभाषित किया गया है “अट्राजिन टेक्निकल” है। अट्राजिन के लिए वैज्ञानिक नाम 6- क्लोरो-एन-एथिन’- (1-मेर्थीलेथील)-ट्राजिन5, 4-डायमिन है।

11. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के अध्याय 38 और आगे सीमा शुल्क उप-शीर्षक 38089199, 38989390 और 38089990 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह किसी भी प्रकार से उत्पाद के कार्यक्षेत्र पर वाध्यकारी नहीं है।

12. विशुद्ध अट्राजिन एक प्रकार का सफेद चूर्ण है, जिसमें गंध नहीं होती है और जो बहुत परिवर्तनशील, प्रतिक्रियाशील अथवा ज्वलनशील नहीं होता है। यह पानी में घुलनशील है। अट्राजिन का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है और यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होता है। विशुद्ध अट्राजिन का उपयोग सीधे तौर पर किसानों द्वारा अपने खेतों में नहीं किया जा सकता है और किसान केवल अट्राजिन सूत्रीकरण का उपयोग कर सकते हैं।

13. घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के संबंध में प्राधिकारी नीचे दिये गये अनुसार नोट करते हैं :

क. यद्यपि दायर की गई याचिका में अट्राजिन और अट्राजिन टेक्निकल दोनों का संदर्भ शामिल है चूंकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी ब्यौरे जिसमें निर्माण प्रक्रिया उपयोग, कच्चा माल, उत्पाद विनिर्देशन और शब्दावली शामिल है और वह वहीं तक सीमित नहीं है, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

ख. किसी भी स्थिति में, दिनांक 27 अगस्त, 2018 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि विचाराधीन उत्पाद केवल “अट्राजिन टेक्निकल” है। इस कारण से, विचाराधीन उत्पाद का कार्यक्षेत्र जांच शुरूआत के चरण से स्पष्ट है और इसमें “अट्राजिन सूत्रीकरण” शामिल नहीं था। इस प्रकार से, विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र के संबंध में कोई कमियां अथवा संदेह नहीं हैं।

ग. संबद्ध वस्तुओं के एवजी की उपलब्धता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया है कि कौन से उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के लिए एवजी

के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि अट्राजिन सूत्रीकरण का एवजी वर्तमन जांच के लिए संगत नहीं है क्योंकि ये सूत्रीकरण विचाराधीन उत्पाद के लिए नहीं बल्कि डाउन स्ट्रीम उत्पाद के लिए ही है।

14. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों का विशेषण करने के बाद उत्पाद के कार्यक्षेत्र की जांच की है और परिणामस्वरूप जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में यथापरिभाषित कार्यक्षेत्र के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है।
15. किसी भी हितबद्ध पक्षकारों ने समान वस्तु के संबंध में अनुरोध नहीं किए हैं। प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जन. गण. के निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किये गये समान वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादन किये गये समान वस्तु और चीन जन. गण. से आयात किये गये संबद्ध वस्तु उत्पाद की विशेषताओं, निमर्ण की प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, उपयोग और कार्य, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और वस्तुओं का प्रशुल्क वर्गीकरण के मामले में तुलनीय नहीं हैं। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किये गये अट्राजिन टेक्निकल नियमावली और सभिस्डी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी करार (ए एस सी एम) के अनुसार चीन जन. गण. के आयात किये गये विचाराधीन उत्पाद का समान वस्तु है।

घ. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और आधार

घ. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

16. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आधार के संबंध में जांच की अवधि के दौरान किये गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :
 - क. यह याचिकाकर्ता कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़े हिस्से के लिये उत्तरदायी है और इस कारण से सी वी डी नियमावली के नियम 2(घ) में यथापरिभाषित घरेलू उद्योग है।
 - ख. संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहचान की गई कंपनियां अट्राजिन सूत्रीकरण का उत्पादक हैं और इस कारण से विचाराधीन उत्पाद का उपभोक्ता है।
 - ग. याचिकाकर्ता और समर्थक दोनों ने संबंधित सभी सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है। याचिकाकर्ता भारत के बाहर संबद्ध उत्पाद का किसी उत्पादक – निर्यातिक से संबंधित नहीं है।
 - घ. घरेलू उद्योग का विशेष आर्थिक क्षेत्र संयंत्र को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि यह घरेलू उत्पादन में लगा हुआ है। नियम 2(ख) का संदर्भ “घरेलू उत्पादन” और न कि “विक्री” अथवा “उत्पादन के उपयोग” से है।
 - ड. विशेष आर्थिक क्षेत्र संयंत्र वास्तव में, घरेलू बाजार में भी विक्री में लगा हुआ है।
 - च. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 54 को विशेष आर्थिक क्षेत्र को सीमा शुल्क प्रक्षेत्र के बाहर की इकाईयों के रूप में मानता है, के संबंध में तर्कों के बारे में यह अनुरोध किया गया था कि यह धारा कानून के अंतर्गत एक अभिगृहित कल्पना और उस कानून के उद्देश्य से ही सृजित करता है।
 - छ. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के उद्देश्यों से ही ऐसा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को “भारत के बाहर” के रूप में माना जाता है। हालांकि, यह केवल एक कानूनी कल्पना है जिसे उस अधिनियम के उद्देश्यों से बनाया गया है और यह भारतीय कंपनी के रूप में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के बदले में कोई परिवर्तन नहीं करता है। इसका निर्णय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के इंडिया एक्सपोर्ट बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में फैसले के द्वारा किया गया है।

ज. सभी घरेलू कानून विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लागू होते हैं और इस कारण से उन्हें केवल इस कारण से बाहर नहीं किया जा सकता है कि इसे शुल्क के भुगतान के बिना इनपुट के आयात की अनुमति दी गई है।

झ. हितबद्ध पक्षकारों ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 के किसी प्रावधान की पहचान नहीं की है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को बाहर करने की अनुमति देता है।

ञ. प्रत्यक्ष कर से छूट किसी इकाई को विचार किये जाने के हक से वंचित नहीं करता है। अनेक कंपनियों को धारा 80ए, धारा 80-बी और आदि के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर से छूट पाने का अधिकार प्राप्त है जिसे घरेलू उद्योग के हिस्से के रूप में माना गया है।

ट. विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों से निर्यात पर भारत के मूल के निर्यातों के रूप में अन्य अधिकार क्षेत्रों में व्यापार सुरक्षा शुल्क लग सकता है। वास्तव में प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को भारत से निर्यातों के विरुद्ध उन लाभों के कारण लगाया गया है जो इस प्रकार की इकाई को दिया गया है।

ठ. डी टी ए को विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई द्वारा की गई बिक्री को डी जी सी आई एंड एस द्वारा उपलब्ध कराये गये आयात संबंधी आंकड़ों में आयातों के रूप में रिकाई नहीं किया जाता है जबकि इसके निर्यातों को भारत से निर्यातों के रूप में माना जाता है।

ड. अनेक देश विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान योजनाएं चलाते हैं। इस प्रकार के प्रक्षेत्र से निर्यात की गई वस्तुओं को इस प्रकार के देशों से निर्यातों और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा माना गया पाटनरोधी शुल्क/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के रूप में माना जाता है। उसी तर्क से, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन पर भारत में घरेलू उद्योग के भाग के रूप में अलग से विचार किया जाना चाहिए।

ढ. निर्दिष्ट प्राधिकारी के विगत जांच परिणामों में अर्थात् सोलर सैल, पोलीप्रोलिन आदि के मामले में विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना जाता है।

ण. इसके अलावा, अनेक मामलों में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एक निर्यात उन्मुख एकक को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में माना है। हालांकि, निर्यात उन्मुख एकक से लाभों और विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों और निर्यात उन्मुख इकाईयों पर लागू प्रावधानों की तुलना यह दर्शायेगी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के पास निर्यात उन्मुख इकाईयों के विपरीत एक घरेलू उत्पादक के रूप में माने जाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक पात्रता है। ऐसा इस कारण से है कि जबकि 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख एकक को घरेलू बाजार में इसके उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक बिक्री से वंचित किया गया है। अतः इस प्रकार की कोई रोक विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों पर नहीं लगाई गई है।

त. उच्च न्यायालय ने लगातार यह नोट किया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों को भारत के प्रक्षेत्रों से बाहर नहीं माना जा सकता है। इस कारण से, इस प्रकार की किसी इकाई को बाहर नहीं किया जा सकता है।

थ. पक्षपात के बिना यदि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को बाहर भी कर दिया जाता है तब याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादन के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी होंगे।

द. इस अनुरोध में कोई दम नहीं है कि इण्डिया इनसेक्टीसाइड्स लिमि. को इसलिए बाहर किया गया है ताकि भारत में इस उद्योग की हालत के कार्य निष्पादन सूचकांकों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके क्योंकि याचिकाकर्ता एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी है।

ध. इनसेक्टीसाइड्स इण्डिया लिमि. द्वारा संभवतः इस कारण से भाग नहीं लिया गया है कि अट्राजिन टेक्निकल इस उत्पादक के लिए एक बड़ा उत्पाद नहीं है और कंपनी के कुल राजस्व में इसका हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत कम है और यह अपने राजस्व की अपेक्षाकृत छोटे हिस्से के लिए है।

न. इस कारण से याचिकाकर्ता कंपनी प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अंतर्गत दिये गये निर्धारित मानदंडों के भीतर घरेलू उद्योग है और यह आधार की आवश्यकता को पूरा करता है।

घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

17. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र और आधार के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध नीचे दिये गये अनुसार हैं :

- क. प्राधिकारी की वर्तमान प्रथा और इस देश में कानूनी स्थिति के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई में घरेलू उद्योग के उत्पादन को घरेलू उद्योग का निर्धारण करने के लिए नहीं लिया जा सकता है।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को अधिकृत कार्रवाही करने के उद्देश्यों से भारत के बीमा शुल्क प्रक्षेप के बाहर माना जायेगा। इस प्रकार की अधिकृत कार्रवाही में उत्पादन, निर्यात, आयात शामिल है।
- ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई के उत्पादन को बाहर रखे जाने के बाद आवेदक उद्योग अब भारत में कुल घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं रहेगा।
- घ. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए इनसेक्टीसाइड्स इण्डिया लिमि. के आंकड़ों और सूचना की जांच करनी चाहिए कि घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से उन्हें बाहर करना जानवृत्तकर भारतीय उद्योग की स्थिति के कार्यनिष्पादन सूचकांकों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए नहीं किया जाता है।
- ड. याचिकाकर्ता, मेघमणि इडस्ट्री लिमि. की विशेष आर्थिक क्षेत्र के संयंत्र को घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए क्योंकि यह मुख्य रूप से निर्यात बाजार की मांग को पूरा करता है जैसा कि प्राधिकारी द्वारा व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन प्रथाओं के मैनुअल में उल्लेख किया गया है और जैसा कि “सोलर सैल्स चाहे उसको एसेम्बल मॉड्यूल अथवा पैनल में किया गया हो अथवा नहीं” के जांच परिणामों में माना गया है।

घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

18. प्रतिकारी शुल्क नियमावली का नियम 2(घ) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाइट वस्तु के नियंत्रकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” एवं का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

19. यह याचिका मैसर्स मेघमणि इडस्ट्रीज लिमि. (एम आई एल) द्वारा दायर की गई है और इसका समर्थन मैसर्स इनसेक्टीसाइड्स (इण्डिया) लिमि. द्वारा किया गया है। इन दो उत्पादकों के अलावा, भारत में संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य ज्ञात उत्पादक नहीं है।

20. यह नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के पास एक इकाई है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस ई जैड) में स्थिति है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के भीतर विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को शामिल करने के संबंध में अथवा अन्य प्रकार से नीचे दिये गये अनुसार नोट करते हैं :

- क. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को नियंत्रित के संवर्धन के लिए और उससे संबंधित अथवा उसके प्रासंगिक मामलों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, विकास और प्रबंधन के लिए प्रावधान करने हेतु बनाया गया था।
- ख. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2(i) में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र का आशय पूरे भारत (समुद्री सीमा और महाद्वीपीय जल सीमा सहित) से है लेकिन इसमें विशेष आर्थिक क्षेत्रों के क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं।

ग. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 2(एम) (ii) के अनुसार निर्यात में “घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से किसी इकाई अथवा विकासकर्ता को वस्तुओं की आपूर्ति करना अथवा सेवाएं उपलब्ध कराना” (विशेष आर्थिक क्षेत्र में) शामिल है।

घ. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 53 में आगे यह प्रावधान है कि -

“(1) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को किसी नियत दिन को और से अधिकृत सामरिक गतिविधियों को करने के उद्देश्यों से भारत के सीमा शुल्क प्रक्षेत्र के बाहर एक प्रक्षेत्र के रूप में माना जायेगा।

(2) एक विशेष आर्थिक क्षेत्र को उस तिथि से जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है, पोर्ट, अंतर्देशीय कंटेनर डिपों, लैंड स्टेशन और लैंड सीमा शुल्क स्टेशन, जैसी भी स्थिति को सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 7 के अंतर्गत माना जायेगा”

बशर्ते की इस धारा के उद्देश्यों से केंद्र सरकार अलग अलग विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग तिथियों को अधिसूचित कर सकती है।

ड. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन इसे स्पष्ट करता है कि यद्यपि विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयां भारत के सम्प्रभुता सम्पन्न प्रक्षेत्र का एक भाग है, अतः उन्हें डी टी ए इकाईयों से अलग रखा जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयां स्थापित करने का मौलिक उद्देश्य निर्यातों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा विशेष आर्थिक क्षेत्र को डी टी ए की परिभाषा से बाहर रखा जाता है।

21. उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता की विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है।

22. डी टी ए की इकाई के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही इसका संबंध संबद्ध वस्तुओं के किसी आयात अथवा निर्यात से है। इसके अलावा प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसके उत्पादन और कुल भारतीय उत्पादन दोनों से याचिकाकर्ता की विशेष आर्थिक क्षेत्र का उत्पादन को बाहर करने के बाद, याचिकाकर्ता का भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, इस जांच के उद्देश्य से, प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 2(ब) के आशय से घरेलू उद्योग है।

23. इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता और समर्थक भारत में संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु का एक मात्र उत्पादक है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता इस नियमावली के नियम 6(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ड. 1. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

24. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. निर्यातकों ने दिनांक 07 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धांतों जो उस समय लागू थी जब उत्तरों को प्रस्तुत किया गया है, का उल्लेख किया है। चूंकि व्यापार सूचना के द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धांत व्याख्यात्मक प्रकृति के हैं अतः उनका पालन निर्यातकों द्वारा उत्तर प्रस्तुत करने में किया जाना चाहिए था।

ख. निर्यातकों ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना को गोपनीय रूप में होने का दावा किया है।

ग. जेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. ने खुली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष निधि के नाम वाली सबिसडी के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। हालांकि, इसने इस तथ्य के बावजूद की यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, गोपनीय के रूप में प्राप्त लाभ के बारे में सूचना का दावा किया है।

घ. अगोपीनय सारांश को उचित रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है और इस कारण से यह कोई सार्थक सूचना देने में असफल है।

ङ. वितरण के माध्यम का भी गोपनीय होने के रूप में दावा किया गया है।

च. इस आरोप में कोई दम नहीं है कि घरेलू उद्योग ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि इसने क्षति से संबंधित सभी मानदंडों की प्रवृत्तियों को उपलब्ध कराया है जो इस मामले के गुणों पर तर्क देने के लिए आयातकों के लिए पर्याप्त है।

छ. घरेलू उद्योग का प्रकटन व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप है।

ज. प्रपत्र क से ठ तक ने कंपनी की लागत और कीमत निर्धारित संबंधी सूचना निहित है जो अत्यधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है। हालांकि, इसके प्रकटन न किये जाने से अन्य पक्षकारों से कोई पक्षपात नहीं होता है।

झ. डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के संबंध में सङ्केतों के बारे में, यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग को इस व्यापार सूचना 07/2018 को प्रकट करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा, इन आंकड़ों को प्राप्त करने के समय घरेलू उद्योग लिखित रूप में यह वचन देता है कि वह इसके बारे में किसी को नहीं बतायेगा अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में इसे नहीं रखेगा।

ञ. यदि हितबद्ध पक्षकार लेनदेन वार डी जी सी आई एंड एस के आंकड़े प्राप्त करना चाहते थे तब वे व्यापार सूचना के संबंध में इसे प्राप्त करने के लिए जांच करने वाले अधिकारी के समक्ष आवश्यक घोषणा प्रस्तुत कर सकते थे।

ट. कुल भारतीय उत्पादन को प्रकट नहीं किया गया है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं के केवल दो उत्पादक हैं और इस प्रकार के उत्पादन को प्रकट करना अन्य उत्पादक के उत्पादन का प्रत्येक उत्पादक को प्रकट करने के बराबर होगा।

ङ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों किया गया अनुरोध

25. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं :

क. घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना 10/2018 के अनुसार अपेक्षित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है :

- (i) याचिकाकर्ताओं का विदेशी उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ घरेलू उत्पादकों के साथ संबंध;
- (ii) भारत ने संबद्ध वस्तुओं के अन्य सभी भारतीय उत्पादकों/ उपभोक्ताओं/ आयातकों के नाम और पते;
- (iii) घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादन की मात्रा और मूल्य। घरेलू उद्योग ने वास्तविक आंकड़ों में इस सूचना को उपलब्ध नहीं कराया है।

ख. याचिकाकर्ता ने नियम 8 और व्यापार सूचना सं. 1/2013 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है क्योंकि खंड VI में याचिकाकर्ता ने सभी प्रश्नों के उत्तर 'संलग्न व्यापार प्रोप्राटरी सूचना' के रूप में दिए हैं। याचिकाकर्ता से यह कहा जाना चाहिए कि यह अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराये अथवा सूचना प्रकट करे।

ग. याचिकाकर्ता निर्यातकों से गोपनीय के रूप में सब्सिडी का आंकलन नहीं कर सकता है।

घ. याचिकाकर्ता ने लेन देन वार डी जी सी आई एंड एस के आयात संबंधी आंकड़ों उपलब्ध नहीं कराये हैं यद्यपि इसने आई टी ए एस आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये हैं।

ङ. आवेदक उद्योग ने नए लागत प्रपत्रों, मात्रा से संबंधित सूचना, उत्पादन का हिस्सा, भारत में मांग के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसने अगोपनीय सारांश भी उपलब्ध नहीं कराया है।

च. प्रपत्र क से ठ को एक पृष्ठ में गोपनीय के रूप में दावा किया गया है। अगोपनीय पाठ को गोपनीय पाठ का सही प्रतिकृति होना और इसने सभी पृष्ठों, प्रपत्रों और अनुबंधों इनके बारे में गोपनीय होने का दावा किया जा रहा है, का उल्लेख होना चाहिए।

छ. पक्षकारों के बचाव के अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस याचिका में उपलब्ध कराये गये महत्वपूर्ण आंकड़ों को सही ढंग से अगोपनीय पाठ में सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

ड. 3. प्रधिकारी द्वारा जांच

26. सूचना की गोपनीयता के संबंध में सब्सिडीरोधी नियमावली के नियम 8 में निम्नलिखित प्रावधान है :

“गोपनीय सूचना। (1) नियम 7 के, उपनियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 का उप नियम (2), नियम 17 का उपनियम (4) और नियम 19 का उपनियम (3) में निहित किन्हीं तथ्यों के बाबजूद, नियम 6 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों अथवा जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर इसके द्वारा ऐसा माना जायेगा और इस प्रकार की किसी सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जायेगा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को यह कह सकते हैं कि वे गोपनीय सूचना के तथ्य को उचित तरीके से समझने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विवरण में उसका अगोपनीय सार प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार की राय में, इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है तब ऐसे पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा इस सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं है अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन का अधिकार देने के लिए इच्छुक नहीं है, तब यह इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकता है।”

27. प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है।

28. घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा संगत और वास्तविक मानी गई सीमा तक गोपनीयता के संबंध में किये गये निवेदनों की जांच प्राधिकारी द्वारा की गई थी और तदनुसार, उसका समाधान किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक हुआ गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस प्रकार की सूचना को गोपनीय और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न किया गया माना गया है। जहां भी संभव हो गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध करायें। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों गोपनीयता के रूप में अपने व्यापार से संबंधित संवेदनशील सूचना का दावा किया है।

च. विविध अनुरोध

च. 1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किये गये हैं :

क. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना जनहित के विपरीत होगा। अनपयुक्त सुरक्षा उपायों के न केवल घरेलू उद्योग को सुरक्षा मिल सकती है बल्कि इसकी दीर्घवधि और मौलिक हित को नुकसान भी पहुंच सकता है। बड़ती हुई कीमतों के कारण डाउनस्ट्रीम उद्योग संकुचित हो जायेगा और समग्र मांग में गिरावट आयेगी; तथा इससे एक अप्रतिस्पर्धी वातावरण बनेगा।

ख. याचिकाकर्ताओं ने जानबूझकर प्राधिकारी को भ्रमित करने और उत्पाद के कार्यक्षेत्र के बारे में संशय पैदा करने के उद्देश्य से संबद्ध वस्तुओं के आयातकों और उपभोक्ताओं के संबंध में सूचना छुपाई है। इससे हितबद्ध पक्षकारों को उत्पाद के कार्यक्षेत्र और घरेलू उद्योग के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अधिकारों को हानि पहुंची है।

ग. गलत सूचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य हितबद्ध पक्षकारों की संख्या को कम करने के लिए था जो इस याचिका में उपलब्ध कराई गई भ्रामक और गलत सूचना का विरोध कर सकते हैं।

घ. बाहर रखे जाने का प्रभाव यह है कि क्रेता घरेलू उद्योग से खरीदों के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नहीं हो पाये हैं जो निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदक उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय संबंधी आंकड़ों का सत्यापन करने के लिए अनुमति दी होती।

ड. इसके अलावा यह अनुरोध किया जाता है कि वास्तविक आयातकों और उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना इस याचिका में उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदक उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आयातकों की सूची संबद्ध वस्तुओं के लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं का है जो वर्तमान में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण नहीं कर रहे हैं। यह एक तथ्य है जो कई कंपनियों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है जो इस उत्पाद से जुड़े हुए हैं क्योंकि अट्राजिन टेक्निकल एक प्रतिबंधित उपयोग वाला कीटनाशक (आर यू पी) है और इसका आयात, निर्माण और बिक्री भी कीटनाशक अधिनियम 1968 के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सी आई बी) द्वारा पंजीकृत और विनियमित किये गये अनुसार कुछ आयातकों/ उपभोक्ताओं/ निर्माताओं तक चिन्हित है। इस कारण से, यह जानना दिलचस्प होगा कि क्यों इन कंपनियों के नाम एक विशिष्ट अभिकथन के साथ प्राधिकारी को उपलब्ध कराये गये थे कि वे इस उत्पाद के आयातक हैं जबकि वे वास्तविक रूप में भारत में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक हैं। यह स्पष्ट है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं/ आयातकों से कम से कम प्रतिरोध के साथ संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है।

च. घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना को गंभीर त्रुटियों, असंगतताओं और सटीक न होने के आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से इस कारण से हुआ है कि विगत हाल में, प्राधिकारी ने लिपिकीय त्रुटियों के लिए भी निर्यातकों से उत्तरों को अस्वीकार किया है।

छ. चूंकि संबद्ध वस्तुओं की विक्री किसी किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं की जा सकती है अतः आवेदक उद्योग यह दावा नहीं कर सकता है कि आयातकों/ उपभोक्ताओं को इनके बारे में जानकारी नहीं है।

ज. बार बार अनुस्मारक दिये जाने के बावजूद, जांच की अवधि के लिए संशोधित याचिका प्राप्त नहीं हुई थी।

झ. यदि भारत ने यू एस ए और अन्य देशों के उदाहरणों को इस तथ्य के बावजूद प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांचों को आरंभ करने पर बल देने के लिए अपनाया है कि चीन अपने आपको बाजार अर्थव्यवस्था के निर्माण में समर्पित करता रहा है; यह दो सरकारों के बीच बातचीत और आर्थिक एवं व्यापार संबंध के व्यापक परिदृश्य पर विचार करते हुए माना जाना चाहिए।

ज. द्विपक्षीय व्यापार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रस्तुत की गई याचिका को स्थाई द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंध के व्यापक परिदृश्य पर विचार करते हुए माना जाना चाहिए।

ट. याचिकाकर्ता ने लेन देन वार आई टी एस आंकड़े और न कि डी जी आई सी एंड एस आंकड़े उपलब्ध कराये हैं।

ठ. वर्तमान सी वी डी कार्रवाइयां न्यायोचित नहीं हैं और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में त्रुटिपूर्ण और भ्रामक सूचना प्रस्तुत की हैं। घरेलू उद्योग के आवेदन में कमियां सुधार न की जाने वाली प्रकृति की है और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है।

ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी यह अनुरोध किया कि इसकी सूचना के अनुसार, डी जी टी आर विचाराधीन उत्पाद की मौजूदा कीमत के 60 प्रतिशत की सीमा तक सी वी डी शुल्क लगाने की सिफारिश कर रहा है, जिसके फलस्वरूप “अट्राजिन सूचीकरण” जो विचाराधीन उत्पाद का डाउनस्ट्रीम उत्पाद है का 15-20 प्रतिशत तक कीमत में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से भारत के किसानों की स्थिति और आगे बदतर हो जायेगी जो पहले से ही भारी क्रृष्ण और अन्य वित्तीय मुद्दों के कारण परेशानी में हैं। इस संदर्भ में, यह माननीय प्रधानमंत्री के किसानों की आय को दुगुना करने की कल्पना के विरुद्ध होगा।

ढ. घरेलू उत्पादकों को चीन से आयात किये गये प्रमुख कच्चे माल के सब्सिडीयुक्त आयातों से लाभ मिल रहा है। इस कारण से यह मानते हुए कि चीन में सब्सिडी है, का घरेलू उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें इस प्रकार की सब्सिडी से भी लाभ मिल रहा है।

ण. यह दुखद है कि घरेलू उत्पादकों ने इस तथ्य के बावजूद याचिका में किसी भी किसान संघ का नाम नहीं लिया है कि यह एक कानूनी अपेक्षा है। यह स्पष्ट है कि किसान संघों को शामिल नहीं करना स्पष्ट रूप से इससे जुड़े पक्षकारों से कोई सूचना प्राप्त किये विना इन शुल्कों को प्राप्त करने का प्रयास है।

च. 2. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

30. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के उत्तर में घरेलू उद्योग का अनुरोध नीचे दिये अनुसार है :

क. इस तर्क के संबंध में की आयातकों और उपभोक्ताओं के ब्यौरों को छुपाया गया है, यह अनुरोध किया गया था कि घरेलू उद्योग ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों में यथा सूचीबद्ध आयातकों की सूची दी है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराये गये आयातों की सूची वह है जो संबद्ध वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं। अट्राजिन निर्माण का कोई उत्पादक निश्चित रूप से अट्राजिन टेक्निकल का एक उपभोक्ता अथवा आयातक होगा।

ग. हितबद्ध पक्षकारों का भाग लेने के अधिकारों को कम करने के संबंध में यह अनुरोध किया गया था कि जैसे ही जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होगी तभी आयातकों और उपभोक्ताओं के बारे में यह माना जायेगा कि उन्हें इसकी सूचना मिल गई है।

घ. जब निर्यातक कुछ अधिकृत निर्यातकों जिन्हें जांच शुरूआत की सूचना प्राप्त हुई, तक सीमित हों; तब वे निश्चित रूप से इसके बारे में भारत में अपने आयातकों को सूचित किया होगा जो बाद में अपने क्रेताओं अर्थात् भारत में उपभोक्ताओं को सूचित किया होगा। वास्तव में, इस जांच में भाग लेने के लिए उत्तर देने वाले आयातकों की क्षमता भी किसी भी प्रकार से इस याचिका में सूचीबद्ध न किये जाने के कारण वाधित नहीं हुई है।

ड. जनहित के तर्कों के संबंध में, यह अनुरोध किया गया था कि यह आयातकों के लिए नहीं है कि वे इस पर टिप्पणी करें जब संबद्ध देश से सस्ते आयातों के होने के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। इस अलावा, यह शुल्क भारतीय और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिए बाजार में समान अवसर सुनिश्चित करेगा और वह संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता को प्रतिवंधित नहीं करेगा।

च. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विधि मुद्दों के संबंध में दिये गये विभिन्न अनुरोधों और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गये अनुरोधों की जांच और उसका समाधान नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

क. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच आरंभ करने की मांग करते हुए निर्धारित प्रोफोर्मा और प्रपत्रों के अनुसार एक विधिवत प्रमाणित की गई याचिका दायर की थी। इस याचिका की पर्याप्तता का विश्लेषण जांच शुरूआत के चरण किया गया था और यह जांच उचित विचार विमर्श के बाद आरंभ की गई थी।

ख. इस अनुरोध के संबंध में की संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातकों की पहचान इस याचिका में नहीं की गई थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। इस याचिका में कुछ आयातकों के नाम को शामिल न किये जाने के कारण किसी पक्षपात का दावा नहीं किया जा सकता।

ग. प्राधिकारी द्वारा विचार की गई जांच की अवधि के लिए अध्यतीत सूचना की मांग करते हुए कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोधों के संबंध में, इस प्रकार की अध्यतीत सूचना घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उसे मौखिक सुनवाई के पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया गया था और उसे साथ ही साथ सार्वजनिक फाइल में रखा गया था।

घ. इसके अलावा प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने इस याचिका में डी जी सी आई एंड एस के अनुसार लेन देन वार आयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराये थे और यह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये दावे के अनुसार गौण स्रोतों के अनुसार नहीं था।

ड. जहां तक जनहित का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आमतौर पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने का उद्देश्य सबिसडी दिए जाने की अनुचित व्यापार प्रशासनों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से संबद्ध देश से आयातों में किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से यह उचित कीमतों पर उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं ढालेगा। प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाये जाने से सबिसडी दिये जाने के कारण प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जायेगा, घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जायेगा और उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाये रखने में मदद मिलेगी।

च. सबिसडी का मार्जिन और क्षति मार्जिन जिसे प्राधिकारी द्वारा स्थापित किया गया है, पर विचार करते हुए, सी वी डी शुल्क के निचले क्रम के उपभोक्ताओं पर प्रभाव, यदि कोई हो, न्यूनतम होगा।

छ. वर्तमान जांच में प्राधिकारी का अधिकार विचारधीन उत्पाद (अर्थात् अट्राजिन टेक्निकल) के लिए कथित सबिसडी मात्र, और न कि विचाराधीन उत्पाद के कच्चे माल की सबिसडी की जांच करना है।

ज. इस अनुरोध के संबंध में कि किसान संघ की पहचान इस याचिका में नहीं की गई थी, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस कारण से इस याचिका में किसान संघ का नाम शामिल न किये जाने के कारण किसी पक्षपात का दावा नहीं किया जा सकता है।

सबिसडी और मार्जिन का निर्धारण

32. घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई याचिका में चीन ने प्रतिसंतुलनकारी सबिसडी के होने का आरोप लगाया गया। घरेलू उद्योग ने यह दर्शाते हुए कि किस प्रकार से इस याचिका में पहचान की गई, प्रत्येक योजना की जांच की जानी अपेक्षित थी अनुरोध प्रस्तुत किया।

33. चीन की सरकार (जी ओ सी) को विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था, जो नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2018 को आयोजित की गई थी और इसमें चीन की सरकार (जी ओ सी) के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। उक्त विचार विमर्श में, जी ओ सी ने नीचे दिये गये अनुसार तर्क दिये :

क. अधिमान्य ऋण/ उधार के रूप में कार्यक्रम और वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रावधान के रूप में कार्यक्रम राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों के वाणिज्यिक क्रियाकलापों का संदर्भ लेते हैं परंतु इन उपक्रमों को सार्वजनिक निकायों के रूप में नहीं माना जा सकता।

ख. विदेशी निवेश द्वारा प्राप्त लाभों का फिर से निवेश करने के लिए आयकर वापसी के रूप में कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था।

ग. पूर्वोत्तर क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अधिमान्य नीति अब लागू नहीं है।

घ. प्रसिद्ध ब्रांड कार्यक्रम अब लागू नहीं है।

ड. चीन के कुछ कानूनों, विनियमों और नीतियों का उपयोग आरोप लगाने के साक्ष्य के रूप में किया गया है समाप्त हो गये हैं अथवा मौजूद नहीं हैं।

34. प्राधिकारी ने इस याचिका में कथित कार्यक्रमों की सूची का विश्लेषण किया। याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख करते हुए अपने दिनांक 10.08.2018 के पत्र के माध्यम से कथित कार्यक्रमों की सूची से निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों को वापस ले लिया कि यह इन योजनाओं के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य जुटाने में सक्षम नहीं रहे हैं।

- (i) कार्यक्रम सं. 17 : स्वच्छ उत्पादन परियोजना सब्सिडी
- (ii) कार्यक्रम सं. 20 : बीजिंग प्रांत को विभिन्न अनुदान दिये गये
 - (क) कार्यक्रम सं. 20(क) : बीजिंग सरकारों द्वारा विकास को बनाये रखने के लिए अवार्ड
 - (ख) कार्यक्रम सं. 20(ख) : बीजिंग प्रौद्योगिकी व्यापार प्रोत्साहन केंद्र द्वारा अवार्ड
- (iii) कार्यक्रम सं. 59 : परिलक्ष्य से कम के लिए पानी का प्रावधान

35. चीन की सरकार के साथ जांच आरंभ करने से पूर्व विचार विमर्श के दौरान किये गये अनुरोधों को देखते हुए और इस याचिका में कथित योजनाओं की जांच तथा याचिकाकर्ता के अनुरोध की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने 4 और कार्यक्रमों की पहचान की जिन्हें वर्तमान जांच के लिए जांच किये जाने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि इन कार्यक्रमों को या तो वापस ले लिया गया था और/ अथवा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कथित लाभ जांच की अवधि के पूर्व ही समाप्त हो गये थे अथवा याचिकाकर्ता ने इन कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये हैं। इस कारण से कोई भी जांच इन निम्नलिखित 4 कार्यक्रमों के संबंध में आरंभ नहीं की गई थी :

- (i) कार्यक्रम सं. 31 : आयात किये गये प्रौद्योगिकियों और उपकरण के लिए प्रशुल्क एवं मूल्यवर्धित कर से छूट
- (ii) कार्यक्रम सं. 32 : चीन में बनाये गये उपकरण की खरीद पर घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए मूल्यवर्धित कर की वापसी
- (iii) कार्यक्रम सं. 33 : केंद्रीय क्षेत्रों के लिए मूल्यवर्धित कर में छूट और कटौती
- (iv) कार्यक्रम सं. 47 : सरकार की उधार संबंधी नीति

जांच के अधीन सब्सिडी योजनाएं

36. प्राधिकारी ने निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए जांच आरंभ की जिसने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को संभावित रूप से प्रतिसंतुलनकारणीय लाभ मिला होगा :

- I. अनुदान के रूप में अभिज्ञात किए गए कार्यक्रम
 1. कार्यक्रम सं. 1 : राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी नवीकरण परियोजना निधि
 2. कार्यक्रम सं. 2 : प्रसिद्ध ब्राण्ड के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध ब्राण्ड कार्यक्रम / प्रोत्साहन निधि

3. कार्यक्रम सं. 3 : पाटनरोधी/ सब्सिडीरोधी जांचों के लिए अनुदान
4. कार्यक्रम सं. 4 : अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) सहायता अनुदान
5. कार्यक्रम सं. 5 : निर्यात सहायता अनुदान
6. कार्यक्रम सं. 6 : शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिए अनुदान
7. कार्यक्रम सं. 7 : राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय अभिनवता के लिए प्रांतीय निधि के माध्यम से दिया गया अनुदान
8. कार्यक्रम सं. 8 : निर्यात कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार निधि
9. कार्यक्रम सं. 9 : परियोजना निधि भत्ता
10. कार्यक्रम सं. 10 : ऊर्जा बचत प्रौद्योगिकी सुधार के लिए विशेष निधि
11. कार्यक्रम सं. 11 : प्रौद्योगिकीय लघु और मध्यम आकार के उपक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी अभिनवता को सहयोग देने के लिए निधियां/ लघु और मध्यम आकार के उपक्रम को सहायता निधियां
12. कार्यक्रम सं. 12 : प्रमुख उद्योगों और अभिनवता प्रौद्योगिकियों को संवर्धन करने के लिए राज्य विशेष निधि
13. कार्यक्रम सं. 13 : उपक्रम विकास निधि
14. कार्यक्रम सं. 14 : स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी निधि
15. कार्यक्रम सं. 15 : उच्च और नये प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अनुदान
16. कार्यक्रम सं. 16 : विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि
17. कार्यक्रम सं. 18 : जियांगसू प्रांत को विभिन्न अनुदान दिये गये
 - क. जियांगसू प्रांत वित्त सहयोग निधि
 - ख. पर्यावरण संरक्षण अवार्ड (जियांगसू)
 - ग. जियांगसू शहर औद्योगिकी अर्थव्यवस्था कार्य निष्पादन अवार्ड
 - घ. चांगझाउ क्यूअन जिला पर्यावरणीय संरक्षण निधि
 - ड. चांगझाउ प्रौद्योगिकी योजना
 - च. झूयी देश के सरकार द्वारा सहयोग निधि उपलब्ध कराई गई
 - छ. परियोजना अवसंरचना के निर्माण के लिए उपक्रम प्रौद्योगिकी केंद्र/ सहायता निधिया
18. कार्यक्रम सं. 19 : गुआड़ॉग प्रांत को विभिन्न निधियां उपलब्ध कराई गई
 - क. गुआड़ॉग प्रांत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से व्यापार का विकास करने के लिए विशेष निधि
 - ख. गुआड़ॉग – हॉग कॉग प्रौद्योगिकी सहयोग वित्तपोषण कार्यक्रम
 - ग. गुआड़ॉग सहायता निधि
 - घ. गुआड़ॉग सरकारों द्वारा महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विशेष निधि
 - ड. गुआड़ॉग विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यूरो परियोजना निधि की प्रांतीय सरकार

च. गुआड़ॉग सरकारों द्वारा एस एम ई के लिए प्रांतीय क्रृष्ण सूत विशेष निधि

छ. गुआड़ॉग सरकारों द्वारा “समकालीन उद्योगों 500 मजबूत उपक्रम” की विभिन्न परियोजनाओं के लिए विशेष सहायता निधि

ज. गुआड़ॉग सरकारों द्वारा नीतिगत तौर पर उभरने वाले उद्योगों की सहायता के लिए निधि

झ. गुआड़ॉग सरकारों द्वारा नियांत्रित क्रृष्ण बीमा के लिए विशेष निधि

ज. गुआड़ॉग प्रांत का पेटेंट अवार्ड

ट. गुआज्ज्ञात स्थानीय सरकारों से विकास के लिए सहयोग निधि

19. कार्यक्रम सं. 21 : अनहुई प्रांत को विभिन्न अनुदान दिया गया

क. हॉगज्जोज प्रीफेक्चर और (अनहुई प्रांत) के शहर से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आई पी ओ) अनुदान

II. कर प्रोत्साहन और मूल्यवर्धित कर के छूट के रूप में अभिज्ञात किए गए कार्यक्रम

20. कार्यक्रम सं. 22 : निर्यातों पर नियांत्रित कर छूट/ कर वापसी

21. कार्यक्रम सं. 23 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां

22. कार्यक्रम सं. 24 : एफ आई ई के अनुसंधान और विकास के लिए अधिमान्य कर नीतियां

23. कार्यक्रम सं. 25 : एफ आई ई द्वारा अनुसंधान और विकास के लिए कर ऑफसेट

24. कार्यक्रम सं. 26 : घरेलू रूप से उत्पादन की गई और निर्माण किये गये उत्पादन उपक्रम की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट

25. कार्यक्रम सं. 27 : उन कंपनियों के लिए जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है, अधिमान्य कर नीतियों/ आयकर कटौती

26. कार्यक्रम सं. 28 : व्यापक संसाधन उपयोग में लगे हुए उपक्रमों के लिए आयकर में रियायत (विशेष कच्चा माल)

27. कार्यक्रम सं. 29 : विशेष उपकरण की खरीद के संबंध में कर क्रेडिट

28. कार्यक्रम सं. 30 : चीन में निर्मित उपकरण की खरीद करने वाली घरेलू स्तर पर स्वामित्व वाली कंपनियों के लिए आयकर क्रेडिट

29. कार्यक्रम सं. 34 : कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए कार्य करने हेतु निर्धारित उत्पादक एफ आई ई के लिए घटाया गया कर दर

30. कार्यक्रम सं. 35 : विदेश में निवेश करने वाले नियांत्रित उपक्रमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

31. कार्यक्रम सं. 36 : एफ आई ई जो प्रौद्योगिकी गहन और ज्ञान गहन है, के लिए अधिमान्य कर नीतियां

32. कार्यक्रम सं. 37 : एफ आई ई और विदेशी उपक्रमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिनकी चीन में स्थापना अथवा स्थान है और जो घरेलू स्तर पर उत्पादन किये गये उपकरणों की खरीद करने के लिए व्यापार क्रियाकलाप अथवा उत्पादन में लगे हुए हैं।

33. कार्यक्रम सं. 38 : विदेशी निवेशकों द्वारा एफ आई ई से प्राप्त लाभों का फिर से निवेश करने के लिए आयकर वापसी

34. कार्यक्रम सं. 39 : उन्नत प्रौद्योगिकी एफ आई ई के लिए आयकर में कटौती
35. कार्यक्रम सं. 40 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों (जिसमें शंघाई पुड़ौंग क्षेत्र शामिल नहीं है) में स्थापित विदेशी निवेश (एफ आई ई) के साथ उपक्रमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
36. कार्यक्रम सं. 41 : तटीय आर्थिक खुले क्षेत्रों में और आर्थिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास क्षेत्रों में स्थापित एफ आई ई के लिए अधिमान्य कर नीतियां
37. कार्यक्रम सं. 42 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्य निर्धारित क्षेत्रों में स्थानीय आयकर छूट और/ अथवा कटौती
38. कार्यक्रम सं. 43 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्य निर्धारित क्षेत्रों में कारपोरेट आयकर छूट और/ अथवा कटौती
39. कार्यक्रम सं. 44 : विशेष आर्थिक क्षेत्रों और अन्य निर्धारित क्षेत्रों में आयात की गई सामग्री और उपकरण पर प्रशुल्क और मूल्यवर्धित कर (वैट) से छूट
40. कार्यक्रम सं. 45 : पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपक्रमों के लिए अधिमान्य आयकर नीति
41. कार्यक्रम सं. 46 : केंद्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए कर में रियायत

III. अधिमान्य क्रृण और उधार के रूप में अभिज्ञात किये गये कार्यक्रम

42. कार्यक्रम सं. 48 : एस ओ ई को अधिमान्य क्रृण
43. कार्यक्रम सं. 49 : निर्यात उन्मुख उपक्रमों के लिए छूट प्राप्त क्रृण और निर्यात क्रृण व्याज सब्सिडी

IV. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट के रूप में अभिज्ञात किये गये कार्यक्रम

44. कार्यक्रम सं. 50 : निर्यात विक्रेता का क्रेडिट
45. कार्यक्रम सं. 51 : निर्यात क्रेता का क्रेडिट
46. कार्यक्रम सं. 52 : राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों से अन्य निर्यात वित्तपोषण
47. कार्यक्रम सं. 53 : निर्यात क्रेडिट सीमा सब्सिडी
48. कार्यक्रम सं. 54: निर्यात क्रेडिट गारंटी

V. इक्किटी के रूप में अभिज्ञात किये गये कार्यक्रम

49. कार्यक्रम सं. 55 : इक्किटी डालना
50. कार्यक्रम सं. 56 : भुगतान न किया गया लाभांश
51. कार्यक्रम सं. 57 : योग्य स्थानिक उपक्रमों के बीच लाभांश में छूट

VI. वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अभिज्ञात किये गये कार्यक्रम

52. कार्यक्रम सं. 58 : समुचित परिलिंग्धि से कम के लिए बिजली का प्रावधान
53. कार्यक्रम सं. 60 : औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि के उपयोग का अधिकार
54. कार्यक्रम सं. 61 : एस ओ ई के लिए भूमि के उपयोग का आधार

55. कार्यक्रम सं. 62 : एफ आई ई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

37. जांच शुरूआत के पश्चात, चीन की सरकार और चीन जन. गण. से अट्राजिन टेक्निकल के उत्पादकों/ निर्यातकों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें और उन्हें इस प्रकार की सब्सिडी, यदि कोई हो के मौजूद होने और उसकी मात्रा का उपयुक्त निर्धारण करने के लिए कथित सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था।

38. चीन की सरकार ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है :

- मैसर्स झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि.
- मैसर्स अनहुई झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि.
- मैसर्स सियांगशुई झोंगशन बायोसाइंस कं. लिमि.

39. उपर्युक्त तीन उत्पादकों/ निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली के उत्तरों का चीन में डी जी टी आर के एक सत्यापन दल द्वारा मौके पर सत्यापन किया गया था और प्राधिकारी यह मानते हैं कि उसे निम्नलिखित कारणों से वर्तमान उद्देश्यों के लिए और अलग अलग सी वी डी मार्जिन का निर्धारण करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अपनाया नहीं जा सकता है :

क. जांच की अवधि के दौरान मैसर्स झेजियांग झोंगशन द्वारा विचाराधीन उत्पाद के लिए जारी किये गये क्रमरहित नमूना निर्यात दस्तावेजों का मौके पर सत्यापन किये जाने की प्रक्रिया के दौरान, यह देखा गया था कि दो बीजकों जिस पर एक ही बीजक संख्या थी और उसमें उल्लिखित सामग्री अलग अलग थी (जैसे दर, तिथि) आदि कंपनी द्वारा इसके लेखांकन सॉफ्टवेयर से जारी किया गया है। बीजकों के निम्नलिखित चार ऐसे सेट प्राप्त किये गये थे :

- हॉग कॉग को निर्यात :** दो बीजक जिसका बीजक सं. *** एक ही है और एक तिथि है *** एक ही आदेश संख्या और मात्रा है, के बारे में यह पाया गया कि इनकी दो अलग अलग दरें अर्थात् *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. और *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. है।
- भारत को निर्यात (मैसर्स ***):** दो बीजक जिसका एक ही बीजक संख्या *** और एक ही मात्रा, आदेश संख्या और दर है, के बारे में यह पाया गया कि इनके दो अलग अलग तिथियां अर्थात् दिनांक *** और *** हैं।
- ब्राजील का इजरायल (मैसर्स ***):** दो बीजक जिसकी बीजक संख्या एक ही है और एक ही मात्रा और आदेश संख्या है, के बारे में यह पाया गया कि उसकी दो अलग अलग तिथियां अर्थात् *** और *** अर्थात् दो अलग अलग दरें अर्थात् *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. और *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. है।
- इजरायल को निर्यात (मैसर्स ***):** दो बीजक जिसकी बीजक संख्या एक ही है और एक ही मात्रा और आदेश संख्या है, के बारे में यह पाया गया कि उसकी दो अलग अलग तिथियां अर्थात् *** और *** अर्थात् दो अलग अलग दरें अर्थात् *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. और *** यू एस डालर प्रति कि. ग्रा. है।

ख. इसके अलावा, सत्यापन दल ने ऐसे वीजकों के समान सेट के साथ इस प्रकार के कुच्छ और उदाहरण पाये हैं और कंपनी से उसकी प्रतियां मांगी हैं लेकिन कंपनी ने उसकी प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई। कंपनी से यह कहा गया था कि वे इस विसंगति को स्पष्ट करें। कंपनी द्वारा अपने व्यापार और लेखांकन रिकार्डों में इस प्रकार की बड़ी विसंगति के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

ग. अतः, सत्यापन दल के उपर्युक्त टिप्पणियों के आलोक में, इन कंपनियों की इलेक्ट्रॉनिकल सॉफ्टवेयर और लेखा बुक पर लेन देन का रिकार्ड करने के संबंध में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता है। तदनुसार प्राधिकारी यह मानते हैं कि इन विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर को स्वीकार नहीं किया जाये।

40. चीन के किसी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

ज. 1. कथित सब्सिडी कार्यक्रमों का सामान्य सिंहावलोकन

घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

41. इस याचिका में वर्तमान जांचों की प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं।

- i. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण. की सरकार ("जी ओ सी") संबद्ध वस्तुओं के अपने उत्पादकों/निर्यातकों को निपेंथित और कार्रवाई योग्य सब्सिडी दे रहा है और विधायन एवं नीतिगत दस्तावेजों के संबंध में इस प्रकार की सब्सिडी योजनाओं के होने का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य दिया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग ने ए एस सी एम और भारतीय नियमावली के आशय से चीन जन. गण. में कुच्छ संख्या में प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी योजनाएं के मौजूद होने की पहचान की और यह तर्क दिया है कि चीन जन. गण. ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को इस प्रकार की सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है।
- ii. याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को कार्रवाई योग्य सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। चीन की सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को चालू रखा है। याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में चीन के संगत कानूनों और विनियमों, विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्टें, मीडिया स्रोतों, सरकारी रिपोर्टें, स्वतंत्र रिपोर्टें और अध्ययनों, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच विश्लेषण और अन्य प्राधिकारियों के निष्कर्षों जैसे दस्तावेजों पर विचार किया है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई है।
- iii. चीन की सरकार और चीन जन. गण. में अन्य सार्वजनिक निकायों के कार्यक्रम में निम्नलिखित कारणों से सब्सिडी होती है :

 - क. सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान किया जाता है जहां सरकारी प्रथा में निधियों का सीधा अंतरण (अर्थात् अनुदान, ऋण और इक्रीटी डालना) शामिल है, सरकारी राजस्व जो अन्य प्रकार से देय है परंतु उसका त्वाग कर दिया गया है अथवा उसका संग्रहण नहीं किया गया है (अर्थात् कर क्रेडिट जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन), सरकार सामान्य अवसंरचना को छोड़कर वस्तुओं अथवा सेवाएं उपलब्ध कराती है या वस्तुओं को खरीदती है।
 - ख. विचाराधीन उत्पाद के चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को लाभ दिया जाता है; और
 - ग. यह कार्यक्रम भारतीय नियमावली और ए एस सी एम के आशय से विशिष्ट है।

- iv. चीन के संगत कानून एवं विनियम, डब्ल्यू टी ओ की रिपोर्ट, विभिन्न सरकारी रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट और स्वतंत्र अध्ययन एवं विश्लेषण, अपने सब्सिडीरोधी जांचों में अन्य जांच एजेंसियों के जांच परिणाम स्पष्ट रूप से चीन जन. गण. में प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी कार्यक्रम के मौजूद होने का पर्याप्त साक्ष्य है। इन

साध्यों को सभी हितबद्ध पक्षकारों जिसमें जी ओ सी और चीन जन. गण. में ज्ञात उत्पादक और निर्यातिक शामिल हैं, को याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

v. इस जांच के उद्देश्य से, “चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार” में सरकार के सभी स्तर अर्थात् संघीय, केंद्रीय, 27 प्रांतीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय सरकार जैसे नगर अथवा शहर अथवा टाउनशिप की सरकारें, शामिल हैं। ग्राम अथवा स्थानीय विधायिका, प्रशासनिक अथवा न्यायिक एजेंसियों/ निकाय और राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रम जो चीन की सकरार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण अथवा प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं जो ए एस सी एम में यथापरिभाषित शब्दावली के आधिर से “सार्वजनिक निकाय” के रूप में कार्य करते हैं।

vi. इस याचिका के अनुसार, संबद्ध वस्तुओं के चीन के उत्पादकों/ निर्यातिकों को सरकारों के विभिन्न स्तरों के निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी प्राप्त हुई है और उनका वर्गीकरण 6 व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत किया गया है। इन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत विभिन्न कार्यक्रमों की सूची नीचे दी गई है :

- क. अनुदान
- ख. कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि
- ग. अधिमान्य ऋण और उधार
- घ. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट
- ड. इक्विटी डालना
- च. वस्तु और सेवा का प्रावधान

vii. चीन की सरकार ने इन सब्सिडी कार्यक्रामों के संबंध में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और न तो कोई सार्थक सूचना उपलब्ध कराई है। चीन की सरकार द्वारा उत्तर न दिये जाने पर इन योजनाओं के बारे में कार्रवाई पर उत्तर देने वाले निर्यातिकों द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

viii. इन निर्यातिकों ने कथित योजनाओं के बारे में कार्रवाई किये जाने का विरोध नहीं किया है। उत्तर देने वाले निर्यातिकों ने कथित योजनाओं से प्राप्त किये गये लाभों के संबंध में किसी विवरण का उल्लेख नहीं किया है। इस कारण से चीन की सरकार द्वारा उत्तर न दिये जाने की स्थिति में इन योजनाओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है और उसका अनुमान नहीं लगाया जायेगा।

ix. उत्तर देने वाले निर्यातिकों द्वारा दायर की गई प्रश्नावली का उत्तर इस निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के प्रपत्र के अनुरूप नहीं है। उत्तर देने वाले निर्यातिकों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है और प्रश्नावली का पूरा जवाब प्रस्तुत किया है।

x. निम्नलिखित सब्सिडी कार्यक्रमों में, निर्यातिकों ने कथित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है।

क्रम सं.	उत्पादक/ निर्यातिक/ व्यापारी	49 योजनाओं में से सब्सिडी उत्तर
1.	ज्ञेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि.	7 अनुदानों के लिए लाभ और एक कर प्रोत्साहन राशि स्वीकार की (पी-6,7,9,12,13,16,23,27)
2.	अनहुई झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि.	पी-5,14,16,58 के लिए लाभ स्वीकार किया
3.	सियांगशु ज्ञिगशन बायोसाइंस कं. लिमि.	केवल एक कर प्रोत्साहन राशि के लिए लाभ स्वीकार किया (अर्थात् कर प्रोत्साहन राशि और मूल्यवर्धित कर के छूट के रूप में घाटे को आगे ले जाना

xii. सरकार के प्रश्नावली के उत्तर न दिये जाने और उत्तर देने वाले उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली के उत्तर का समग्र रूप में अपूर्ण और अपर्याप्त होने के आलोक में प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस जांच में चीन की सरकार और उत्तर देने वाले उत्पादकों – निर्यातकों दोनों को असहयोगी के रूप में माने और तदनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करें।

xiii. निर्यातकों द्वारा दावा किये गये अत्यधिक गोपनीयता के कारण, घरेलू उद्योग निर्यातिक विशिष्ट सब्सिडी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने में सक्षम नहीं है। हालांकि सब्सिडी का मार्जिन की मात्रा का निर्धारण भारत द्वारा पूर्व में की गई सी वी डी जांचों और/ अथवा अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों द्वारा की गई जांचों के आधार किया गया है।

xiv. विश्व व्यापार संगठन का यह न्यायिक तर्क है जो यह सुझाव देता है कि साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा में किसी जांच के आगे बढ़ने पर सुधार होता है और साक्ष्य जो इस याचिका में उपलब्ध थे और जिसे बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा विभिन्न चरणों में प्रस्तुत किया गया और जो अब निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास निर्धारण के लिए उपलब्ध है, की गुणवत्ता और मात्रा में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

xv. इस याचिका में कानूनी आधार, योजना की प्रकृति, वित्तीय अंशदान और विशिष्टता, उपक्रमों जो पात्र हैं और जिन्हें विशेष योजना के अंतर्गत लाभ मिला होगा, यह दर्शाते हुए अन्य जांच करने वाले प्राधिकारियों का निर्णय कि ये योजनाएं वास्तव में चल रही हैं और उनका निर्धारण तय किये गये सब्सिडी मार्जिन के साथ प्रतिसंतुलनकारणीय के रूप में है और किसी अन्य वेब अनुसंधान के रूप में साक्ष्य निहित है। इन जांचों की प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया अतिरिक्त साक्ष्य इन योजनाओं के मौजूद होने और इसकी प्रतिसंतुलनकारणीयता को सिद्ध करता है।

xvi. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा लाभ प्राप्त करने के संबंध में सूचना के बारे में, याचिकाकर्ता द्वारा पहचान की गई विभिन्न योजनाओं को (क) उपक्रम विशिष्ट कार्यक्रम, (ख) सेक्टर विशिष्ट कार्यक्रम और (ग) क्षेत्रीय विशिष्ट कार्यक्रम की श्रेणियों में रखा जा सकता है।

xvii. ऐसा कोई नियम है जो यह कहता हो कि सब्सिडीरोधी शुल्क तभी लगाया जाये जब लगाये जाने के समय सब्सिडी हो। यदि जांच की अवधि के दौरान सब्सिडी के मौजूद होने अथवा उसके प्राप्त किये जाने को स्थापित किया जायेगा तब प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जा सकता है चाहे इस प्रकार की सब्सिडी मौजूद हो अथवा न हो या प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने के समय इसका लाभ उठाया गया हो अथवा नहीं।

xviii. स्थाई परिसंपत्तियों के संबंध में सब्सिडी के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि सब्सिडी लगाये जाने के समय मौजूद होना चाहिए। पूर्व के वर्षों में प्राप्त किये गये लाभ के संबंध में जांच की अवधि में शेष लाभ हो सकता है।

xix. चीन के अलग अलग उत्पादकों द्वारा लाभ प्राप्त करने का साक्ष्य देने के संबंध में, घरेलू उद्योग अलग अलग उत्पादकों/ निर्यातकों द्वारा लाभ की प्राप्ति को दर्शाते हुए साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है। घरेलू उद्योग ने इस कार्यक्रम को या तो विचाराधीन उत्पाद अथवा उत्पादन में निहित उपक्रम अथवा उस क्षेत्र में जहां निर्यातिक स्थित हैं से जोड़कर पर्याप्त साक्ष्य किये हैं और यह दर्शाया है कि संबद्ध उत्पादक इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं :

क. कथित सब्सिडी की प्रकृति और उसकी मौजूदगी के संबंध में इस याचिका में पर्याप्त साक्ष्य न होने के संबंध में, हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया है कि सभी कथित सब्सिडी योजनाओं के बारे में याचिकाकर्ता तीन कारकों के जिसमें क्षति संतुलनकारणीय सब्सिडी के होने को सिद्ध नहीं किया जा सका नामतः

- (i) सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान;
- (ii) लाभ; और
- (iii) विशिष्टता

ख. प्राधिकारी को (क) क्या इसमें सब्सिडी दिये जाने के संबंध में साक्ष्य की समुचितता और सटीकता का आकलन किया है; तथा (ख) यह आधार जिस पर यह मानना है कि इस याचिका में कथित प्रत्येक सब्सिडी के लिए समुचित और सटीक सूचना शामिल है, को न्यायोचित ठहराना चाहिए।

ग. इन याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान किये गये कार्यक्रमों में से किसी भी कार्यक्रम की पुष्टि इन तथ्यों और आंकड़ों से नहीं की गई है जो इस याचिका में सूचीबद्ध उत्पादक/ निर्यातिक को लाभ पहुंचा रहे हैं। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने स्वयं इस याचिका में मान लिया है कि उनके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि इस उत्पाद से प्रत्येक उत्पादक के द्वारा सब्सिडी प्राप्त की गई है।

घ. जब याचिकाकर्ता सब्सिडी के प्रभावों का आकलन करने में सक्षम नहीं हों तब प्राधिकारी जांच शुरूआत के समय इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते थे कि सब्सिडी का मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है।

इ. वे याचिकाकर्ता निर्यातिक थे गोपनीय के रूप में सब्सिडी का आकलन नहीं कर सकते हैं।

च. संबंधित कंपनियां जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन, विपणन अथवा वितरण में शामिल नहीं हैं और इस कारण से यह आवश्यक नहीं है कि वे कंपनियां प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें।

छ. इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई सभी सब्सिडी को निश्चित रूप से अपने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के नोट में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के लिए यह सार्थक नहीं है कि वे रिपोर्ट न की गई सब्सिडी की खोज करें क्योंकि उन्होंने प्रश्नावली के उत्तर में जिनमें से सभी सब्सिडी को रिपोर्ट किया है। अतः इन कंपनियों के लिए किसी सब्सिडी को छुपाना संभव नहीं है।

ज. चीन की सरकार द्वारा उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से निर्यातिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर और अलग सी वी डी मार्जिन की मांग करने के लिए उनके अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्राधिकारी द्वारा सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

43. चीन की सरकार ने वर्तमान जांचों में प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। इस कारण से प्राधिकारी ने भाग लेने वाले विदेशी उत्पादकों/ निर्यातिकों की प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध कराई गई सूचना, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों और उपलब्ध अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की है।

44. याचिकाकर्ताओं द्वारा पहचान किये गये 55 सब्सिडी कार्यक्रमों में से, चीन ने विचाराधीन उत्पाद के उत्तर देने वाले उत्पादकों/ निर्यातिकों जिनका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा मौके पर किया गया है, ने निम्नलिखित योजनाओं के लाभ को प्राप्त करना स्वीकार किया है—

क. मैसर्स झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. ने निम्नलिखित योजनाओं/ कार्यक्रमों के अंतर्गत यह लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है—

क्र. सं.	पी सं.	अट्राजिन में परियोजना का नाम	झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि.
1	पी-6	शेररों के सूचियन के लिए अनुदान	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरक प्रोत्साहन निधि
2	पी-7	राजकोषीय और प्रौद्योगिकीय अभिनवता के लिए प्रांतीय नीति के माध्यम से किया गया अनुदान	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – अभिनवता प्रणाली प्रायोगिक देश के लिए निर्माण निधि प्रांतीय औद्योगिक और आई टी आधारित विकास के लिए विशेष वित्तीय निधि
3	पी-9	परियोजना निधि भत्ता	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – “आसूचना सुरक्षा उत्पाद पर्यवेक्षण” उपक्रम के लिए विशेष प्रोत्साहन राशि
4	पी-12	प्रमुख उद्योगों और अभिनवता प्रौद्योगिकियों का संवर्धन करने के लिए राज्य विशेष निधि	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – मजबूत औद्योगिक देश बनाने के लिए विशेष वित्तीय प्रोत्साहन निधि
5	पी-13	उपक्रम विकास निधि	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – औद्योगिक निवेश के लिए अवार्ड
6	पी-16	विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – खुली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष निधि
7	पी-23	अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – अनुसंधान और विकास खर्च के लिए सुपर कटौती नीति
8	पी-27	उन कंपनियों के लिए अधिमान्य कर नीतियां जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई हैं/ उच्च और नई प्रौद्योगिकी उपक्रमों के लिए उपक्रम आयकर कटौती	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – उच्च और नई प्रौद्योगिकी उपक्रम

ख. मैसर्स अनहुई झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि., ने निम्नलिखित योजनाओं अथवा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है -

क्र. सं.	पी. सं.	अट्राजिन में योजना का नाम	अनहुई झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री कं., लिमि.
1.	पी-5	निर्यात सहायता अनुदान	विदेशी व्यापार सब्सिडी
2.	पी-14	स्वच्छ उत्पादन प्रौद्योगिकी नीति	पर्यावरणीय संरक्षण के लिए विशेष नीति
3.	पी-16	विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष नीति	इस कार्यक्रम का विशेष नाम – खुली अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विशेष नीति
4.	पी-58	समुचित पारिश्रमिक से कम के लिए बिजली का प्रावधान	बिजली की खरीद

ग. मैसर्स सिंगरुई झोंगशन बायोसाइंस कं. लिमि. ने यह उल्लेख किया है कि उन्हें उन्हें आरंभ की गई सब्सिडी/ कार्यक्रमों के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और “घाटे को आगे ले जाने से संबंधित कर प्रोत्साहन राशि और मूल्यवर्धित कर से छूट” के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

45. उत्पादक की प्रश्नावली के उत्तर में उपर्युक्त स्वीकारोक्ति ऊपर में उल्लेख किये गये योजनाओं/ कार्यक्रमों के मौजूद होने को दर्शाता है। हालांकि, जैसा की ऊपर में उल्लेख किया गया है, इन उत्पादकों/ निर्यातिकों द्वारा प्रस्तुत की गई प्रश्नावली का उत्तर अलग अलग सी वी डी मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से उत्तर देने वाले निर्यातिकों के लिए अपनाया नहीं जा सकता है। फिर भी इन उत्पादकों/ निर्यातिकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना को उस सीमा तक अपनाया गया है, जिस सीमा तक उसे संगत और उचित पाया गया।

छ. 2. प्रतिसंतुलनकारणीय शुल्क लगाये जाने के लिए सब्सिडी की कार्रवाई की जांच

छ. 3.6.1. अनुदान

46. प्रश्नावली के उत्तर में, भाग लेने वाले उत्पादक/ निर्यातिकों ने कार्यक्रम सं. 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, और 16 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। याचिकाकर्ता ने मैसर्स झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. जो विचाराधीन उत्पाद के उत्तर देने वाले दो अन्य उत्पादक, मैसर्स अनहुई झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री कं. लिमि. और मैसर्स हियांगशु झोंगशन बायोसाइंस कं. लिमि. की मूल कंपनी है, की निर्देशिका वर्तमान जांच में उपलब्ध कराई। इस निर्देशिका का विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों/ निर्यातिकों को विभिन्न नामों जैसे उन्नत उपक्रम अवार्ड, वर्ष की कंपनी अवार्ड, वित्तीय सहायता, विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास परियोजना निधि, खुलापन आर्थिक विकास विशेष निधि, उत्कृष्ट अंशदान अवार्ड, भूमि का उपयोग कर क्रेडिट, विशेष वित्तीय प्रोत्साहन से वित्त पोषित गोल्ड, तकनीकी अभिनवता अनुदान, प्रौद्योगिकीय उपकरण निवेश, जल संरक्षण निर्माण निधि से रहित मुक्त भूमि आदि में परिसंपत्ति, आय और वित्तीय से संबंधित अनुदानों के लिए चीन ने सरकार के प्राधिकारियों से विभिन्न सब्सिडी प्राप्त हुई है। प्राधिकारी झेजियांग झोंगशन द्वारा प्राप्त किये गये विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत सी वी डी मार्जिन का निर्धारण करता है, जिसकी सूचना उनके द्वारा दी गई है। इस उद्देश्य से, “सरकारी सब्सिडी” शीर्ष के अंतर्गत भाग लेने वाली कंपनियों में से एक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई सकल राशि पर किये गये लाभ के रूप में विचार किया गया है। निर्धारित सब्सिडी मार्जिन की राशि *** प्रतिशत है।

छ. 3.6.2. कर प्रोत्साहन राशि और मूल्यवर्धित कर

47. चीन की सरकार और इसकी एजेंसियां अनेक कर कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, जो कुछ श्रेणी के उपक्रमों को, आर एंड डी, प्रौद्योगिकीय अभिनवता/ उन्नयन जैसे क्रियाकलापों जिन्हें ये उपक्रम करते हैं, की उनकी अवस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर कर छूट/ कटौती/ भुगतान/ छूट प्रदान करती है।

48. प्रश्नावली के उत्तर झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. ने निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की सूचना दी है।

क. कार्यक्रम सं. 27 : उन कंपनियों के लिए जिन्हें उच्च और नई प्रौद्योगिकी कंपनियों के रूप में मान्यता दी गई है, अधिमान्य कर नीतियों/ आयकर कटौती

ख. कार्यक्रम सं. 23 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां झेजियांग झोंगशन ने अधिमान्य कर नीतियों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अलावा झेजियांग झोंगशन ने कार्यक्रम सं. 23 : अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) खर्चों की कटौती के लिए कर नीतियां के अंतर्गत लाभ प्राप्त करना स्वीकार किया है। झेजियांग झोंगशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना आयकर गणना में आर एंड डी खर्च के कारण कुछ कटौती दर्शाती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि लाभ की मात्रा के संबंध में पूर्ण व्यूहरा कंपनी द्वारा रिकार्ड नहीं किया गया है। कार्यक्रम सं. 23 और 27 के अंतर्गत प्राप्त कुल लाभ पर विचार करते हुए, प्राधिकारी सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण *** प्रतिशत के रूप में करते हैं।

छ. 3.6.3. अधिमान्य उधार

49. प्राधिकारी ने कार्यक्रम सं. 48 और 49 के संबंध में जांच आरंभ की है। किसी भी उत्तर देने वाले निर्यातक ने यह नहीं माना है कि उसने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। प्राधिकारी ने पूर्व में यह निर्धारण किया है कि चीन के

उपक्रमों को छूट प्राप्त दरों पर ऋण उपलब्ध हैं और इस प्रकार की रियायती उधार के फलस्वरूप निधियों के सीधे अंतरण के रूप में वित्तीय अंशदान किया गया है जबकि चीन की सरकार ने यह उल्लेख किया कि राज्य के स्वामित्व वाले वैकं स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन की सरकार ने न तो प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और न ही उधार देने की दरों के निर्धारण में निवेश/ नियंत्रण के न होने को दर्शने के लिए कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराये हैं। चीन के उपक्रमों (जिसमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक भी शामिल हैं) को ऋण इन उपक्रमों को लाभ प्रदान करता है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के चीनी उत्पादकों को वैचमार्क दरों से कम पर ऋण प्राप्त हुए हैं। प्राधिकारी झेजियांग झोंगशन की वार्षिक रिपोर्ट में सूचित ऋणों और ब्याज के वैचमार्क दर के आधार पर सी बी डी मार्जिन की मात्रा का निर्धारण करने का प्रस्ताव करते हैं। इस आधार पर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन *** प्रतिशत के रूप में है।

छ. 3.6.4. समुचित पारिश्रमिक से कम (एल टी ए आर) के लिए वस्तु और सेवाओं के लिए प्रावधान

छ. 3.6.4.1. भूमि के उपयोग का अधिकार

50. प्राधिकारी चीन की सरकार से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त न होने को नोट करते हैं। पूर्व की जांचों में प्राधिकारी ने भूमि के उपयोग के अधिकारों के रूप में प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी का होना सिद्ध किया था। प्राधिकारी ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है -

- क. कार्यक्रम सं. 60 : औद्योगिक और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूमि के उपयोग का अधिकार
- ख. कार्यक्रम सं. 61 : एस ओ ई के लिए भूमि के उपयोग का आधार
- ग. कार्यक्रम सं. 62 : एफ आई ई के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार

51. मैसर्स झेजियांग झोंगशन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं. लिमि. द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्नावली के उत्तर में यह देखा गया है कि कंपनी ने भूमि प्राप्त कर ली है और भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए कुछ राशियों का भुगतान किया है। झेजियांग झोंगशन ने समय समय पर अधिग्रहित भूमियों और भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराया है। झेजियांग झोंगशन द्वारा अधिग्रहित भूमि की कुल राशि और भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की राशि पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की गई औसत राशि का निर्धारण किया है। भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए भुगतान की गई औसत राशि की तुलना प्राधिकारी द्वारा स्थापित वैचमार्क (थार्डलैंड में प्रचलित कीमत), यह देखा गया है कि झेजियांग झोंगशन को भूमि के उपयोग के अधिकार के लिए रियायती भुगतान से लाभ प्राप्त हुआ है।

52. तदनुसार प्राधिकारी भूमि के उपयोग के अधिकार को प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी के रूप में मानते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी उपर्युक्त वैचमार्क कीमत के आधार पर सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण इस आधार पर *** प्रतिशत करते हैं।

छ. 3.6.4.2. उपयोगिताएं (बिजली)

53. चीन में सार्वजनिक निकाय समुचित पारिश्रमिक से कम पर औद्योगिक उपक्रमों को बिजली उपलब्ध कराते हैं। चीन की सरकार से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त न होने को देखते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारणीय है। इसके अलावा, जबकि उत्तर देने वाले निर्यातिकों/ उत्पादकों ने सभी संगत ब्योरें उपलब्ध नहीं कराये हैं और यह कि इनके उत्तर को ऊपर में उल्लेख किये गये कारण से स्वीकार नहीं किया गया है, बड़ा हुआ लाभ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तय किया गया है। याचिकार्का द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित सब्सिडी मार्जिन *** प्रतिशत है।

छ. 3.6.4.3. कच्चा माल

54. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यदि सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय के सामान्य अथवा विशिष्ट नीति अथवा कार्यक्रम को देखते हुए समुचित कार्य श्रमिक से कम पर किसी व्यापार उपक्रम को उपलब्ध होता है तब वित्तीय

अंशदान का प्रश्न उठता है। ऐसी स्थिति समुचित कार्य श्रमिक से कम पर कच्चे मालों की पहुंच के दल पर वस्तुओं को प्राप्त करने तक यह लाभ दिया जाता है। इस प्रकार की सब्सिडी विशिष्ट हो जाती है जो कि यह इस प्रकार के कच्चे माल/ वस्तुओं का उपयोग करने वाले कुछ उपकरणों तक सीमित है।

55. चीन की सरकार ने निर्धारित रूप में और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा, तमाम भाग लेने वाले विदेशी उत्पादक/ निर्यातक के उत्तरों को ऊपर में उल्लेख किये गये कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह दर्शाते हुए सूचना उपलब्ध कराई है कि यह लाभ तीन प्रमुख कच्चे मालों की बैंचमार्क कीमत और कंपनी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत पर विचार करते हुए चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों को मिला है।

56. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किये गये कच्चा माल में साईनोरिक क्लोरोराइड, आईप्रोपीलेमिन, एथिलेमिन, मेथिसलफोनिल बेनजोइक एसिड, कास्टिक सोडा और मिथाइल अनश्वालिनेट शामिल हैं। प्राधिकारी ने बैंचमार्क कीमतों के रूप में साईनोरिक क्लोरोराइड और कास्टिक सोडा की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क कीमत की तुलना उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा सूचित की गई वास्तविक कच्चे माल की कीमत से करना यह दर्शाता है कि उत्तर देने वाले निर्यातकों को इस कीमत पर इनपुट प्राप्त हुए हैं जो प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी है, जिसके फलस्वरूप समुचित पारिश्रमिक से कम पर इनपुट्स प्राप्त किये गये हैं। तदनुसार, इस आधार पर निर्धारित की गई सब्सिडी का मार्जिन *** प्रतिशत है।

चीन में सी वी डी योजनाओं के संबंध में निष्कर्ष

57. पूर्व में किये गये उल्लेख को ध्यान में रखकर प्राधिकारी यह पाते हैं कि चीन के उत्पादकों को प्रतिकारणीय सब्सिडी से लाभ प्राप्त हुआ है। की गई जांचों, रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, भाग लेने वाले निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर और चीन की सरकार से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त न होने पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने नीचे दी गई तालिका में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न इनमें सब्सिडी के मार्जिन की मात्रा का निर्धारण किया है -

क्र. सं.	कार्यक्रम सं.	योजना का नाम	सी वी डी मार्जिन
1	कार्यक्रम सं. 1-21 (क)	अनुदान	0-5%
2	कार्यक्रम सं. 22-46	कर और मूल्यवर्धित कर प्रोत्साहन राशि (क+ख+ग)	0-5%
	कार्यक्रम सं. 23	आर एंड डी के लिए कर नीतियां	0-5%
	कार्यक्रम सं. 27	अधिमान्य कर नीतियां	
3	कार्यक्रम सं. 48-49	अधिमान्य उधार	0-5%
4	कार्यक्रम सं. 58-62	एल टी ए आर पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान	10-15%
क	कार्यक्रम सं. 58	विजली	0-5%
ख	कार्यक्रम सं. 60-62	भूमि के उपयोग का अधिकार	0-5%
ग	जिसका उल्लेख नहीं किया गया है	कच्चा माल	5-10%
कुल सब्सिडी मार्जिन (1+2+3+4)			10-20%

ज. क्षति और आकलन और कारणात्मक संबंध

ज. 1. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

58. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया है :

क. संबद्ध देश ने इन उत्पादकों द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक सब्सिडी के फलस्वरूप, संबद्ध देश से आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ख. जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में 2014-15 की तुलना में 2.5 से अधिक गुणा के स्तर तक वृद्धि हुई है।

ग. संबद्ध आयातों में भी उत्पादों और खपत की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है।

घ. संबद्ध आयात मर्चेट बाजार के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण करता है। घरेलू उत्पादकों को उनके अपने “घरेलू बाजार” में अल्पसंख्यक में परिणत कर दिया गया है, जबकि चीन के उत्पादकों बहुसंख्यक हो गये हैं।

ड. इस बाजार में पर्याप्त मांग होने के बावजूद, घरेलू उद्योग की क्षमता का 30 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं हुआ है।

च. कैप्टिव खपत से संबंधित तर्कों के बारे में यह अनुरोध किया गया था कि, वह प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के अनुबंध - । के अंतर्गत मूल्यांकन किये जाने वाला एक कारक नहीं है। किसी भी स्थिति में उसमें वृद्धि घरेलू उद्योग को क्षति के होने अथवा न होने को नहीं दर्शाता है।

छ. माल भंडार में गिरावट बढ़ती हुई मांग के कारण हुई है। हालांकि, तब भी, यह गिरावट केवल इस कारण से संभव हो पाई है कि घरेलू उद्योग ने उचित से कम कीमतों पर बिक्री की।

ज. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है।

झ. हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत यह आवश्यक नहीं है कि कीमत में कटौती के फलस्वरूप घाटा होगा।

ञ. आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बनाया है और उसमें ह्रास हुआ है।

ट. लागत में किसी प्रकार की गिरावट न होने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमत में गिरावट हुई है।

ठ. आयात किये गये वस्तुओं की कीमत संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के कम रखी गई है।

ड. बाजार में बहुत अधिक कीमत प्रतिस्पर्धा है। इसके फलस्वरूप, बाजार में अपना स्थान बनाये रखने के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग को अपने सामानों को उचित से कम कीमतों पर मजबूर होना पड़ा है।

ढ. जबकि घरेलू बिक्री की मात्रा ने क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग इस वृद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी लाभप्रदत्ता का त्याग करने के लिए बाध्य हुआ है।

ण. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय में तेजी से गिरावट हुई है।

त. घरेलू उद्योग के लाभ का मार्जिन 9 प्रतिशत से बहुत कम है जैसा कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। इसके अलावा, जांच की अवधि में अर्जित किये गये लाभ का मार्जिन ऐतिहासिक रूप से घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित किये गये लाभ के मार्जिन से बहुत कम है।

थ. 2015-16 के बाद लाभों में गिरावट आई क्योंकि पहुंच कीमत में बहुत तेजी से गिरावट आई और लागतों में उनकी कमी नहीं आई। घरेलू उद्योग के लाभ जांच की अवधि में भी गिरावट आई क्योंकि उत्पादन की लागत और आयातों की पहुंच कीमत के बीच अंतर ज्यादा हो गया।

द. जबकि घरेलू उद्योग उत्पादन, घरेलू बिक्री की मात्रा, क्षमता के उपयोग और बाजार हिस्से में सकारात्मक वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हुआ फिर भी इसके लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है।

ध. किसी भी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निवेश पर उचित लाभ के रूप में 22 प्रतिशत का बैंचमार्क पर विचार किया है जबकि अन्य कारक जैसे लाभप्रदत्ता अथवा क्षमता में उपयोग के बारे में निर्णय मामले दरमाले आधार पर किया जा सकता है।

न. नियोजित पूँजी में वृद्धि बढ़ी हुई कार्यशील पूँजी, और प्रमुख रूप से बढ़ती हुई बिक्री के कारण हुआ है।

प. इन तर्कों के संबंध में की निवेश पर लाभ नकारात्मक नहीं है यह अनुरोध किया गया था कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली में इस तथ्य की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या निवेशों पर लाभ ने

वास्तविक और संभावित गिरावट हुई है और यदि नहीं तब निवेश पर लाभ नकारात्मक है। वर्तमान मामले में निवेश पर लाभ में गिरावट हुई है।

फ. क्षति में आगे और अधिक वृद्धि होने का खतरा है क्योंकि :

- क. आयातों की वृद्धि की दर मांग में वृद्धि की दर का लगभग 2.5 गुणा है।
- ख. जांच की अवधि के बाद की अवधि में भी संबद्ध वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा अपनी विक्री कीमत में कटौती करने के बावजूद, कीमत में कटौती सकारात्मक है, जो यह दर्शाता है कि यदि कोई शुल्क नहीं लगाया जायेगा तब घरेलू उद्योग की कीमतों में इन आयातों के कारण संभवतः आगे और दबाव बनेगा, अथवा उसकी कीमत कम हो जायेगी।
- घ. केवल 20,000 मी. ट. की घरेलू मांग और 50,000 मी. ट. के नियांति की तुलना में लगभग 150,000 मी. ट. का चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की विशाल क्षमताएं हैं। उसकी तुलना में भारत में घरेलू मांग बहुत कम है।
- ङ. यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को आयात की पहुंच कीमत के स्तर तक कटौती करने के लिए बाध्य है तब इसे घाटा होगा और निवेश पर इसका लाभ नकारात्मक हो जायेगा।
- ब. घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारण से नहीं हुई है।
- भ. संबद्ध देश से सबिसडीयुक्त आयातों और घरेलू उद्योग को क्षति के बीच एक स्पष्ट कारणात्मक संबंध है :

 - क. आयातों की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
 - ख. घरेलू उद्योग की कीमतों में आयातों के कारण कटौती हो रही है। इसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को कम करने के लिए बाध्य हुआ है।
 - ग. कीमत पर दबाव के फलस्वरूप, घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है और इसमें ह्रास हुआ है।
 - घ. यद्यपि घरेलू उद्योग अपनी विक्री को बढ़ाने में सक्षम नहीं था, इस प्रकार की वृद्धि कम की गई लाभप्रदता की लागत हुई क्योंकि घरेलू उद्योग को सस्ते आयातों से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।
 - ङ. इसके फलस्वरूप, घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ में गिरावट आई है।

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

59. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध नीचे दिए गए अनुसार है :

- क. जबकि क्षमता जांच की अवधि के दौरान स्थिर रही लेकिन उत्पादन और क्षमता के उपयोग में इस दौरान वृद्धि हुई है जो यह दर्शाता है कि आयातों से कोई क्षति नहीं हो रही है।
- ख. घरेलू उद्योग विक्री के लिए अलग अलग आंकड़े दिए हैं।
- ग. घरेलू विक्री की मात्रा में वृद्धि हुई है जबकि नियांति शून्य रहा है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को कैप्टिव खपत में वृद्धि की आलोचनात्मक तरीके से जांच करनी चाहिए।
- घ. माल भंडार में गिरावट आई है जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग इन सभी वस्तुओं की विक्री करने में सक्षम नहीं है जिसका यह उत्पादन कर रहा है।
- ङ. औसत भंडार को अलग से नहीं देखा जाना चाहिए और इसे उत्पादन और खपत की तुलना में देखा जाना चाहिए।
- च. विक्री की कीमत में कमी कच्चे माल की लागत में गिरावट के कारण है। लागत में एक सूचकांक तक गिरावट आई जिसके कारण विक्री कीमत 18 सूचकांक तक गिर गया है।

छ. चूंकि पहुंच कीमत विक्री की कीमत की तुलना में अधिक है, अतः इसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

ज. कीमत में कटौती को घरेलू उद्योग के समक्ष कार्य निष्पादन और क्या इसके फलस्वरूप हानि हो रही है, के आलोक में देखा जाना चाहिए।

झ. निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि निवेश की गई औसत पूंजी में तब भी वृद्धि हुई है जब संस्थापित क्षमता स्थिर रही है।

ञ. निवेश की गई औसत पूंजी के प्रतिशत के रूप में पी बी आई टी जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक रही।

ट. कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ जबकि उत्पादकता में बहुत अधिक वृद्धि हुई।

ठ. याचिकाकर्ताओं के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार हो रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति के लिए आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

ड. चूंकि घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता का उपयोग, मर्चेंट विक्री और कैप्टिव खपत में वृद्धि हुई है फिर भी आवेदक इस पहलू के संबंध में क्षति का दावा नहीं कर सकते हैं।

ढ. विक्री से प्राप्त आवेदक उद्योग की विक्री की लागत की तुलना में अधिक है और यह लागत पर 9 प्रतिशत का मार्क-अप अर्जित करने में सक्षम है, जिसे कम के रूप में नहीं माना जा सकता।

ण. इसकी भी जांच अवश्य की जानी चाहिए कि क्या इण्डिया इंसेक्टीसाइड्स लिमि. को भारत में इस उद्योग की स्थिति के कार्य निष्पादन सूचकांकों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए बाहर रखा गया है।

त. अन्य घरेलू उत्पादक की विक्री में भी इस अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

थ. घरेलू उद्योग ने अपनी सुविधा के अनुसार इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि आयातों में वृद्धि स्पष्ट रूप से इस देश में मांग में वृद्धि का परिणाम है।

द. आयात की कीमतों को व्यापक तौर पर घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादक नामतः इनसेक्टीसाइड्स इण्डिया द्वारा पेशकश की जाने वाली कीमतों के द्वारा विनियमित किया गया है।

ध. घरेलू उद्योग का वास्तविक क्षति से खतरे के संबंध में दावे का कोई आधार नहीं है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से अनुमानों, अटकलों और दूर की संभावनाओं पर आधारित है।

न. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा किये गये “वास्तविक क्षति का खतरा” के दावे पर विचार करने का निर्णय लेते हैं तब उत्तर देने वाले पक्षकारों को कृपया इसके बारे में सूचना दी जाये और पर्याप्त समय और अवसर इन्हें दिया जाये ताकि वे इस मुद्दे को मौखिक रूप से और लिखित रूप में उठा सकें।

प. घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति, यदि कोई हो, हुई है। अन्य भारतीय उत्पादक नामतः इनसेक्टीसाइड्स इण्डिया लिमि. उन घरेलू उत्पादन में बाजार हिस्से का लगभग 40-45 प्रतिशत रखता है।

फ. इनसेक्टीसाइड्स इण्डिया लिमि. के आंकड़ों पर क्षति का निर्धारण करते समय विचार किया जाना चाहिए।

व. घरेलू उद्योग को क्षति और आयातों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी भी मानदंडों पर आयातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भ. घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति यदि कोई हो, अन्य कारकों के आधार पर स्पष्ट रूप से है जो घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन पर प्रभाव डाला हो और इन आंकड़ों की प्रस्तुति आवेदक द्वारा इस तरीके से की गई है, जिससे की क्षति दर्शायी जा सके जहां कोई क्षति नहीं है।

ज. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच

60. इस संबंध में हितवद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किये गये विभिन्न निवेदनों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से समिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

61. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 13 के उप-नियम (1) और (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या सब्सिडीयुक्त आयातों के भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो रहा है या भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा उत्पन्न हो रही है।

"(1) उल्लिखित देशों से आयातों के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष देंगे कि भारत में इस प्रकार की वस्तु के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति होने का खतरा उत्पन्न होता है अथवा वास्तविक रूप से भारत में किसी उद्योग की स्थापना को बाधा पहुंच रही है।

(2) केवल उस स्थिति को छोड़कर जब क्षति का जांच परिणाम उप-नियम (3) के अंतर्गत किया जाता हो, निर्दिष्ट प्राधिकारी क्षति, क्षति के खतरे, किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा और सब्सिडीयुक्त आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण अन्य बातों के साथ साथ इस नियमावली के अनुबंध निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखकर करेंगे।"

62. प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे मात्रा और कीमत के प्रभाव दोनों की जांच करने के बाद क्षति की जांच करें। क्षति के निर्धारण में दोनों की वस्तुपरक जांच शामिल है :

(क) सामान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा और कीमतों पर सब्सिडीयुक्त आयातों का प्रभाव तथा

(ख) इन आयातों का घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव।

ज्ञ. सब्सिडीयुक्त आयातों की मात्रा का प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(i) **मांग का आकलन**

63. भारत में संबद्ध उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को विश्व में सभी देशों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू विक्री के योग के रूप में किया गया है। यह देखा गया है कि क्षति की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
चीन से आयात	मी. ट.	1,036	1,280	3,320	2,776
अन्य देशों से आयात	मी. ट.	897	67	113	60
घरेलू उद्योग की विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	मी. ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	सूचीबद्ध	100	169	222	210
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	मी. ट.	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	सूचीबद्ध	100	443	390	508
विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई द्वारा विक्री	मी. ट.	***	***	***	***
मांग/ खपत (कैप्टिव को छोड़कर)	मी. ट.	2547	2277	4688	4328
घरेलू उद्योग द्वारा कैप्टिव खपत (केवल डी टी ए इकाई)	मी. ट.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	160	106	117
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा कैप्टिव खपत	मी. ट.	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा कैप्टिव खपत		100	136	160	113
एम आई एल की विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा कैप्टिव	मी. ट.	***	***	***	***

खपत					
एम आई एल की विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा कैप्टिव खपत		100	51	172	286
मांग/ खपत (कैप्टिव सहित)	मी. ट.	3074	2911	5473	5165

(ii) संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और आयातों का हिस्सा

64. संबद्ध आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में अथवा स्वतंत्र रूप में सबिसडीयुक्त आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से विचारधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
चीन/ संबद्ध देश से आयात	मी. ट.	1,036	1,280	3,320	2,776
अन्य असंबद्ध देशों से आयात	मी. ट.	897	67	113	60
कुल आयात	मी. ट.	1,933	1,347	3,432	2,836
भारतीय घरेलू उत्पादन	मी. ट.	1,055	1,318	1,528	1,533
भारतीय घरेलू उत्पादन	सूचीबद्ध	100	125	145	145
खपत (कैटिप्व को छोड़कर)	मी. ट.	2,547	2,277	4,688	4,328
खपत (कैटिप्व सहित)	मी. ट.	3,074	2,911	5,473	5,165

निम्नलिखित की तुलना में संबद्ध देश से आयात :

कुल आयात	%	54%	95%	97%	98%
कुल भारतीय घरेलू उत्पादन	%	98%	97%	217%	181%
खपत (कैटिप्व को छोड़कर)	%	41%	56%	71%	64%
खपत (कैटिप्व सहित)	%	34%	44%	61%	54%

65. यह देखा गया है कि

क. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है जो 168 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

ख. ये आयात जांच की अवधि के दौरान आयातों में 98 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रायः अनन्य रूप से संबद्ध देश से हुए हैं।

ग. भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध देश से आयातों में 98 प्रतिशत से 181 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

घ. भारतीय खपत (कैप्टिव सहित) की तुलना में संबद्ध देश से आयातों में 34 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

ड. संबद्ध देश से आयातों का भारतीय मर्चेंट बाजार का लगभग दो तिहाई की सीमा तक घरेलू मर्चेंट बाजार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

66. इस प्रकार यह देखा गया है कि भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में तथा स्वतंत्र रूप से आयातों में वृद्धि हुई है।

II. संबद्ध आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

67. कीमतों पर सबिसडीयुक्त आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य की जांच करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत से तुलना किये जाने पर सबिसडीयुक्त आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या इस प्रकार के सबिसडीयुक्त आयातों के प्रभाव से अन्य प्रकार से बहुत अधिक हृद तक कीमतों में कमी होगी अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी, जो काफी हृद तक अन्य प्रकार से हुआ होता। घरेलू उद्योग

की कीमतों पर सबिस्डीयुक्त आयातों के प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्लास और कीमत दबाव, यदि कोई हो, के संदर्भ में किया गया है।

(i) कीमत में कटौती

68. कीमत में कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करते हुए की गई है। निवल बिक्री प्राप्ति को बाहरी खर्चों और करों की कटौती करने के बाद तय किया गया है। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना संबद्ध आयातों के सी आई एफ मूल्य में लागू उपकर सहित पहुंच प्रभार और लागू मूल सीमा शुल्क को जोड़कर किया गया है।

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
आयात का पहुंच कीमत	रु/ मी. ट.	241,204	229,123	199,701	210,922
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	79	82
कीमत में कटौती	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	39	61	52
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रेंज	10-20%	0-10%	10-20%	5-15%

69. यह देखा गया है कि आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

(ii) कम कीमत पर बिक्री

70. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमतों का निर्धारण किया है और उसकी तुलना संबद्ध देश से आयात किये गये वस्तुओं के पहुंच मूल्य से किया है ताकि कम कीमत पर बिक्री की सीमा तय की जा सके।

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	पहुंच मूल्य रु/ मी. ट.	क्षति रहित कीमत रु/ मी. ट.	कम कीमत पर बिक्री रु/ मी. ट.	कम कीमत पर बिक्री %	कम कीमत पर बिक्री रेंज
चीन जन. गण.	2,10,922	***	***	***	5-15%

71. यह देखा गया है कि कम कीमत पर बिक्री सकारात्मक है। संबद्ध आयात इस बाजार में क्षति रहित कीमत से कम कीमतों पर हो रहा है।

(iii) कीमत ह्लास अथवा न्यूनीकरण

72. यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या सबिस्डीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्लास हो रहा है और क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से कीमतों पर बहुत अधिक सीमा तक दबाव पड़ेगा अथवा कीमत में वृद्धि रुक जायेगी जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक मात्रा तक हुआ होता। प्राधिकारी क्षति की अवधि के दौरान लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया। यह स्थिति नीचे दी गई तालिका के अनुसार दर्शायी गयी है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
बिक्री की लागत	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
		100	85	92	99
निवल बिक्री प्राप्ति	रु/ मी. ट.	***	***	***	***

		100	86	79	83
चीन से पहुंच कीमत	रु/ मी. ट.	2,41,204	2,29,123	1,99,701	2,10,922

73. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग की विक्री की लागत में क्षति की अवधि के दौरान 1 प्रतिशत तक कमी आई है जबकि इसकी विक्री कीमत में उसी अवधि के दौरान 17 प्रतिशत तक कमी आई है। संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत में भी उसी अवधि के दौरान कमी आई है और वह घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत से कम है। इस प्रकार से यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और साथ ही कीमत हास भी हो रहा है।

घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मानदंड

74. इस नियमावली में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर इन आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका इस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें विक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता का उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; वे कारक जो घरेलू कीमतें, नकदी के प्रवाह, माल भंडार, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की जांच क्षति के अवधि के दौरान की गई है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग और विक्री

75. उत्पादन, क्षमता, क्षमता का उपयोग एवं विक्री के संबंध में क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति नीचे दिये गये अनुसार है :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
क्षमता	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	122	126
क्षमता का उपयोग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	122	126
विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	169	222	210

76. यह देखा गया है कि

- घरेलू उद्योग की क्षमता क्षति की पूरी अवधि के दौरान स्थिर रही है।
- घरेलू उद्योग के उत्पादन में क्षमता उपयोग में वृद्धि के अनुपात में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की विक्री में क्षति की अवधि के दौरान सुधार हुआ है। हालांकि, जांच की अवधि में विक्री में गिरावट आई है।

(ii) बाजार हिस्सा

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
मांग में हिस्सा (कैप्टिव सहित)					
संबद्ध देश से आयात	%	34%	44%	61%	54%
असंबद्ध देश से आयात	%	29%	2%	2%	1%
घरेलू उद्योग की विक्री (कैप्टिव सहित)	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	%	***	***	***	***
विशेष आर्थिक क्षेत्र की विक्री	%	***	***	***	***
कुल	%	100%	100%	100%	100%
मांग में हिस्सा (कैप्टिव को छोड़कर)					
संबद्ध देश से आयात	%	41%	56%	71%	64%
असंबद्ध देश से आयात	%	35%	3%	2%	1%
घरेलू उद्योग की विक्री (कैप्टिव को छोड़कर)	%	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की विक्री	%	***	***	***	***
विशेष आर्थिक क्षेत्र की विक्री	%	***	***	***	***
कुल	%	100%	100%	100%	100%

77. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2015-16 में वृद्धि हुई है और इसके उसके बाद इसमें गिरावट आई और जबकि चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध आयातों का अब बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है।

(iii) माल सूची

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
आरंभिक माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	687	352	140
अंतिम माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	51	20	12
औसत माल भंडार	मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	132	62	28

78. घरेलू उद्योग के पास माल भंडार में 2015-16 में वृद्धि हुई है और उसके बाद 2016-17 में और जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।

(iv) लाभप्रदता, निवेश पर लाभ और नकद लाभ

79. घरेलू उद्योग के लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ नीचे दिये गये अनुसार हैं :

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर पूर्व लाभ	रु/ मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	32	25

कर पूर्व लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	149	72	53
नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	143	70	52
निवेश की गई पूंजी पर लाभ	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	54	35

80. यह देखा गया है कि

क. घरेलू उद्योग के लाभ में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक कमी आई है। प्रति इकाई लाभ में बढ़ते हुए आयातों के साथ क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक कमी आई है।
 ख. घरेलू उद्योग का नकद लाभ और निवेश पर लाभ में 2015-16 में वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि सहित उसके बाद की अवधि में इसमें बहुत अधिक कमी आई है।

(v) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	91	96	135
प्रति इकाई मजदूरी	रु./ मी. ट.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	79	107
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. ट./ सं.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	122	126
प्रति दिन उत्पादकता	मी. ट./ दिन	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	101	122	126

81. कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि के दौरान इन्हीं स्तरों पर रही है। प्रति इकाई मजदूरी और भुगतान की गई मजदूरी में आरंभ में गिरावट आई और उसके बाद उसमें वृद्धि हुई। प्रति कर्मचारी उत्पादकता और प्रतिदिन उत्पादकता में बढ़ते हुए उत्पादन के साथ क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

(vi) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

82. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लाभों में गिरावट आई है और यह कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव बन रहा है। कीमत पर लगातार दबाव घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है।

(vii) वृद्धि

विवरण	इकाई	2014-15	2015-16	2016-17	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	1%	20%	3%
घरेलू बिक्री की मात्रा	%	-	69%	32%	-5%
प्रति इकाई लाभ/ (हानि)	%	-	-11%	-63%	-22%
नकद लाभ	%	-	43%	-51%	-26%

निवेश की गई पूँजी पर लाभ	%	-	16%	-54%	-34%
--------------------------	---	---	-----	------	------

83. जबकि उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दृष्टिगत हुई है, विक्री के आधार पर वृद्धि में जांच की अवधि में गिरावट आ रही है। इसके अलावा यह वृद्धि लाभ, नकद लाभ और निवेश पर लाभ के मामले में नकारात्मक है।

(viii) कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

84. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात भारतीय मर्चेंट बाजार के लगभग दो तिहाई के लिये जिम्मेदार है। इसके अलावा, इस प्रकार के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग की कीमतों पर इस प्रकार के आयातों की पहुंच कीमत के द्वारा दबाव पड़ा है। यद्यपि घरेलू उद्योग अन्य भारतीय उत्पादकों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं फिर भी इस प्रकार के अन्य भारतीय उत्पादकों द्वारा भारित बाजार हिस्सा इन आयातों के द्वारा भारित बाजार हिस्से से तुलना किये जाने पर कम है। चीन के आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यह दर्शाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने की स्थिति में है। इस तथ्य से यह भी स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत में गिरावट के प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी कीमतों को कम करना पड़ा यद्यपि लागत में बहुत अधिक गिरावट नहीं आई थी।

(ix) वास्तविक क्षति संबंधित निष्कर्ष

85. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में नीचे दिये गये अनुसार निष्कर्ष निकालते हैं :

- संबद्ध देशों से आयातों में स्वतंत्र रूप में तथा उत्पादन और खपत की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- संबद्ध देश से आयात भारतीय मर्चेंट बाजार का लगभग दो तिहाई के लिए जिम्मेदार है।
- संबद्ध देश से आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।
- संबद्ध देश से आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।
- संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत संबद्ध वस्तुओं की एन आई पी से कम है।
- घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता के उपयोग में क्षति की अवधि के दौरान में वृद्धि हुई है।
- घरेलू उद्योग की विक्री में 2016-17 तक वृद्धि हुई है लेकिन जांच की अवधि में इसमें गिरावट आई है।
- घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ने क्षति की अवधि के दौरान तेजी से गिरावट आई है।
- निवेश पर लाभ और नकद लाभ में भी बहुत अधिक गिरावट हुई है।
- घरेलू उद्योग की कीमतों पर संबद्ध देश से आयातों की कीमत का प्रभाव पड़ा है।

86. इस कारण से प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

IV. वास्तविक क्षति का खतरा

87. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के खतरे का भी दावा किया है। चूंकि प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। अतः वास्तविक क्षति के खतरे का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है।

कारणात्मक संबंध

88. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नीचे दिये गये अनुसार क्षति हो सकती थी :

(I) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

89. जांच की अवधि के दौरान, संबद्ध देश से आयात कुल आयातों का 98 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है और अन्य असंबद्ध देशों से आयात मामूली मात्रा में हुआ है।

(ii) खपत की पद्धति में परिवर्तन

90. संबद्ध वस्तुओं के खपत की पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(iii) मांग में संकुचन

91. क्षति के अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं हुआ है। इस उत्पाद के लिए मांग में क्षति के अवधि के दौरान वृद्धि हुई है यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान इसमें मामूली गिरावट आई है। हालांकि, सही अर्थों में जांच की अवधि में मांग में आधार वर्ष 2014-15 के दौरान 68 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(iv) विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और उनके बीच प्रतिस्पर्धा

92. ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा की जानकारी नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती थी। इसके अलावा, चूंकि संबद्ध देश से आयातों का भारतीय घरेलू/ मर्चेंट बाजार के दो तिहाई पर कब्जा है। अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है।

(v) प्रौद्योगिकी में विकास

93. किसी भी हितवद्ध पक्षकारों ने प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(vi) घरेलू उद्योग का नियंत्रित कार्य निष्पादन

94. चूंकि घरेलू उद्योग (अर्थात् केवल डी टी ए इकाई) में संबद्ध वस्तुओं का नियंत्रित नहीं किया है, अतः घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के लिए निम्न नियंत्रित कार्य निष्पादन को नहीं ठहराया जा सकता।

(vii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की जा रही और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन

95. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की जा रही और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के कार्य निष्पादन ने प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के बारे में किये गये आकलन पर प्रभाव नहीं डाला है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई क्षति केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

(viii) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

96. चूंकि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है, अतः घरेलू उद्योग को इस आधार पर क्षति नहीं हुई है।

V. कारणात्मक संबंध दर्शाने वाले कारक

97. जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपर में सूची दिये गये अनुसार अन्य ज्ञात कारकों के कारण निर्धारित की क्षति नहीं हुई है, निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति सम्बिडीयुक्त आयातों से हुई है।

क. आयातों में सस्ते सम्बिडीयुक्त कीमतों पर बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू उद्योग की कीमतों में आयातों के कारण कटौती हो रही है।

ग. घरेलू उद्योग की विक्री कीमत में गिरावट आई है। इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव आ रहा है।

घ. सबिसडीयुक्त आयातों के कारण कीमत में हो रही कटौती के परिणामस्वरूप आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

झ. यद्यपि उद्योग घरेलू उद्योग के उत्पादन, विक्री में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है, फिर भी लाभ, नकद लाभ और निवेश की गई पूँजी पर लाभ में संबद्ध देश से कीमत में मापले में कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति के अवधि के दौरान बहुत अधिक कमी आई है।

98. इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध वस्तुओं को सबिसडी दिये जाने और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध हैं।

झ. **क्षति मार्जिन की मात्रा**

99. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं की क्षति रहित कीमत जैसा कि प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, की तुलना जांच की अवधि के दौरान क्षति के निर्धारण के लिए संबद्ध से आयातों की पहुंच कीमत से की गई है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दिये गये अनुसार है :

उत्पादक/ निर्यातक का नाम	पहुंच मूल्य (रु./ मी. ट.)	क्षति रहित कीमत (रु./ मी. ट.)	क्षति मार्जिन रु./ मी. ट.	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन रेंज
चीन जन. गण.	2,10,922	***	***	***	5-15%

ज. **प्रकटन पश्चात् टिप्पणियां**

100. हितवद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात् अनुरोध प्राप्त किये हैं। उनमें उठाये गये अधिकांश मुद्दों को पहले भी उठाया गया था और उनका समाधान भी उपयुक्त रूप से किया गया था। अतिरिक्त अनुरोधों का विश्लेषण नीचे दिये गये अनुसार किया गया है :

ज. 1. **घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध**

101. घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र, निर्यातकों द्वारा प्राप्त सबिसडी, वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे को दोहराया है। इसके अलावा घरेलू उद्योग ने नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया :

क. अप्रत्यक्ष कर में छूट अथवा निर्यात कर में छूट, निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट और इक्विटी की प्रतिसंतुलनकारणीयता के संबंध में आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया है और साथ ही इस प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभों की मात्रा को भी प्रकट नहीं किया है।

ख. क्षति संबंधी मानदंडों को घरेलू उद्योग की हैसियत से गोपनीय के रूप में माना गया है।

ग. याचिकाकर्त्ता की विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को अलग करना इस संबंध में उच्च न्यायालयों के अनेक निर्णयों के आलोक में उपयुक्त नहीं है।

घ. निर्धारित की गई क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए किसानों पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य होगा।

ङ. चीन की सरकार द्वारा सहयोग न किये जाने पर, योजनाओं की प्रतिसंतुलनकारणीयता की कल्पना अवश्य की जानी चाहिए। चूंकि निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है, अतः इस लाभ की मात्रा का निर्धारण सभी कार्यक्रमों के लिए किया जाना चाहिए, जिन पर जांच की शुरुआत के चरण में विचार किया गया था।

च. परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवन के दौरान प्राप्त पूँजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित सभी अनुदानों पर विचार किया जाना चाहिए।

छ. निर्यात कर छूट शुल्क वापसी के समान निर्यात की गई वस्तुओं के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट पर भुगतान किये गये करों की वापसी है। इस कारण से इसे प्रतिसंतुलनकारणीय माना ही जाना चाहिए।

- ज. निर्यात वित्तपोषण और निर्यात क्रेडिट तथा इक्रिटी कार्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिए।
- झ. सब्सिडी मार्जिन का फिर से निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है।
- ञ. वास्तविक क्षति के खतरे की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि क्षति के विभिन्न रूप एक साथ हो सकते हैं।
- ट. क्षति रहित कीमत का निर्धारण अनुबंध - ।।। के अनुसार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह वास्तविक लागत की उपेक्षा करता है और यह घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति का निवारण नहीं करता है।
- ठ. प्रगति पर कार्य के लिए समायोजित कच्चे माल की खपत, खर्च को फिर से आवंटित करना और विक्री खर्च पर विचार करने के बाद क्षति रहित कीमत को फिर से निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किये गये अनुरोध

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग की क्षति के मानदंडों के संबंध में दोहराया है। इसके अलावा, हितबद्ध पक्षकारों ने नीचे दिये गये अनुसार अनुरोध किया :

- क. चूंकि घरेलू उद्योग इस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत की तुलना में अधिक कीमत की वसूली पहले से कर रहा है, घरेलू उद्योग को अतिरिक्त संरक्षण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। यह प्राधिकारी की सतत प्रथा के अनुरूप भी है।
- ख. अट्राजिन टेक्निकल का एवजी (क) बेयर द्वारा लायडिस (ख) बी ए एस एफ द्वारा टिंजर और (ग) धनुका द्वारा सेम्प्रा है; जिसे प्रस्तुत की गई आयातक की प्रश्नावली में सूचीबद्ध किया गया है और कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर इसका उल्लेख किया गया है।
- ग. घरेलू उद्योग ने प्रतिरोध से बचने के लिए जानवूझकर उपभोक्ताओं के नामों को बाहर रखा है। चूंकि अट्राजिन टेक्निकल का कीटनाशक के रूप में सीमित उपयोग होता है और उसकी आयात और विक्री सी आई बी के साथ पंजीकृत कुछ आयातकों तक सीमित है, घरेलू उद्योग इसकी जानकारी न होने का तर्क नहीं दे सकते हैं।
- घ. विशेष आर्थिक क्षेत्र में संबद्ध देशों से आयातों, विशेष आर्थिक क्षेत्र में घरेलू उद्योग की विक्री और विशेष आर्थिक क्षेत्र में विक्री और किये गये आयातों को छोड़कर संबद्ध वस्तुओं की मांग के संबंध में प्रकटन की आवश्यकता है क्योंकि इस प्रकार की सूचना टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास में निष्कर्षों का आधार बन गया था।
- ङ. आयातों में मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग की विक्री, अन्य घरेलू उत्पादकों की कैपिटल खपत और विक्री में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।
- च. यदि अपेक्षित सूचना में कोई विसंगति थी तब प्राधिकारी को अतिरिक्त सूचना की मांग करनी चाहिए थी। प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि ये सभी साक्ष्य जिन्हें वे ए एस सी एम और अपीलीय निकाय के जांच परिणामों के अनुरूप उचित संगत मानते हों, उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दें। इस प्रकार का अवसर दिये बिना उत्तर को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
- छ. दस्तावेजों में विसंगति विक्री प्रबंधक की लापरवाही के कारण और भूलवश हुई थी, उपलब्ध कराये गये बीजक अंतिम बीजक नहीं थे।
- ज. यह उचित नहीं है कि प्रकटन विवरण में उल्लिखित कारणों से झोंगशन समूह के संपूर्ण उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाये विशेषकर क्योंकि सत्यापन रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है कि इस दल ने निर्यातों के सभी लेन देन के लिए संगत अभिलेखों का सत्यापन किया।

ज. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

103. संबद्ध आयातों के भीतर विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को शामिल किये जाने के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि याचिकार्कार्ता की विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को प्राधिकारी के सतत् प्रथा के अनुरूप घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया है।

104. निर्यात क्रेडिट और इक्विटी डालने के संबंधित कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनकारणीयता पर तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पर्याप्त साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए उपलब्ध नहीं है कि निर्यातकों को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ है।

105. इस तर्क के संबंध में की क्षति के खतरे की जांच अवश्य की जानी चाहिए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि जब इन्होंने पहले ही यह निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और इस कारण से क्षति के खतरे की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

106. इस तर्क के संबंध में की क्षति रहित कीमत निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना में अधिक है, यह नोट किया जाता है कि एन एस आर के साथ एन आई पी की उपयुक्त तुलना के लिए, यह तुलना उसी स्तर पर की जानी है। यह नोट किया जाता है कि एन आई पी में किये गये समायोजन के अनुसार समायोजन के उसी स्तर के बाद निवल बिक्री प्राप्ति (अर्थात् रूपये *** प्रति एम टी) क्षति रहित कीमत की तुलना में कम है और इस कारण से इस आधार पर जांच को समाप्त करने के लिए पूरा तर्क अपना महत्व खो देता है।

107. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में की विचाराधीन उत्पाद का एवजी है, प्राधिकारी यह चाहते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि सूचीबद्ध उत्पाद अर्थक्षम एवजी हैं। अर्थक्षम एवजी के रूप में विचार किये जाने के लिए किसी उत्पाद हेतु, यह निश्चित रूप से तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं होना चाहिए, बल्कि तुलनीय कीमतों पर आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए और उसी रूप में उपयोग किये जाने में सक्षम होना चाहिए।

108. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने आयातकों/ उपभोक्ताओं का नाम नहीं दिया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वास्तव में घरेलू उद्योग ने इस याचिका में कुछ आयातकों के नाम दिये हैं और इन आयातकों को अट्राजिन के आयातकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में सूचीबद्ध के रूप में पाया गया है। इन कंपनियों को अट्राजिन सूचीकरण के उत्पादकों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में दर्शाया भी गया है और इस कारण से इसे संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के रूप में उचित रूप से माना जा सकता है। इसके अलावा, याचिका में सूचीबद्ध आयातकों को छोड़कर अन्य आयातकों ने भी इस जांच में भाग लिया है। इसके अलावा, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना सभी संबंधितों की सूचना के लिए डी जी आर की वेबसाइट पर प्रकाशित और राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इस कारण से प्राधिकारी इस तर्क में कोई महत्व नहीं पाते हैं कि आयातकों/ उपभोक्ताओं के नाम गलत इरादे से छुपाए गए थे।

109. इस तर्क के संबंध में कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की सभी इकाईयों के द्वारा आयातों को मात्रा और कीमत क्षति के विश्लेषण के लिए अलग किया जाये, प्राधिकारी ऐसे अनुरोध के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मामले के तथ्यों पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विश्वास किया गया अर्थात् टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास पर विश्वास किया गया था और यह वर्तमान मामले से अलग था। टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास की जांच में, अधिकांश आयातों को विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा किया गया हुआ पाया गया था, जिसके कारण क्षति के अलग अलग विश्लेषण की आवश्यकता हुई। हालांकि, वर्तमान जांच के तथ्यों में इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

110. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क किया है कि आयातों ने मांग में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई है। हालांकि, प्राधिकारी यह मानते हैं कि आयातों में 168 प्रतिशत तक वृद्धि हुई जबकि मांग में केवल 68 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। इस कारण से आयातों में वृद्धि को मांग में वृद्धि के अनुरूप होना नहीं माना जा सकता है।

111. इन उत्तरों में विसंगतियों के संबंध में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सत्यापन के दौरान निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये गये बीजकों को कंपनी के विक्री प्रबंधक द्वारा इन अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि विक्री प्रबंधक कृषि बीजकों को उपलब्ध कराने के लिए एक सक्षम व्यक्ति नहीं था। उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों में यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि झोगशॉन्ट समूह द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना विश्वास किये जाने योग्य नहीं थी और यह निर्यातक अनेक बीजकों जिसकी बीजक संख्या एक ही है, रख रहा था। इसके अलावा, जब सत्यापन दल द्वारा विसंगति की व्याख्या करने के लिए बुलाया गया तब निर्यातक द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इस कारण से निर्यातक के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

112. समुचित अवसर उपलब्ध नहीं कराये जाने के तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि यह न केवल प्रस्तुत की गई सूचना में विसंगति का एक मामला था। बल्कि प्रस्तुत की गई सूचना अपने आप में भ्रामक और अविश्वसनीय पार्इ गई थी। इसके अलावा प्राधिकारी ने निर्यातक को उसी संख्या वाले अनेक बीजकों को जारी करने के बारे में स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवसर दिये थे। इस कारण से उत्तर को अस्वीकार करना न्यायोचित है और यह ए एस सी एम के अंतर्गत अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अंतर्गत प्राधिकारी के दायित्व का उल्लंघन नहीं करता है।

ट. निष्कर्ष

113. हितवद्ध पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना और किये गये अनुरोधों और उपर्युक्त जांच परिणाम में यथारिकार्ड किये गये प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के संबंध में, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि

- विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत में चीन जन. गण. से सब्सिडीयुक्त मूल्य पर किया गया है और इसके फलस्वरूप इस उत्पाद को सब्सिडी दी जा रही है।
- घरेलू उद्योग को विचाराधीन उत्पाद को सब्सिडी दिये जाने के कारण वास्तविक क्षति हुई है।
- वास्तविक क्षति संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के सब्सिडीयुक्त आयातों के द्वारा हुई है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

114. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने का उद्देश्य आमतौर पर सब्सिडी देने की अनुचित व्यापार प्रथाओं के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से संबद्ध देश से आयातों पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

115. यह माना गया है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से संबद्ध वस्तुओं की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रतिसंतुलनकारी शुल्कों को लगाये जाने विशेषकर यदि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाना उस राशि तक सीमित हो जो सब्सिडीयुक्त संबद्ध वस्तुओं के आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निवारण करने के लिए है, द्वारा कम नहीं होगी। इसके विपरीत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने से सब्सिडी दिये जाने के कारण प्राप्त अनुचित लाभों को समाप्त किया जायेगा और समान अवसर सृजित होंगे।

ड. सिफारिश

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस जांच की शुरुआत थी और इसकी सूचना चीन जन. गण. की सरकार सहित सभी हितवद्ध पक्षकारों को दी गई थी और सब्सिडी देने, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर उसके पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध सूचना/ साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए समुचित अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमावली के संबंध में सब्सिडी देने और क्षति और कारणात्मक संबंधों की जांच को शुरू करने और उसे पूरा करने तथा सकारात्मक सब्सिडी मार्जिन स्थापित किये जाने तथा इस प्रकार के सब्सिडीयुक्त आयातों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति को सिद्ध करने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया जाना सब्सिडी देने और

क्षति के प्रभाव को दूर करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी इसे आवश्यक मानते हैं कि वे नीचे दिये गये निर्धारित रूप में और तरीके से चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करें।

117. प्राधिकारी द्वारा अपनाये गये कमतर शुल्क नियमावली के संबंध में, प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए सब्सिडी का मार्जिन और क्षति के मार्जिन के कमतर के बराबर निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाये जाने की सिफारिश करते हैं जिससे की घरेलू उद्योग को क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका से कॉलम 7 में यथाउल्लिखित निश्चयात्मक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किये गये संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से लगाये जाने के लिए करते हैं।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उप शीर्षक	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	नियाति का देश	उत्पादक	सी आई एफ मूल्य के % के रूप में शुल्क राशि
1	38089199, 38089390 और 38089990	अट्राजिन टेक्निकल*	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई अन्य देश	कोई भी	9.52
2	उपरोक्त	उपरोक्त	चीन जन. गण. को छोड़कर अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी	9.52

*इस उत्पाद को निम्नलिखित नामों से भी जाना जाता है :

6-क्लोरो-एन-एथिन- (1-मेथिलेथिल) – ट्राइजिन-2, 4 – डाइमाइन;

2-क्लोरो-4-एथिलामिनो-6- इसोप्रोपाइलामिनो-एस- ट्राइजिन;

2-क्लोरो-4- (एथिलामिनो)-6- (इसोप्रोपाइलामिनो) –एस- ट्राइजिन;

2-क्लोरो-4- (एथिलामिनो)-6- (इसोप्रोपाइलामिनो) –ट्राइजिन;

क्लोरो-4- (प्रोपाइलामिनो)-6- इथीलामिनो-एस- ट्राइजिन;

क्लोरो-4- (प्रोपाइलामिनो)-6- इथीलामिनो-एस- ट्राइजिन, इत्यादि

118. इस अंतिम जांच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2019

FINAL FINDINGS

Subject: Anti-subsidy investigation concerning imports of Atrazine Technical from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 6/19/2018-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the “Rules” or the “Countervailing Duty/ CVD Rules”) thereof:

1. Whereas, M/s Meghmani Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Petitioner” or “Domestic Industry”) has filed a petition, supported by M/s Insecticides (India) Limited, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Countervailing Duty Rules for imposition of Countervailing Duty on imports of “Atrazine Technical” from People’s Republic of China (hereinafter also referred to as the “subject country”).
2. And, whereas, the Authority, on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioner, issued a public notice vide Notification No. 6/19/2018 - DGAD dated 27th August, 2018, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 6 to determine existence, degree and effect of the alleged subsidy and to recommend the amount of anti-subsidy/ countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of People’s Republic of China in India about the receipt of the present anti-subsidy application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 6(5) of the Countervailing Duty Rules.
 - b. The Authority invited the Government of China PR for consultation with the aim of clarifying the situation and arriving at a mutually agreed solution in accordance with Article 13 of the Agreement on subsidies and countervailing measures. The consultation was held on 11th July, 2018 in New Delhi, which was attended by the representatives of the Government of China PR (hereinafter also referred to as GOC). The issues clarified by the GOC were taken on record.
 - c. The Authority issued a public notice dated 27th August, 2018 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating countervailing duty/ anti-subsidy investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
 - d. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 27th August, 2018 to the Embassy of People’s Republic of China, known producers/ exporters from People’s Republic of China, known importers/ users in India and the domestic industry as well as the supporter, M/s Insecticides (India) Limited as per the names and addresses made available by the petitioner and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - e. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/ exporters and to the embassy of the People’s Republic of China in India in accordance with Rule 7(3) of the Rules supra.
 - f. The Embassy of People’s Republic of China in India was also requested to advise the producers/ exporters from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/ exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/ exporters from the People’s Republic of China.
 - g. The Authority sent questionnaires to the GOC (Govt. of China) in order to seek relevant facts/ information with regard to various schemes/ programs where countervailable benefit might have been conferred by the GOC.

- h. In addition, the Authority sent questionnaires to the following known producers/ exporters in People's Republic of China, in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - i. Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd.
 - ii. Shandong Binnong Technology Co., Ltd.
 - iii. Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
 - iv. Zhejiang Province Changxing First Chemical Co., Ltd.
 - v. Shandong Vicome Greenland Chem Co., Ltd.
 - vi. Liaoning Tianyi Pesticide Chemical Co., Ltd.
 - vii. Jinan Kesai Agrochem Co., Ltd.
 - viii. Shandong Qiaochang Chemical Co., Ltd.
- i. In response, the following producers/ exporters from the subject country filed Exporter's Questionnaire Response (EQR) in the prescribed format:
 - i. Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd.
 - ii. Zhejiang Zhongshan Chemicals Industry Group Co. Ltd.
 - iii. Anhui Zhongshan Chemicals Industry Co. Ltd.
- j. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/ users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 7(4) of the Rules:
 - i. Rallis India Limited
 - ii. Vijayalakshmi Insecticides Pesticides Limited
 - iii. PI Industries Ltd.
 - iv. Vantech Chemicals Limited
 - v. Sudarshan Consolidated Ltd
 - vi. Nagarjuna Agrichem Limited
 - vii. GSP Crop Science Private Limited
 - viii. Best Agrochem Pvt. Ltd.
 - ix. HPM Chemicals & Fertilizers Ltd.
- k. In response, the following importers from India filed the Importer's Questionnaire Response (IQR) in the prescribed format:
 - i. ADAMA India Private Limited;
 - ii. Crystal Crop Protection Limited;
 - iii. Krishi Rasayan Exports Private Limited.
- l. Apart from the respondent exporters and importers mentioned above, some legal submissions have been received on behalf of M/s China Crop Protection Industry Association (CCPIA).
- m. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/ submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- n. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the Period of Investigation (POI), which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data, wherever required, for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- o. The Non-Injurious Price (NIP) based on the cost of production and cost to make & sell the like article of subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) has been worked out so as to ascertain whether countervailing duty lower than the subsidy margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

- p. Physical inspection through on-spot verification of the information provided by the applicant domestic industry, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present final findings.
- q. Verification of the information provided by the responding producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority and such information/ evidence, to the extent provided by these parties within reasonable time, has been relied upon for the purpose of present final findings.
- r. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present anti-subsidy investigation is from April, 2017 to March, 2018 (12 Months). The injury investigation period has however, been considered as the period from 2014-15, 2015-16, 2016-17 and the POI.
- s. In accordance with Rule 7(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on 15th February, 2019. All the parties who had attended the oral hearing were advised to file written submissions of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and were advised to offer their rebuttals/rejoinders.
- t. The arguments made in the written submissions/rejoinders received from the interested parties have been considered in the present final findings, to the extent considered relevant and necessary for the present purposes.
- u. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant and material, have been addressed by the Authority, in this final findings.
- v. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information or provided unreliable information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- x. A Disclosure Statement was issued to interested parties on 9th August, 2019 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, giving time up to 16th August, 2019 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately in the present final findings.
- y. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1=₹ 65.33

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

- 4. At the stage of initiation, the product under consideration is defined as:

"The product under consideration is "Atrazine Technical", classifiable under various tariff subheadings No. 38089199, 38089390 and 38089990. The scientific name for Atrazine is 6- chloro-N-ethylN'-(1-methylethyl)-triazine-2,4-diamine."
- 5. Atrazine technical is a commonly used herbicide. It is a systemic triazine herbicide registered for the control of pre and post emergence of broadleaf weeds and grassy weeds. Pure atrazine is an odourless white powder, which is not very volatile, reactive, or flammable. It is synthesized in chemical factory made in the laboratory and does not occur naturally. It is used mostly on farms on crops such as sugarcane, corn, pineapples, sorghum, and macadamia nuts and also to prevent weeds from growing on both highway and railroad rights-of-way. It can be sprayed on croplands before crops start growing.
- 6. Atrazine Technical is designated as a Restricted-Use Pesticide (RUP), and is not available to the general public. RUP's are, by law, only available for sale to certified applicators or persons under their direct supervision, and only for the purpose covered by the applicator's certification. It is known by various names such as
 - (a) 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-Methylethyl)-Triazine-2,4-Diamine;
 - (b) 2-Chloro-4-Ethylamino-6-Isopropylamine-S-Triazine;
 - (c) 2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-S-Triazine;
 - (d) 2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-Triazine;

- (e) Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine;
- (f) Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine, etc

7. Scope of PUC includes all synonyms of the PUC.

D.1. Submissions made by the Domestic Industry

8. The submissions made by the domestic industry with regard to product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

- a. The product under consideration in the present investigation is "Atrazine Technical". Atrazine Technical is used like Active Pharma Ingredient in Pharma industry. This Technical grade is used in making the formulation of various kinds like Atrazine- 50% WP, Atrazine -80% WP, Atrazine- 50% SC, Atrazine -80% WDG and products with different combinations for its marketing and sale as approved by Central Insecticides Board and Registration Committee (CIBRC). The formulations so made are used as fertilizers.
- b. Pure atrazine is an odourless white powder, which is not very volatile, reactive, or flammable. It will dissolve in water. Atrazine is made in the laboratory and does not occur naturally.
- c. The product under consideration may be classified under 3808 91 99, 3808 93 90 and 3808 99 90.
- d. There is no known difference in the subject goods produced by the Indian industry and exported from subject country. The consumers are using the two interchangeably.
- e. The petition clearly shows that the product under consideration has been defined as "Atrazine technical" and its manufacturing process, usage, raw materials, product specifications, etc. have been stated.
- f. The petition states that formulation is packed in bulk or retail packing, for sale to farmers. It has also been mentioned that the producers of formulations sell the same under their own brand name. Therefore, the scope of product under consideration is clear in the petition.
- g. There are no substitutes of the product under consideration, as a producer of atrazine formulation would only be able to use any other product.
- h. No evidence has been provided to show that atrazine as herbicide can be substituted. In any case, different herbicides are appropriate for use in different crops.
- i. Based on the increasing demand and imports, it can be safely concluded that there are no technically and commercially viable substitutes for atrazine technical.

D.2. Submissions made by the other interested parties

9. The submissions made by the exporters, importers, users and other interested parties with regard to product under consideration and like article, and considered relevant by the Authority, are as follows:

- a. The petitioners have provided incorrect information with regard to usage of the product, stating that it can be sprayed on croplands and used by farmers. However, the product under consideration is atrazine technical which cannot be directly used by the farmers. The farmers can use directly only the atrazine formulations.
- b. Applicant industry categorically submitted that there are no viable substitutes. The information about substitutes are available on the website of CIBRC, Therefore, applicant industry cannot take the plea that such information was not known to them. Thus, the information provided in the petition, shows that the applicant industry has taken Hon'ble Authority for granted while filing the application. Therefore, the petition does not satisfy requirements of Rule 6(3).
- c. The petition fails to fulfil the requirements of Rule 6(3) as the applicant industry have referred both atrazine technical and formulations as subject goods, although the petition is only in respect of "Atrazine Technical".
- d. Domestic industry has changed the scope and usage of the PUC. The scope and usage of PUC are different in the application of the domestic industry which is only pertaining to "Atrazine Technical" than in the initiation notification issued by DGTR where the investigation has been initiated for both "Atrazine Technical" and its formulations.
- e. The CIB registration form of applicant industry shows that subject goods are used to produce formulation to show that the usage of PUC mentioned by the domestic industry is with respect to the formulations derived from the PUC i.e., "Atrazine Technical" and not for "Atrazine Technical" itself. Certificate shows that the subject goods are not fit for use on the crops directly by farmers, as mentioned by the applicant industry in their petition.

D.3. Examination by the Authority

10. The Authority has noted submissions made by various interested parties with regard to scope of the product under consideration and like article offered by the domestic industry. With respect to the product under consideration, the Authority notes that the product under consideration in the present investigation, as defined in the initiation notification, is "Atrazine Technical". The scientific name for Atrazine is 6-chloro-N-ethylN'-(1-methylethyl)-triazine-2,4-diamine.

11. The product under consideration is classified under Chapter 38 of the Customs Tariff Act, 1975, and further classified under customs sub-heading 38089199, 38089390 and 38089990. The customs classification is indicative only and in no way binding upon the product scope.

12. Pure atrazine is an odourless white powder, which is not very volatile, reactive, or flammable. It will dissolve in water. Atrazine is made in the laboratory and does not occur naturally. Pure atrazine cannot be used directly by the farmers on their farms and the farmers can use only the atrazine formulations.

13. With regard to the submissions raised by the domestic industry and other interested parties, the Authority notes as under:

- Although the petition filed includes reference to both atrazine and atrazine technical; the Authority notes that all details including, but not limited to, manufacturing process, usage, raw materials, product specifications and nomenclature, have been provided by the domestic industry.
- In any case, the Initiation Notification dated 27th August, 2018 makes it clear that the product under consideration is only "Atrazine Technical". Therefore, the scope of product under consideration was clear from the stage of initiation and did not include "atrazine formulations". Thus, there is no discrepancy or confusion with regard to the scope of product under consideration.
- With regard to the availability of substitutes of the subject goods, it is noted that the interested parties have not provided any details with regard to what products may be considered as a substitute for the product under consideration. Further, it is noted that substitutes of atrazine formulations are irrelevant for the present investigation as the formulations are not the product under consideration, but only the downstream product..

14. The Authority, after analysing the submissions made by all the interested parties, has examined the product scope, and has consequently decided to continue with the scope as defined in the initiation notification.

15. None of the interested parties have made submissions in regards to like article. The Authority holds that there is no known difference between the subject goods exported from China PR and the like article produced by the petitioner. Like article produced by the petitioner and the subject goods imported from China PR are comparable in terms of product characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Therefore, the Authority holds that the Atrazine Technical produced by the domestic industry is a like article to the product under consideration imported from China PR as per the Rules and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM).

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**D.1. Submissions made by the Domestic Industry**

16. The submissions made by the domestic industry during the course of the investigation with regard to the scope of domestic industry and standing are as follows:

- The petitioner accounts for a major proportion of the total domestic production and therefore, constitutes domestic industry as defined in Rule 2(b) of the CVD Rules.
- There is no other producers of subject goods. The entities identified by the interested parties are producers of atrazine formulations, and therefore, users of the product under consideration.
- The petitioner and the supporter, both have provided all the relevant information. The production of the petitioner company constitutes a major proportion of total Indian production. The petitioner is not related to any producer-exporter of the subject product outside India.
- The SEZ plant of the domestic industry cannot be excluded from the scope of domestic industry, as it is engaged in domestic production. Rule 2(b) refers to "domestic production" and not "sale" or "utilization of production".
- The SEZ plant is, in fact, engaged in sales in domestic market as well.
- As regards arguments with regard to Section 54 of the SEZ Act which deems SEZ units to be outside the customs territory, it was submitted that the Section creates a deeming fiction under that law and only for the purpose of that law.

- g. It is only for the purposes of SEZ Act that SEZ units are treated as “outside India”. However, this is merely a legal fiction created for the purposes of that Act, and it does not change the status of the SEZ unit as an Indian entity. This is settled by judgment of the Hon’ble High Court of Allahabad in the case of India Exports Vs. State of U.P.
- h. All domestic laws are applicable to SEZs and therefore, they cannot be excluded only because it is allowed to import inputs without payment of duty.
- i. The interested parties have not identified any provision of the Customs Tariff Act, 1975 which allows for exclusion of SEZ unit.
- j. Direct tax exemption does not disentitle a unit from being considered. A number of entities are entitled to 100% tax exemption, under Section 80-IA, Section 80-IB and so on, which are considered as part of domestic industry.
- k. Exports from SEZ units may attract trade defence measures in other jurisdictions as exports originating in India. In fact, countervailing duties have been imposed against exports from India because of the benefits that have been given to such a unit.
- l. The sales made by the SEZ unit to DTA are not recorded as imports in the import data provided by DGCI&S, while its exports are treated as exports from India.
- m. A number of countries maintain schemes similar to SEZ. Goods exported from such territory are treated as exports from such countries and ADD/CVD considered by the Designated Authority. By the same reasoning, production in SEZ must be considered as part of domestic industry in India.
- n. In the past findings of the Designated Authority, such as in the case of solar cells, polypropylene, etc., SEZ units are considered as part of domestic industry.
- o. Moreover, in a number of other cases, the Designated Authority has considered an EOU to be a part of domestic industry. However, a comparison of EOU benefits and provisions applicable to SEZ units and EOU units would show that SEZ unit have a higher eligibility to be treated as a domestic producer as opposed to EOU units. This is because while a 100% EOU is barred from selling more than 50% of its output in the domestic market, no such bar is placed on the SEZ units.
- p. High courts have consistently noted that SEZ units cannot be considered outside the territories of India. Therefore, such a unit cannot be excluded.
- q. Without prejudice, even if SEZ unit is excluded, the petitioner shall nevertheless account for a major proportion of the domestic production.
- r. There is no merit in the submission that exclusion of India Insecticides Ltd. has been done to distort the performance indices of the state of the industry in India as the petitioner accounts for a major proportion.
- s. The non-participation by Insecticides India Limited is presumably for the reason that Atrazine Technical is not a major product for the producer, and its share in the total revenue of the company is much lower and constitutes a relatively small share of its revenue.
- t. The petitioner company, therefore, constitutes domestic industry within the stipulated criteria provided under the Countervailing Duty Rules and satisfies the requirement of standing.

D.2. Submission of other interested parties

- 17. The submissions made by interested parties with regard to the scope and standing of the domestic industry are as follows:
 - a. As per the current practice of the Authority and legal position in the country, the production of domestic industry in SEZ unit cannot be taken for determining domestic industry.
 - b. As per Section 54 of the SEZ Act, SEZ unit shall be deemed to be outside the customs territory of India for the purposes of undertaking authorized operations. Such authorized operations include production, exports, imports, etc.
 - c. After exclusion of the production of SEZ unit, the applicant industry would no longer be major proportion of the total domestic production in India.
 - d. Authority should look into the data and information of Insecticides India Ltd. to ensure that their exclusion from the scope of the domestic industry is not done to wilfully distort the performance indices of the state of Indian industry.

e. SEZ plant of petitioner, Meghmani Industries Limited should be excluded from the scope of domestic industry as it caters primarily to the export market, as stated by the authority in the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations and as held in the final findings of "Solar Cells whether or not assembled in modules or panels".

D.3. Examination by the Authority

18. Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules defines domestic industry as follows:

"domestic industry means the domestic producers as a whole of the like article or domestic producers whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidized article, or are themselves importers thereof, in which case such producers shall be deemed not to form part of domestic industry".

19. The petition has been filed by M/s Meghmani Industries Limited (MIL), and supported by M/s Insecticides (India) Limited. Apart from these two producers, there are no other known producers of the subject goods in India.

20. It is noted that the petitioner has a unit situated in Special Economic Zone (SEZ). The Authority notes as under with regard to inclusion or otherwise of SEZ unit within the scope of domestic industry:

(a) The SEZ Act, 2005 was enacted to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports and for matters connected therewith or incidental thereto.

(b) Domestic Tariff Area in section 2(i) of the SEZ Act, 2005 means the whole of India (including the territorial waters and continental shelf) but does not include the areas of the Special Economic Zones.

(c) As per Section 2(m) (ii) of the SEZ Act, 2005 "export" includes "supplying goods, or providing services, from the Domestic Tariff Area to a Unit or Developer" (in a SEZ).

d. Section 53 of the SEZ Act, 2005 further provides that –

"(1) A Special Economic Zone shall, on and from the appointed day, be deemed to be a territory outside the customs territory of India for the purposes of undertaking the authorized operations.

(2) A Special Economic Zone shall, with effect from such date as Central Government may notify, be deemed to be a port, inland container depot, land station and land customs stations, as the case may be, under section 7 of the Customs Act, 1962:

Provided that for the purposes of this section, the Central Government may notify different dates for different Special Economic Zones."

e. A perusal of the provisions of the SEZ Act makes it clear that even though SEZ units are a part of the sovereign territory of India, they are distinguished from DTA units. The fundamental objective of establishing SEZ units is promotion of exports. Further, SEZ is excluded from the definition of DTA.

21. In view of the above, the Authority notes that the SEZ unit of the petitioner cannot be treated as part of domestic industry.

22. As regards the DTA unit, the Authority notes that the petitioner has neither imported the subject goods nor is related to any exporter or importer of the subject goods. The Authority further notes that, after excluding the petitioner's SEZ production from both its production and the total Indian production, the petitioner commands a major proportion of the production of the subject goods in India. Accordingly, for the purpose of this investigation, the Authority holds that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Countervailing Duty Rules.

23. Further, since the petitioner and the supporter are the only producers of the like article to subject goods in India, the Authority holds that the petitioner satisfies the requirements of Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by domestic industry

24. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:

a. The exporters have violated the principles laid down by Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September, 2018, which was in force at the time when the responses have been filed. Since the principles laid down

by the trade notice are clarificatory in nature, the same should have been followed by the exporters in filing the response.

- b. The exporters have claimed publicly available information as confidential.
- c. Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd. has accepted the receipt of benefit under a subsidy named Special Fund for Development of Open Economy. However, it has claimed the information about benefit received as confidential in spite of the fact that it's publicly available.
- d. The non-confidential summaries have not been indexed properly and therefore, fail to convey any meaningful information.
- e. Even the channel of distribution has been claimed confidential.
- f. There is no merit in the allegation that the domestic industry has claimed excessive confidentiality as it has provided trends of all injury parameters which is sufficient for the importers to argue on merits of the case.
- g. The disclosures of the domestic industry are consistent with the requirements prescribed under the Trade Notice No. 10/2018.
- h. Formats A to L contain costing and pricing information of a company, which is highly business-sensitive information. However, non-disclosure thereof does not cause any prejudice to the other parties.
- i. With regards to arguments regarding DGCI&S data, it was submitted that the domestic industry is not authorized to disclose the same Trade Notice 07/2018. Further, the domestic industry at the time of procurement of the data, undertakes that it shall not share it or get it placed in public domain.
- j. If the interested parties wanted to obtain the transaction-wise DGCI&S data, they could have submitted the necessary declaration to the Investigating Officer to obtain the same in terms of the trade notice.
- k. The total Indian production has not been disclosed as there are only two producers of subject goods and the disclosure of such production would amount to disclosure to each producer of the production of the other producer.

E.2. Submissions by other interested parties

- 25. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
 - a. The domestic industry has not provided the following information required as per Trade Notice 10/2018:
 - (i) Relationship of petitioners with foreign producers/ exporters/ importers/ domestic producers;
 - (ii) Names and addresses of all other Indian Producers/ users/ importers of the subject goods in India;
 - (iii) Volume and Value of production by all other producers except domestic industry. The domestic industry has not provided this information in actual figures.
 - b. The petitioner has claimed excessive confidentiality, in contravention of the Rule 8 and Trade Notice No. 1/2013 as in section VI, the petitioner has replied to all questions as 'Enclosed. Business Proprietary information.' The petitioner should be asked to disclose the information or provide non-confidential summary.
 - c. The petitioners cannot keep assessment of subsidy as confidential from the exporters.
 - d. The petitioner has not provided transaction-wise DGCI&S import data, although it has provided ITAS import data.
 - e. The applicant industry has claimed excessive confidentiality with regard to new costing formats, volume related information, share of production, demand in India. It has not even provided a non-confidential summary.
 - f. Formats A to L have been claimed confidential in a single page. The non-confidential version has to be a true reflection of the confidential version and should mention all pages, formats and Annexures that are being claimed confidential.
 - g. The rights of defence of parties cannot be fully exercised, since significant data provided in the petition is not properly indexed in the non-confidential version.

E.3. Examination by the Authority

- 26. With regard to confidentiality of information, Rule 8 of Anti-Subsidy Rules provides as follows:

“Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in subrule (1), (2), (3) and (7) of rule 7, subrule (2) of rule 14, subrule (4) of rule 17 and subrule (3) of rule 19 copies of applications received under subrule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in subrule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

27. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non- confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection.

28. Submissions made by the domestic industry and other opposing interested parties with regard to confidentiality to the extent considered relevant and material, were examined by the Authority and addressed accordingly. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non- confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non- confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions made by other interested parties

29. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties:

- a. Levy of countervailing duty will be contrary to public interest. Inappropriate protection measures may not only protect domestic industry but damage its long term and fundamental interest. The rising prices will cause the downstream industry to shrink and a decline in overall demand; and would form an uncompetitive environment.
- b. The petitioners have deliberately concealed information in relation to the importers and users of the subject goods, with intent to mislead Authority and create confusion about product scope. This has impaired the rights of the interested parties to offer comments on product scope and domestic industry.
- c. The intent of providing incorrect information was to reduce the number of interested parties who can counter the misleading and incorrect information provided in the petition.
- d. The effect of exclusion is that the buyers have not been able to provide information regarding purchases from domestic industry, which would have allowed the Designated Authority to verify the sales data furnished by the applicant industry.
- e. It is further submitted that the information relating to actual importers and users have not been provided in the petition. The list of importers provided by applicant industry is of the licensed manufacturers of subject goods, who are not presently manufacturing the subject goods. This is a fact very well known to all companies who are associated with this product as Atrazine Technical is a Restricted Use Pesticide (RUP) and its import, manufacture and sale are also restricted to certain importers/ users/ manufacturers as registered and regulated by Central Insecticides Board (CIB) under Insecticides Act, 1968. Therefore, it is curious as to why the names of these companies were provided to the Authority with a specific assertion that they are importers of the product while they actually are the producers of PUC in India. It is clear that the applicant has provided misleading information with the object of getting the protection with least resistance from the users/ importers of the PUC.

- f. The information supplied by domestic producers should be rejected on grounds of serious mistakes, inconsistencies and inaccuracies. This is especially because in the recent past, the Authority has rejected responses of the exporters for clerical errors also.
- g. Since the subject goods cannot be sold to any unauthorized person, the applicant industry cannot claim that the importers/users are not known to them.
- h. Despite repeated reminders, the revised petition for the period of investigation had not been received.
- i. If India has followed the examples of USA and other countries to insist on initiation of countervailing duty investigations, despite the fact that China has been devoting itself to the construction of market economy; it would negatively impact the dialogue and economic and trade cooperation between the two governments.
- j. The problems arising from bilateral trade should be solved through consultations. The petition filed should be treated considering the broad picture of stable bilateral economic and trade relationship.
- k. The petitioner has provided transaction-wise ITAS data, and not DGIC&S data.
- l. The current CVD proceedings are not justified and should be terminated. Domestic industry has filed erroneous and misleading information in its application. The deficiencies in the application of the domestic industry are irreparable in nature and the same cannot be rectified.
- m. The other interested parties also submitted that, according to its information, the DGTR is recommending CVD duty to the extent of 60% of the existing price of the PUC which has resulted in price rise by 15-20% of “Atrazine Formulations”, the downstream product of the PUC. This increase will further worsen the condition of the Indian farmers, who are already in fix due to huge loans and other financial issues. In this context, this will go against the Hon’ble Prime Minister’s vision of doubling the farmers’ income.
- n. Domestic producers are getting benefit from the subsidized imports of major raw material imported from China. Therefore, assuming that there is subsidy in China, would not impact much to the Domestic Industry, as they are also benefitted by such subsidy.
- o. It is shocking that the domestic producers have intentionally not named any of the farmer associations in the petition despite the fact that it is a legal requirement. It is clear that this non-inclusion of farmers associations clearly is an attempt to get the duties without getting any input from the parties associated with it.

F.2. Submissions made by domestic industry

30. In response to the submissions of the interested parties, the domestic industry submitted as under:

- a. Regarding argument that details of importers and users were suppressed, it was submitted that the domestic industry has given the list of importers as listed in publicly available data.
- b. The list of importers provided by domestic industry is those that are engaged in formulations of subject goods. Any producer of atrazine formulation would invariably be a user or importer of atrazine technical.
- c. Regarding impairment of rights of interested parties to participate, it was submitted that once the initiation notification is published in the Official Gazette, all importers and users are presumed to have notice thereof.
- d. When the exporters are limited to certain authorized exporters, who received the notice of initiation; they must have informed their importers in India regarding the same, who in turn would have informed their buyers, that is, the users in India. In fact, even the ability of the responding importers to participate in the investigation has in no way been impeded by virtue of not being listed in the petition.
- e. As regards arguments of public interest, it was submitted that it is not for the exporter to comment upon when onslaught of cheap imports from the subject country has caused material injury to the domestic industry. Moreover, the duty will ensure level playing field in the market for both Indian and foreign suppliers and the same will not restrict availability of subject goods.

F.3. Examination by the Authority

31. Various submissions made by the interested parties with regard to miscellaneous issues and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:

- a. The Authority notes that the petitioner had filed a duly substantiated petition, as per the prescribed proforma and formats, seeking initiation of countervailing duty investigations. The sufficiency of the petition was analyzed at the stage of initiation and the investigation was initiated after due consideration.

- b. With regards to the submission that all the importers of the subject goods were not identified in the petition, the Authority notes that initiation notification was published by the Authority in the Official Gazette. No prejudice can be claimed due to non-inclusion of some importer's name in the petition.
- c. Regarding the requests made by certain interested parties seeking updated information for the POI considered by the authority, such updated information was filed by the domestic industry and the same was circulated to all interested parties before the oral hearing and the same was placed simultaneously in the public file.
- d. The Authority further notes that the domestic industry had provided transaction-wise import data as per DGCI&S in the petition, and not as per secondary sources, as claimed by the interested parties.
- e. As regards public interest, the Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not prohibit imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers at fair prices. Imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods at fair prices.
- f. Considering the subsidy margin and injury margin as established by the Authority, the impact, if at all, on downstream users of the CVD duty will be minimal.
- g. The mandate of the Authority in the present investigation is to investigate only the subsidies alleged for the PUC (i.e. Atrazine Technical), not those of the raw material of the PUC.
- h. With regards to the submission that the farmers' association were not identified in the petition, the Authority notes that initiation notification was published by the Authority in the Official Gazette. No prejudice can, therefore, be claimed due to non-inclusion of farmer association' name in the petition.

G. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

- 32. The petition filed by the Domestic Industry alleged existence of countervailable subsidies in China. The domestic industry filed submission showing how each of the scheme identified in the petition was required to be investigated.
- 33. Government of China (GOC) was invited for consultation, which was held on 11th July, 2018 in New Delhi and was attended by the representatives of the Government of China (GOC). In the said consultation, GOC contended as follows:
 - a. Programs in form of preferential loans/ lending and programs in the form of Provision of goods and services refers to commercial activities of state owned enterprises but these enterprises cannot be termed as public bodies.
 - b. Program in the form of Income tax refund for re-investment of profits by foreign investment was rescinded.
 - c. Preferential policy for the enterprises of Northeast Region is no longer in force.
 - d. The famous brand program is no longer in force.
 - e. Certain Chinese laws, regulations and policies used as evidence of allegation have expired or do not exist.
- 34. The authority analyzed the list of programs alleged in the petition. Petitioner withdrew following 3 programs from the list of alleged programs vide its letter dated 10.08.2018 stating that it has not been able to gather enough evidence with regard to these schemes:
 - (i) Program No. 17: Clean Production Project Subsidy
 - (ii) Program No. 20: Various grants provided to Beijing Province:
 - (a) Program No. 20(a): Award for Maintaining the Growth by Beijing Governments
 - (b) Program No. 20(b): Award by Beijing Technology Trading Encouraging Centre
 - (iii) Program No. 59: Provision of Water for Less Than Adequate Remuneration
- 35. In view of the submissions raised during the pre-initiation consultation with the GOC and after examination of the schemes alleged in the petition and submission of the petitioner, the Authority identified 4 more programs which were not required to be investigated for the present investigation, as these programs were either withdrawn, and/or the alleged benefit under these programs already expired before the POI or the petitioner has

not provided sufficient evidence for these programs. No investigation was therefore initiated in respect of these following 4 programs:

- (i) Program No. 31: Tariff and VAT exemptions for imported Technologies and equipment
- (ii) Program No. 32: VAT refunds for domestic Firms on Purchases of Chinese made Equipment
- (iii) Program No. 33: VAT Exemptions and Deductions for Central Regions
- (iv) Program No. 47: Government Policy Lending

SUBSIDY SCHEMES UNDER INVESTIGATION

36. The Authority initiated investigations for the following subsidy programs wherein the producers of the product under consideration may have potentially received the countervailable benefits:

I. Programs Identified in the form of Grants

1. Program No.1: The State Key Technology Renovation Projects Fund
2. Program No.2: Famous Brands Program/ Incentive fund for famous-brand products
3. Program No.3: Grants for Anti-dumping/Anti-subsidy Investigations
4. Program No.4: Research & Development (R&D) Assistance Grant
5. Program No.5: Export Assistance Grant
6. Program No.6: Grants for Listing Shares
7. Program No.7: Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation
8. Program No.8: International Market Fund for Export Companies
9. Program No.9: Project funds allowance
10. Program No.10: Special Fund for Energy Saving Technology Reform
11. Program No.11: Funds for supporting technological innovation for the technological small and medium-sized enterprises/ Small and Medium-sized Enterprise Support Funds
12. Program No.12: State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies
13. Program No.13: Enterprise Development Funds
14. Program No.14: The Clean Production Technology Fund
15. Program No.15: Grants for High and new technology industries
16. Program No.16: Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation
17. Program No.18: Various grants provided to Jiangsu province
 - a. Jiangsu Province Finance Supporting Fund
 - b. Environment Protection Award (Jiangsu)
 - c. Jiangsu City Industrial Economy Performance Award
 - d. Changzhou Qishuyan District Environmental Protection Fund
 - e. Changzhou Technology Plan
 - f. Supportive Fund provided by the Government of Xuyi Country
 - g. Enterprise Technology Centers/ Support Funds for Construction of Project infrastructure
18. Program No.19: Various grants provided to Guangdong province
 - a. Special fund for developing trade through science and technology of Guangdong Province
 - b. Guangdong - Hong Kong Technology Cooperation Funding Program
 - c. Guangdong Supporting Fund
 - d. Special Fund for Significant Science and Technology by Guangdong Governments
 - e. Provincial Government of Guangdong Science and Technology Bureau Project Fund

- f. Provincial Loan Discount Special Fund for SMEs by Guangdong Governments
- g. Special Supporting Fund for Key Projects of “500 Strong Enterprises in Contemporary Industries” by Guangdong Governments
- h. Fund for Supporting Strategic Emerging Industries by Guangdong Governments
- i. Special Fund for Export Credit Insurance by Guangdong Governments
- j. Patent Award of Guangdong Province
- k. Supporting Fund for the Development from Guangzhou Local Governments

19. Program No.21: Various grants provided to Anhui Province

- a. Initial Public Offering (IPO) Grants from the Hangzhou Prefecture and the City of (Anhui Province)

II. Programs Identified in form of Tax Incentives and VAT exemption

- 20. Program No.22: Export tax rebate/Tax Refund on Exports
- 21. Program No.23: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses
- 22. Program No.24: Preferential Tax Policies for the Research and Development of FIEs
- 23. Program No.25: Tax Offsets for Research and Development by FIEs
- 25. Program No.26: Income tax credit for the purchase of domestically Produced & manufactured production equipment
- 26. Program No.27: Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies
- 27. Program No.28: Income tax concessions for the enterprises engaged in comprehensive resource utilization (special raw materials')
- 28. Program No. 29: Tax credit concerning the purchase of special equipment.
- 29. Program No.30: Income Tax credits for domestically owned Companies Purchasing Chinese made Equipment
- 30. Program No.34: Reduced Tax Rate for Productive FIEs Scheduled to operate for a period not Less Than 10 Years
- 31. Program No.35: Preferential Tax Policies for Foreign Invested Export Enterprises
- 32. Program No.36: Preferential Tax Policies for FIEs which are Technology Intensive and Knowledge Intensive
- 33. Program No.37: Preferential Tax Policies for FIEs and Foreign Enterprises Which Have Establishments or Places in China and are engaged in Production or Business Operations Purchasing Domestically Produced Equipment's
- 34. Program No.38: Income Tax Refund for Re-investment of FIE Profits by Foreign Investors
- 35. Program No.39: Income Tax Reduction for Advanced Technology FIEs
- 36. Program No.40: Preferential Tax Policies for Enterprises with Foreign Investment (FIEs) Established in Special Economic Zones (excluding Shanghai Pudong Area)
- 37. Program No.41: Preferential Tax Policies for FIEs Established in the Coastal Economic Open Areas and in the Economic and Technological Development Zones
- 38. Program No.42: Local Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas
- 39. Program No.43: Corporate Income Tax Exemption and/or Reduction in SEZs and Other Designated Areas

40. Program No.44: Tariff and Value-added Tax (VAT) Exemptions on Imported Materials and Equipment in SEZs and Other Designated Areas
41. Program No.45: Preferential income tax policy for the enterprises in the Northeast region
42. Program No.46: Tax concessions for Central and Western Regions

III. Identified Programs in the Form of Preferential Loans & Lending

43. Program No.48: Preferential Loans to SOE
44. Program No.49: Discounted Loans for Export-Oriented Enterprises and Export Loan Interest Subsidies.

IV. Identified Programs in the Form of Export Financing and Export Credit

45. Program No.50: Export Seller's Credit.
46. Program No.51: Export Buyer's Credit.
47. Program No.52: Other Export Financing from State-Owned Banks.
48. Program No.53: Export Credit Insurance Subsidies.
49. Program No.54: Export Credit Guarantees.

V. Identified Programs in the Form of Equity

50. Program No.55: Equity infusions
51. Program No.56: Unpaid dividends.
52. Program No. 57: Dividend exemption between qualified resident enterprises.

VI. Identified Programs in the Form of Provision of Goods and Services

53. Program No. 58: Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration.
54. Program No. 60: Land Use Rights in Industrial and Other Special Economic Zone.
55. Program No. 61: Land Use rights for SOEs.
56. Program No. 62: Land Use rights for FIEs
37. Post initiation, the GOC and producers/ exporters of Atrazine Technical from China PR were advised to file response to the questionnaire in the form and manner prescribed and were given adequate time and opportunity to provide verifiable evidence on the existence, degree and effect of alleged subsidy program for making an appropriate determination of existence and quantum of such subsidies, if any.
38. Government of China did not file questionnaire response. The following producers/ exporters of the subject goods, all related with each other, from China PR have filed questionnaire responses:
 - i. M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd.,
 - ii. M/s Anhui Zhongshan Chemical Industry Co. Ltd.
 - iii. M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd.
39. The questionnaire responses filed by the above said three producers/ exporters were verified onsite in China by a verification team from DGTR and the Authority holds that the same cannot be accepted and adopted for the present purposes and for determination of individual CVD margins for the following reasons:

- a. During the course of onsite verification of random sample export documents issued for the PUC by M/s Zhejiang Zhongshan during the POI, it was noticed that two Invoices bearing same Invoice Numbers with different contents mentioned therein (like rate, date) etc have been issued by the company from its accounting software. Following four such sets of invoices were obtained:
 - (i) **Export to Hong Kong:** Two invoices bearing the same Invoice No. *** dated *** with same date, Order No. and quantity were found to have two different rates viz. *** USD/Kg and *** USD/Kg.
 - (ii) **Export to India (M/s ***):** Two invoices bearing the same Invoice No. *** with same quantity, Order No. and rate were found to have two different dates viz. dated *** and ***.
 - (iii) **Export to Brazil (M/s ***):** Two invoices bearing the same Invoice No. *** with same quantity and Order No. were found to have different dates viz. *** and *** and with two different rates viz. *** USD/Kg and *** USD/Kg.
 - (iv) **Export to Israel (M/s ***):** Two invoices bearing the same Invoice No. *** with same quantity and Order No. were found to have two different dates viz. *** and *** and with two different rates viz. *** USD/Kg and *** USD/Kg.
- b. Further, the Verification Team also found few more such instances with similar sets of such invoices and asked for the copies thereof from the company, but the companies did not provide the copies thereof. The company was asked to explain the discrepancy. No satisfactory explanation was given by the company for such major discrepancy in its business and accounting records.
- c. Hence, in the light of above observations of the Verification Team, the accounting software and the books of accounts of these companies cannot be completely relied upon with respect to the recording of transactions. The Authority accordingly holds to not accept the response filed by these foreign producers/exporters.

40. There is no other response from any other Chinese producers/ exporters.

G.1. GENERAL OVERVIEW OF THE ALLEGED SUBSIDY PROGRAMS

Submissions made by domestic industry

- 41. The following submissions have been made by the domestic industry in the petition and during the course of the present investigations:
 - i. The domestic industry has contended that the Government of China PR ("GOC") is providing prohibited and actionable subsidies to its producers/exporters of the subject goods and has provided *prima facie* evidence of existence of such subsidy schemes in terms of legislation and policy documents. Accordingly, the domestic industry identified existence of certain numbers of countervailable subsidy schemes in China PR, within the meaning of ASCM and Indian Rules and have contended that the producers/exporters of subject goods in China PR have benefited from such subsidies.
 - ii. The Petitioner has submitted that the producers/exporters of subject goods have benefited from actionable subsidies. The Government of China has maintained various programs. Petitioner has considered documents such as relevant Chinese laws and regulations, WTO reports, media sources, government reports, independent reports & studies, countervailing duty investigations analysis and findings of other authorities regarding subsidy programs in China PR. The petitioner has provided elaborate information regarding various subsidy programs
 - iii. The programs of the GOC and other Public Bodies in China PR constitute a subsidy because of the following reasons:
 - a. There is a financial contribution by government or a public body, where the government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits), government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases goods;
 - b. Benefit is thereby conferred on the Chinese producers/ exporters of the PUC; and
 - c. The program is specific within the meaning of Indian Rules and ASCM.
 - iv. Relevant Chinese laws and regulations, WTO reports, various Government reports, media reports and independent studies and analysis, findings of other investigating agencies in their ant-subsidy investigations clearly constitute sufficient evidence of the existence of countervailable subsidy programs in China PR. These evidences were made available by the petitioner to all interested parties, including the GOC and the known producers and exporters in China PR.

v. For the purpose of this investigation, the "Government of People's Republic of China" covers all levels of government, i.e. Federal, Central, 27 Provincial, Regional or Local Govt. such as Municipal or City or Township Govts. Village or Local legislative, administrative or judicial agencies/bodies; and State-owned enterprises, operating under the direct or indirect control or influence of the GOC which operate as 'public bodies' within the meaning of the term as defined in the ASCM.

vi. As per the petition the Chinese producers/exporters of the subject goods have received countervailable subsidies under the following programs of various levels of Govts. and they have been classified under 6 broad categories. The various programs classified under these categories are listed below:

- a. Grants
- b. Tax and VAT incentives
- c. Preferential Loans & Lending
- d. Export Financing and Export Credit
- e. Equity Infusion
- f. Provision of Goods and Services

vii. The Government of China has not filed questionnaire response nor provided any meaningful information with regard to these subsidy programs. In the absence of a response by GOC, the actionability of the schemes cannot be questioned by the responding exporters.

viii. The exporters have not contested the actionability of the alleged schemes. The responding exporters have barely mentioned any detail on the benefits received out of the alleged schemes. Therefore, in the absence of a response by the Government of China, the countervailability of the schemes cannot be questioned and shall have to be presumed.

ix. The questionnaire responses filed by the responding exporters are not consistent with the questionnaire format prescribed by the Directorate. The responding exporters have suppressed vital facts and have filed incomplete questionnaire responses.

x. In the following subsidy programs, the exporters have admitted receiving the benefit under the alleged schemes/ programs:

SN	Producer/Exporter/Trader	Subsidy Response out of 49 Schemes
1.	Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co. Ltd.	Accepted benefit for 7 grants and one tax incentives (P-6,7,9,12,13,16,23,27)
2.	Anhui Zhongshan Chemical Industry Co. Ltd.	Accepted benefit for P-5,14,16,58
3.	Xiangshui Zhingshan Bioscience Co. Ltd.	Accepted benefit for only one tax incentive (i.e. Carrying forward of losses in the form of tax incentives and VAT exemption)

xi. In the light of absence of Government Questionnaire response and grossly incomplete and inadequate questionnaire responses filed by the responding producers and exporters, the Authority is requested to treat both the GOC and the responding producers-exporters as non-cooperative in this investigation and accordingly to quantify the subsidy margin based on the facts available.

xii. Due to excessive confidentiality claimed by the exporters, the domestic industry is handicapped in quantifying exporter-specific subsidy margin. However, the subsidy margin has been quantified on the basis of earlier CVD investigations by India and/ or investigations by other investigating authorities.

xiii. There are WTO jurisprudences that suggest that quality and quantity of evidence improves as an investigation progresses and there has been significant improvement in the quality and quantity of evidences that was available in the petition and later submitted by the petitioners at various stages and now available to the Designated Authority for determination.

- xiv. Petition contains the evidence in the form of legal basis, nature of the scheme, financial contribution, and specificity, enterprises that are eligible and that might have availed the benefits under particular scheme, decision of other investigating authorities demonstrating that the schemes actually exist and determined as countervailable with subsidy margins worked out and any other web research. Additional evidences provided by the petitioner during the course of the investigations establish the existence and countervailability of these schemes.
- xv. As regards information concerning availment of benefits by producers/ exporters of the PUC, various schemes identified by the petitioner can be categorized into – (a) enterprise specific programs, (b) sector specific programs and (c) regions specific program..
- xvi. There is no rule which says that anti subsidy duty be imposed only when there is subsidy at the time of imposition. If the existence and availment of subsidy during period of investigation is established, then countervailing duty can be imposed whether or not such subsidy is in existence or availed at the time of imposition of countervailing duty.
- xvii. In the case of subsidy relating to fixed assets, it is not necessary that subsidy should exist at the time of imposition. There may be residual benefit in the POI in respect of benefit availed in earlier years.
- xviii. As regards providing evidence of availment of benefits by individual Chinese producers, domestic industry is not obliged to provide evidence showing availment of benefit by individual producers/exporters. The domestic industry has given sufficient evidences linking the program either with the product under consideration or the enterprise involved in the production or in the region where the exporters are located, and has shown that the subject producers are eligible for benefit under these programs.
- xix. If GOC is non-cooperative, the Designated Authority must apply adverse facts and determine the countervailability of the schemes based on evidences already available on record and proceed further in determining the subsidy margins.

Submissions made by other interested parties

42. The following submissions have been made by the other interested parties:

- (a) With regard to the absence of sufficient evidence in the Petition regarding the nature and existence of the alleged subsidies, the interested parties submitted that with regard to all the subsidy schemes alleged, the petitioner could not establish the existence of three elements comprising a countervailable subsidy namely:
 - (i) Financial contribution by a government or public body;
 - (ii) Benefit; and
 - (iii) Specificity.
- (b) The authority should justify (a) whether it has assessed the adequacy and accuracy of the evidence concerning subsidization; and (b) the basis on which it considers that the petition contains adequate and accurate information for each subsidy alleged.
- (c) None of the programs identified by the petitioners is substantiated with facts and figures that are benefitting the producer/exporter listed in the petition. In fact, the petitioners have themselves admitted in the petition that they do not have evidence to establish that the subsidies have been received by each producer of the product.
- (d) When the petitioners are unable to assess the effects of subsidy, the Authority could not have determined, at the time of initiation, that the subsidy margin is above de – minimis.
- (e) The petitioners cannot keep assessment of subsidy as confidential from the exporter.
- (f) The related entities who have not filed questionnaire response are not involved in production, marketing or distribution of PUC and therefore it is not necessary that these entities file questionnaire response.

- (g) All subsidies received by the companies must be clearly shown in the notes of their audited financial statements. It is meaningless for the petitioner to look for unreported subsidies as they have reported all of them in the questionnaire response. So, it is impossible for the companies to hide any subsidies.
- (h) Non-filing of the response by GOC does affect the response filed by the exporters and their right to seek individual CVD margins.

Examination of Subsidy programs by the Authority

43. Government of China has not filed questionnaire response in the present investigations. The Authority has therefore proceeded on the basis of information provided in the questionnaire response of the participating foreign producer/exporter(s), evidences furnished by the petitioner and other facts available.
44. Out of the 55 subsidy programs identified by the petitioners, the responding producers/ exporters of the PUC in China, who have been verified onsite by the Authority, have accepted availing the benefit of the following schemes:
 - a. M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd has accepted availing the benefit under the following schemes/programs-

S.N	P. No	Name of Schemes in Atrazine	Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd
1	P-6	Grants for Listing Shares	Specific Name of the Program -Supplementary Incentive Fund for the Industrial Economy
2	P-7	Grants provided through the Provincial Fund for Fiscal and Technological Innovation	Specific Name of the Program - Construction Fund For Innovation System Pilot County Special Financial Fund For Provincial Industrial And IT-Based Development
3	P-9	Project funds allowance	Specific Name of the Program- Special Incentive for "Intelligent Safety Production Supervision" Enterprise
4	P-12	State Special Fund for Promoting Key Industries and Innovation Technologies	Specific Name of the Program- Special Financial Incentive Funds for Building A Strong Industrial County
5	P-13	Enterprise Development Funds	Specific Name of the Program-Award For Industrial Investment
6	P-16	Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation	Specific Name of the Program--Special Fund For Development Of Open Economy
7	P-23	Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses	Specific Name of the Program--Super-deduction Policy for Research and Development Expenses
8	P-27	Preferential tax policies for companies that are recognized as high and new technology companies/ Enterprise Income Tax Reduction for High and New Technology Enterprises	Specific Name of the Program--High and New Technological Enterprises

b. M/s Anhui Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd has accepted availing the benefit under the following schemes/programs-

S.N.	P-No	Name of Schemes in Atrazine	Anhui Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd
1.	P-5	Export Assistance Grant	Foreign trade subsidy
2.	P-14	The Clean Production Technology Fund	Special fund for environmental protection
3.	P-16	Special fund for the development of foreign trade and economic Cooperation	Specific Name of the Program -Special Fund For Development Of Open Economy
4.	P-58	Provision of Electricity for Less Than Adequate Remuneration	Purchase of Electricity

c. M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co., Ltd. has mentioned that they have not availed any benefit under the initiated subsidy/programs, and have received benefits under “Tax Incentives and VAT exemption relating to carrying forward losses”.

45. The above acceptance in the questionnaire response of the producer shows existence of the above-mentioned schemes/ programs. However, as stated above, the questionnaire response filed by the producers/exporters cannot be adopted for the purpose of determination of individual CVD margin for the responding exporters. The information made available by these producers/ exporters have nonetheless been adopted to the extent found relevant and appropriate.

G.2. EXAMINATION OF ACTIONABILITY OF SUBSIDIES FOR IMPOSITION OF COUNTERAVAILABLE MEASURES

G.3.6.1. Grants

46. In the questionnaire response, participating producer/exporters have admitted availment of benefit under Program No. 5 6, 7, 9, 12, 13, 14 and16. The petitioner provided prospectus of the M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd., which is the parent company of other two responding producers of the PUC, M/s Anhui Zhongshan Chemical Industry Co. Ltd. and M/s Xiangshui Zhongshan Bioscience Co. Ltd. in the present investigation. Analysis of this prospectus shows that the producers/ exporters of PUC in China have received various subsidies from the Government Authorities in China for grants related to Asset, Income and Finance in various names such as Advanced Enterprise Award, Company of the Year Award, Financial assistance, Foreign trade and economic development projects Funds, Openness economic development specific fund, Outstanding Contribution Award, land use Tax credits, Special financial incentives funded gold, Technical innovation grants, Technological Equipment investment, Water conservancy construction fund less Free allowance etc.. The Authority determines CVD margin under various grants received by Zhejiang Zhongshan as reported by them. For the purpose, gross amounts reported in annual report of one of the participating companies under the head “Govt. subsidies” has been considered as the benefit conferred. The amount of subsidy margin determined is *** %.

G.3.6.2. Tax incentives and VAT

47. The GOC and its agencies administer a number of tax programs, which provide tax exemption/reduction/remission/rebate to certain categories of enterprises based on their location or nature of the activities such as R &D, technological innovation/ upgradation these enterprises undertake.

48. Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd in the questionnaire response has reported availing benefit under following programs

- Program No. 27- Preferential tax policies/ Income Tax Reductions for companies that are recognized as high and new technology companies/ enterprises.
- Program No. 23: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses.

Zhejiang Zhongshan has provided information with regard to preferential tax policies. Further, Zhejiang Zhongshan has admitted having availed benefit under Program No. 23: Tax Policies for the deduction of research and development (R&D) expenses. The information provided by Zhejiang Zhongshan shows some deduction on account of R&D expenses in the income tax computation. The Authority notes that complete details with regard to the quantum of benefit have not been reported by the company. Considering total benefit received under program number 23 and 27, the Authority determines subsidy margin as *** %.

G.3.6.3. Preferential Lending

49. The authority initiated investigations in respect of Program No. 48 and 49. None of the responding exporters have admitted having availed benefit under this program. The Authority has earlier determined that loans are available to Chinese enterprises at discounted rates and such concessional lending results in financial contribution in the form of direct transfer of funds. While GOC stated that the state owned banks operate independently, the authority notes that the GOC neither filed questionnaire response, nor provided some evidence to demonstrate absence of direction/control in fixation of landing rates. Loans to the Chinese enterprises (which includes producers of the PUC as well) provides a benefit to these enterprises. The authority considers that the Chinese producers of the PUC have benefited from loans at less than benchmark rates. The Authority quantifies the CVD margin on the basis of loans reported in the annual report of Zhejiang Zhongshan, and benchmark rate of interest. The subsidy margin determined on this account as *** %.

G.3.6.4. Provision for Goods and Services for less than adequate remuneration (LTAR)**G.3.6.4.1. Land use right**

50. The authority notes the absence of questionnaire response from GOC. The authority in earlier investigations had established the existence of countervailable subsidies in the form of land use rights. Authority has examined the following programs

- Program No. 60: Land Use Rights in Industrial and Other Special Economic Zone,
- Program No. 61: Land Use rights for SOEs
- Program No. 62: Land Use rights for FIE.

51. In the questionnaire response filed by M/s Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd., it is seen that the company has obtained land and has paid certain amounts towards land use rights. Zhejiang Zhongshan has provided details of lands acquired from time to time and the amount paid towards land use right. Considering the total amount of land acquired by Zhejiang Zhongshan and amount paid towards land use right, the authority has determined the average amount paid towards land use right. Comparison of this average amount paid towards land use right with the benchmark established by the authority (price prevailing in Thailand), it is seen that Zhejiang Zhongshan has benefited by concessional payments towards land use right.

52. The authority accordingly holds land use right as countervailable subsidy. Further, the Authority on the basis of abovesaid benchmark price determines subsidy margin of *** % on this account.

G.3.6.4.2. Utilities (electricity)

53. Public bodies in China provide electricity to industrial enterprises at less than adequate remuneration. In view of absence of questionnaire response from the Govt. of China, the Authority holds this program as countervailable. Further, while the responding exporters/producers have not provided all relevant details and that their response has not been accepted due to reason mentioned above, the benefit accrued has been worked out based on facts available. The subsidy margin determined on the basis of information provided by the petitioner and other facts available is *** %.

G.3.6.4.3. Raw materials

54. The Authority notes that financial contribution arises if raw materials become available to a business enterprise at less than adequate remuneration in view of a general or specific policy or a program of the government or a public body. In such a situation, benefit is conferred on the recipient of goods by virtue of access to raw materials at less than adequate remuneration. Such subsidy becomes specific because it is limited to certain enterprise using such raw material/goods.

55. The GOC has not filed questionnaire response in the form and manner prescribed. Further, the responses of the participating foreign producers/ exporter have not been accepted due to reasons mentioned above. The petitioner provided information demonstrating that the benefit has accrued to Chinese producer(s)/ exporter(s) considering the benchmark price of three major raw materials and the actual price paid by the company.

56. Raw material used in the production of subject goods include cyanuric chloride, Isopropylamine, Ethylamine, Methylsulfonyl benzoic acid, Caustic soda and Methyl anthranilate. The Authority has considered international prices of Cyanuric chloride and Caustic soda as the benchmark prices. Comparison of this international benchmark price with the actual raw materials price reported by the responding exporters shows that the responding exporters have received inputs at a price materially below prevailing international prices, resulting in access to inputs at less than adequate remuneration. The subsidy margin accordingly determined on this basis is *** %.

Conclusion on CVD Schemes in China

57. In view of the foregoing, the Authority finds that the Chinese producers are benefited from countervailable subsidies. On the basis of the investigations conducted, facts on record available, questionnaire response of the participating exporters and considering absence of questionnaire response from the GOC, Authority has quantified margin of subsidies therein as shown in table below.

S. N.	Program no.	Name of Scheme	CVD margin
1	Program No 1-21 (a)	Grants	0-5%
2	Program No 22-46	Tax and VAT Incentives (a+b+c)	0-5%
	Program No. 23	Tax Policies for R&D	0-5%
	Program No. 27	Preferential tax policies	
3	Program No 48-49	Preferential Lending	0-5%
4	Program No 58-62	Provision for goods and services at LTAR	10-15%
A	Program No 58	Electricity	0-5%
B	Program No 60-62	Land use right	0-5%
C	Non-alleged	Raw Material	5-10%
Total Subsidy Margin (1+2+3+4)			10-20%

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submission made by the Domestic Industry

58. The domestic industry submitted as under with regard to injury and causal link:

- As a result of significant subsidies received by the producers in the subject country, there has been a drastic increase in the imports from the subject country.
- In the period of investigation, the subject imports have increased to a level of more than 2.5 times of that in 2014-15.
- The subject imports have also increased significantly in relation to production and consumption.
- The subject imports control major share of the merchant market. . The domestic producers have been pushed into a minority in their own “home market”, whereas the Chinese producers have attained majority.
- Despite there being ample demand in the market, more than 30% of the capacity of the domestic industry remains unutilized.
- Regarding arguments pertaining to captive consumption, it was submitted that the same is not a factor to be evaluated under Annexure – I to the Countervailing Duty Rules. In any case, increase therein does not show existence or absence of injury to the domestic industry.
- The decline in inventories is due to the increasing demand. However, even then, the decline has been possible only because the domestic industry made sales at sub-optimal prices.
- The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price underselling is also positive. There is a tremendous pressure on the prices of the domestic industry.
- Contrary to the contention of the interested parties, it is not necessary that price undercutting shall result in losses.
- The imports have suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- There has been a decline in selling price of the subject goods, despite no decline in cost.
- The imported goods are priced below the cost of production of the subject goods.
- There is stiff price competition in the market. As a result, in order to maintain its place in the market, the domestic industry has been forced to sell its goods at sub-optimal prices.

- n. While the domestic sales volume has shown an increase over the injury period, the domestic industry has been forced to sacrifice on its profitability in order to achieve this increase.
- o. There has been a steep decline in the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry.
- p. The profit margin of the domestic industry is much lower than 9%, as has been claimed by the interested parties. Further, the profit margin earned in the period of investigation is much lower than that earned by the domestic industry historically.
- q. The profits post 2015-16 declined as the landed price fell sharply, without a corresponding reduction in costs. The profits of the domestic industry declined even in the period of investigation as the gap between cost of production and landed price of imports widened.
- r. While the domestic industry was able to achieve positive growth in terms of production, domestic sales volume, capacity utilisation and market share, its profits, cash profits and return on investment have declined.
- s. In any case the Designated Authority has considered a benchmark of 22% as reasonable return on investment, while other factors such as profitability or capacity utilization may be decided on a case to case basis.
- t. The increase in capital employed is a result of the increased working capital, majorly because of the increasing sales.
- u. As regards arguments that the return on investment is not negative, it was submitted that Countervailing Duty Rules requires examination of whether there is actual and potential decline in return on investments, and not if return on investment is negative. There has been a decline in the return on investment in the present case.
- v. There is threat of further aggravated injury in as much as:
 - a. The rate of increase in imports is almost 2.5 times of the rate of increase in demand.
 - b. There has been an increase in prices of subject goods even post period of investigation.
 - c. Despite the domestic industry reducing its selling price, the price undercutting remains positive, which shows that the imports are likely to further suppress or depress the prices of the domestic industry, if no duties are imposed.
 - d. There are huge capacities of the subject goods in China PR of about 150,000 MT as against domestic demand of only 20,000 MT and exports of 50,000 MT. As against this, the domestic demand in India is very low.
 - e. If the domestic industry is forced to reduce its price to that of the landed price of imports, it would incur losses and its return on investment would become negative.
- w. Injury to the domestic industry has not been caused by any other factor.
- x. There is clear causal link between the subsidized imports from the subject country and the injury to the domestic industry:
 - a. There has been a significant increase in volume of imports.
 - b. Imports are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the domestic industry has been forced to reduce its prices.
 - c. As a result of the price pressure, the prices of the domestic industry have been depressed and suppressed.
 - d. Although the domestic industry was able to increase its sales, such an increase came at the cost of reduced profitability, as the domestic industry faced stiff competition from the cheap imports.
 - e. Resultantly, the profits, cash profits and return on investment of the domestic industry have declined.

H.2. Submission by other interested parties

- 59. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link, are as follows:
 - a. While capacity has remained constant, production and capacity utilization has increased during the period of investigation, indicating that imports are not causing any injury.
 - b. The domestic industry has given different figures for sales.

- c. Domestic sales volume has increased, while exports have become nil. The Designated Authority should critically examine the increase in captive consumption.
- d. Inventory has declined, indicating that domestic industry is able to sell whatever it is producing.
- e. Average stock should not be seen in isolation and should be seen in relation to production and consumption.
- f. The decrease in selling price is on account of the decline in cost of raw materials. The cost declined by 1 index point, which caused the selling price to decline by 18 index points.
- g. Since landed price is higher than selling price, it has not caused injury to the domestic industry.
- h. Price undercutting should be seen in light of overall performance of the domestic industry and whether it is resulting in losses.
 - i. The Designated Authority is requested to examine the fact that the average capital employed has increased even when installed capacity has remained constant.
 - j. PBIT as percentage of average capital employed remained positive during the period of investigation.
 - k. Number of employees remained unchanged whereas productivity increased substantially.
 - l. The overall performance of the petitioners is improving and injury to the domestic industry cannot be attributed to imports..
 - m. Since production, capacity utilization, merchant sales and captive consumption of the domestic industry have increased, the applicant cannot claim injury on this aspect.
 - n. Sales realization is more than cost of sales of the applicant industry, and it is able to earn a mark-up of 9% on cost, which cannot be considered as low.
 - o. It must be examined if the exclusion of India Insecticides Ltd. has been done to distort the performance indices of the state of the industry in India.
 - p. The sales of other domestic producer has also increased significantly over the period.
 - q. Domestic industry has conveniently overlooked the fact that the increase in imports are evidently a result of increase in demand in the country.
 - r. The import prices have largely been regulated by the prices offered by the Domestic Industry and the other Indian producer namely, Insecticides India.
 - s. The claims of Domestic Industry regarding threat of material injury is baseless and is liable to be rejected as it is purely based on conjectures, surmises and remote possibilities.
 - t. If DA decides to consider the claim of "threat of material injury" made by the domestic industry, the responding parties may kindly be intimated about the same and sufficient time and opportunity should be granted to them to address the same orally and in writing.
 - u. Domestic industry has suffered injury, if any, on account of the inter se competition between the domestic producers of the subject goods. Other Indian producer namely, Insecticides India Ltd. enjoys around 40-45% of the market share in the total domestic production.
 - v. Data of Insecticides India Ltd should be considered while making injury determination.
 - w. Causal link between imports and injury to the domestic industry cannot be established as there is no impact of imports on any of the parameters.
 - x. Injury suffered by the Domestic Industry, if any, is clearly on account of other factors which might have impacted the performance of the domestic industry, and the presentation of the data has been done by the applicant in a manner to show injury where none exists.

H.3. Examination by the Authority

- 60. In consideration of the various submissions made by the interested parties and the domestic industry in this regard, the Authority has examined injury to the domestic industry on account of subsidized imports from the subject country.
- 61. Under sub-rule (1) and (2) of Rule 13 to the Countervailing Duty Rules, the Designated Authority is required to examine whether the subsidized imports are causing or threatening material injury to any industry established in India, or materially retarding the establishment of an industry in India.

“(1) In the case of imports from specified countries, the designated authority shall give a further finding that the import of such article into India causes or threatens material injury to any industry established in India, or materially retards the establishment of an industry in India.

(2) Except when a finding of injury is made under sub-rule (3), the designated authority shall determine the injury, threat of injury, material retardation to the establishment of an industry and the causal link between the subsidized import and the injury, taking into account inter alia, the principle laid down in Annexure I to the rule.”

62. The Countervailing Duty Rules require the Authority to examine injury by examining both volume and price effect. A determination of injury involves an objective examination of both:

- (a) the volume of the subsidized imports and the effect of the subsidized imports on prices in the domestic market for the like article and
- (b) the consequent impact of these imports on domestic industry.

I. Volume effect of subsidized imports and Impact on domestic Industry

(i) Assessment of demand

63. Demand or apparent consumption of the product concerned in India is defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all countries in the world. It is seen that demand has increased over the injury period.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Imports from China	MT	1,036	1,280	3,320	2,776
Imports from other countries	MT	897	67	113	60
Domestic industry sales (excluding captive)	MT	***	***	***	***
Domestic industry sales (excluding captive)	Indexed	100	169	222	210
Sales by Other Indian Producers (excluding captive)	MT	***	***	***	***
Sales by Other Indian Producers (excluding captive)	Indexed	100	443	390	508
Sales by SEZ unit	MT	***	***	***	***
Demand/ Consumption (excluding captive)	MT	2547	2277	4688	4328
Captive Consumption by domestic industry (only DTA unit)	MT	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	160	106	117
Captive Consumption by Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Captive Consumption by Other Indian Producers		100	136	160	113
Captive Consumption by MIL's SEZ	MT	***	***	***	***
Captive Consumption by MIL's SEZ		100	51	172	286
Demand/ Consumption (including captive)	MT	3074	2911	5473	5165

(ii) Import volumes and share of the imports from subject country

64. With regard to volume of the subject imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in subsidized imports either in absolute terms or in relation to production or consumption in India. The volume of imports of PUC from the subject country has been analysed as under:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Imports from China/ subject country	MT	1,036	1,280	3,320	2,776
Imports from other Non-subject countries	MT	897	67	113	60
Total imports	MT	1,933	1,347	3,432	2,836

Indian Domestic Production	MT	1,055	1,318	1,528	1,533
Indian Domestic Production	Indexed	100	125	145	145
Consumption (excluding captive)	MT	2,547	2,277	4,688	4,328
Consumption (including captive)	MT	3,074	2,911	5,473	5,165
Imports from Subject Country in relation to:					
Total imports	%	54%	95%	97%	98%
Total Indian Domestic Production	%	98%	97%	217%	181%
Consumption (excluding captive)	%	41%	56%	71%	64%
Consumption (including captive)	%	34%	44%	61%	54%

65. It is seen that

- The volume of subject imports from the subject country has increased over the injury period substantially showing an increase of 168%.
- The imports are almost exclusively from the subject country, with a 98% of share in imports during the period of investigation.
- The imports from the subject country in relation to Indian production has increased from 98% to 181%.
- The imports from the subject country in relation to Indian consumption (including captive) has increased from 34% to 54%.
- The imports from the subject country hold a major share in the domestic merchant market to the extent of about two-thirds of the Indian merchant market.

66. It is thus seen that imports have increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India.

II. Price effect of subject imports and impact on domestic industry

67. With regard to the effect of subsidized imports on prices, the Authority is required to examine whether there has been a significant price undercutting by the subsidized imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such subsidized imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increase, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact of subsidized imports on the prices of the domestic industry has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any.

(i) Price undercutting

68. Price undercutting has been worked out by comparing the landed price of imports with the selling price of the domestic industry during the investigation period. The net sales realization has been arrived after deducting outward freight and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding landing charge and applicable basic customs duty including applicable cess to the CIF value of subject imports.

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Landed price of imports	Rs/MT	241,204	229,123	199,701	210,922
Net Sales Realization	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	79	82
Price undercutting	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	39	61	52
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	Range	10-20%	0-10%	10-20%	5-15%

69. It is seen that the landed value of imports is below the net sales realization of the domestic industry. Imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market.

(ii) Price underselling

70. The Authority has worked out non-injurious prices of the subject goods and compared the same with the landed values of the imported goods from the subject country to arrive at the extent of price underselling.

Name of the producer/exporter	Landed Value (Rs./MT)	Non-Injurious Price (Rs./MT)	Price underselling Rs./MT	Price underselling %	Price underselling range
China PR	2,10,922	***	***	***	5-15%

71. It is seen that price underselling is positive. The subject imports are entering the market at prices below the non-injurious price.

(iii) Price suppression or depression

72. In order to determine whether the subsidized imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
		100	85	92	99
Net Sales Realization	Rs./MT	***	***	***	***
		100	86	79	82
Landed Price from China	Rs./MT	2,41,204	2,29,123	1,99,701	2,10,922

73. It is noted that the cost of sales of the domestic industry has reduced by 1% over the injury period, whereas its selling price has reduced by 17% during the same period. The landed price of imports from the subject country has also reduced over the same period and is below the cost of production of the domestic industry. Thus, it is seen that the imports from the subject country are depressing the prices of the domestic industry and also causing price suppression.

III. Economic parameters relating to the domestic industry

74. The Rules require that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products. With regard to this, the Rules further provide that the examination of the impact of the subsidized imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

(i) Production, capacity, capacity utilization and sales

75. Position of the domestic industry over the injury period with regard to production, capacity, capacity utilization and sales was as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Capacity	MT	***	***	***	***

	Indexed	100	100	100	100
Production	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	101	122	126
Capacity utilization	%	***	***	***	***
	Indexed	100	101	122	126
Sales (excluding captive)	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	169	222	210

76. It is seen that:

- Capacity of the domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- Production of the domestic industry has increased throughout the period, with a commensurate increase in capacity utilization.
- The sales of the domestic industry have improved over the period. However, sales declined in the period of investigation.

(ii) Market share

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
<u>Share in demand (including captive)</u>					
Imports from Subject Country	%	34%	44%	61%	54%
Imports from Non-subject Countries	%	29%	2%	2%	1%
Domestic industry Sales (including captive)	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
SEZ sales	%	***	***	***	***
Total	%	100%	100%	100%	100%
<u>Share in demand (excluding captive)</u>					
Imports from Subject Country	%	41%	56%	71%	64%
Imports from Non-subject Countries	%	35%	3%	2%	1%
Domestic industry Sales(excluding captive)	%	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	%	***	***	***	***
SEZ sales	%	***	***	***	***
Total	%	100%	100%	100%	100%

77. It is seen that the market share of domestic industry increased in 2015-16 and declined thereafter, whereas the market share of China increased. It is also seen that subject imports are now commanding majority share.

(iii) Inventories

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	687	352	140
Closing inventory	MT	***	***	***	***
	Indexed	100	51	20	12
Average inventory	MT	***	***	***	***

	Indexed	100	132	62	28
--	---------	-----	-----	----	----

78. The inventories with the domestic industry have increased in 2015-16 and thereafter decreased in 2016-17 and the period of investigation.

(iv) Profitability, return on investment and cash profits

79. The profits, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
Profits Before Tax	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	89	32	25
Profits Before Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	149	72	53
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	143	70	52
Return on capital employed	%	***	***	***	***
	Indexed	100	116	54	35

80. It is seen that:

- The profits of the domestic industry have reduced significantly over the injury period. The per unit profits declined significantly over the injury period with the rising imports.
- Cash profits and return of investment of the domestic industry increased in 2015-16, but have reduced significantly thereafter including the POI.

(v) Employment, wages and productivity

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
No of Employees	Nos.	***	***	***	***
	Indexed	100	100	100	100
Wages	Rs Lacs	***	***	***	***
	Indexed	100	91	96	135
Wages per Unit	Rs./MT	***	***	***	***
	Indexed	100	90	79	107
Productivity Per Employee	MT/Nos	***	***	***	***
	Indexed	100	101	122	126
Productivity Per Day	MT/day	***	***	***	***
	Indexed	100	101	122	126

81. The number of employees has remained at the same levels over the injury period. The wages paid and wages per unit declined initially and then increased. The productivity per employee and productivity per day have increased over the injury period, with the increasing production.

(vi) Ability to raise capital investment

82. The Authority notes that the profits of the domestic industry have declined and that the imports are creating a pressure on the prices of the domestic industry. Continued price pressure may impact the ability of the domestic industry to raise capital investment.

(vii) Growth

Particulars	Unit	2014-15	2015-16	2016-17	POI
-------------	------	---------	---------	---------	-----

Production	%	-	1%	20%	3%
Domestic Sales Volume	%	-	69%	32%	-5%
Profit/(Loss) per unit	%	-	-11%	-63%	-22%
Cash Profit	%	-	43%	-51%	-26%
Return on Capital Employed	%	-	16%	-54%	-34%

83. While the production has shown a positive growth, growth on account of sales is declining in the POI. Further, the growth is negative in respect of profits, cash profits and return on investment.

(viii) Factors affecting prices

84. The Authority notes that the imports from the subject country accounts for about two-thirds of the Indian merchant market. Furthermore, such imports are undercutting the prices of the domestic industry. The prices of the domestic industry are depressed by the landed price of such imports. Even though the domestic industry may also face competition from other Indian producers, the market share held by such other Indian producers is lower when compared to the market share held by the imports. Market share of Chinese imports increased significantly over the injury period. This shows that the imports from the subject country are in a position to influence the prices of the domestic industry. This is also evident from the fact that the domestic industry had to reduce its prices in response to the decline in landed price of the subject goods, even though there was no significant decline in the cost.

(ix) Conclusions on material injury

85. Based on above, the Authority concludes as under with regard to injury suffered by the domestic industry

- Imports from the subject country have substantially increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- Imports from subject country account for about two-thirds of the Indian merchant market.
- Imports from subject country are undercutting the prices of the domestic industry.
- Imports from subject country have had a depressing effect on the prices of the Domestic industry.
- The landed price of the imports from subject country is below the NIP of the subject goods.
- The production, and capacity utilization of the domestic industry have increased over the injury period.
- Sales of the domestic industry increased till 2016-17, but declined in POI.
- The profitability of the domestic industry has declined drastically over the injury period.
- There has been a significant decline in the return on investment and cash profits as well.
- The prices of the domestic industry are impacted by the price of imports from the subject country.

86. The Authority, therefore, concludes that the domestic industry has suffered material injury.

IV. Threat of material injury

87. Petitioner has also claimed threat of material injury. Since Authority holds that the domestic industry has suffered material injury, the threat of material injury is not being analysed.

V. Causal Link

88. The Authority examined whether other known factors could have caused injury to the domestic industry as follows:

(i) Volume and prices of imports from third countries

89. During the period of investigation, the imports from subject country account for 98% of the total imports and the imports from other non-subject countries are insignificant in volume.

(ii) Changes in the pattern of consumption

90. There have been no changes in the pattern of consumption of the subject goods, which could have caused injury to the domestic industry.

(iii) Contraction in demand

91. There is no contraction in the demand during injury period. Demand for the product has increased over the injury period, although there has been a slight decline during the period of investigation as compared to the preceding year. However, in essence, the demand in the POI has increased by 68% over the base year 2014-15.

(iv) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

92. There is no known trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry. Further, as the imports from the subject country command almost two-thirds of the Indian domestic/merchant market, the injury caused to the domestic industry cannot be attributed to inter-se competition between domestic producers.

(v) **Developments in technology**

93. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(vi) **Export performance of the domestic industry**

94. Since the domestic industry (i.e. only DTA unit) has not exported the subject goods, the injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to poor export performance.

(vii) **Performance of other products being produced and sold by the domestic industry**

95. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The injury considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

(viii) **Productivity of the domestic industry**

96. Since the productivity of the domestic industry has improved, the injury to the domestic industry is not on this account.

VI. Factors showing causal link

97. While the other known factors as listed above do not appear to have caused the injury determined, the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the subsidized imports:

- There has been a significant increase in imports at cheap subsidized prices.
- Imports are undercutting the prices of the domestic industry.
- The selling price of the domestic industry has declined. The imports are depressing the prices of the domestic industry.
- Price undercutting being caused by the subsidized imports is resulting in increase in market share of imports.
- Although the production, sales of the domestic industry have increased over the injury period, the profits, cash profits and return on capital employed have declined significantly over the injury period, due to stiff price competition from the subject country.

98. The Authority therefore holds that there is causal link between the subsidization of the subject goods and the injury suffered by the domestic industry.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

99. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed price of the exports from the subject country for determination of injury margin during the period of investigation. The injury margin thus determined is as under

Name of the producer/exporter	Landed Value (Rs./MT)	Non-Injurious Price (Rs./MT)	Injury margin Rs./MT	Injury margin %	Injury margin range
China PR	2,10,922	***	***	***	5-15%

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

100. The post disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under

J.1. Submission made by the domestic industry

101. The domestic industry reiterated its submissions regarding scope of domestic industry, subsidies received by the exporters, material injury and threat of material injury. In addition, the domestic industry submitted as under:

- a. The essential facts with regard to countervailability of indirect tax exemptions or export tax rebates, export financing and export credit and equity have not been disclosed, as also the quantum of benefits received under such schemes.
- b. The injury parameters have been treated as confidential qua the domestic industry.
- c. The exclusion of SEZ unit of the petitioner is not appropriate in light of numerous decisions of High Courts in this regard.
- d. The impact of duties, considering the injury margin determined, on the farmers would be negligible.
- e. In the absence of cooperation by Government of China, the countervailability of schemes must be assumed. Since exporters have not cooperated, benefit should be quantified for all programs which were considered at the stage of initiation.
- f. All grants tied to capital assets received over the average useful life of assets should be considered.
- g. Export tax rebate is a refund of taxes paid on inputs used for exported goods, similar to duty drawback. It must, therefore, be held countervailable.
- h. Export financing and export credit, as well as equity programs should be considered.
- i. There is a need for re-quantification of subsidy margin.
- j. The threat of material injury should also be examined, as different forms of injury may co-exist.
- k. The non-injurious price should not be determined as per Annexure – III, as it ignores actual cost and does not address injury suffered by the domestic industry.
- l. There is a need for re-determination of non-injurious price after considering raw material consumption adjusted for work-in-progress, re-allocation of expenses and consideration of selling expenses.

J.2. Submission made by other interested parties

102. The other interested parties reiterated their submissions with regard to injury parameters of the domestic industry. Additionally, the interested parties submitted as under:

- a. Since the domestic industry is already recovering a higher price than the non-injurious price determined by the Authority, there is no question of additional protection to the domestic industry. This is also in line with consistent practice of the Authority.
- b. The substitutes of atrazine technical are (a) Loudis by Bayer (b) Tynzer by BASF and (c) Sempra by Dhanuka; which have been listed in the importers' questionnaire filed and also mentioned on the website of Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
- c. The domestic industry has intentionally excluded names of users to avoid resistance. Since Atrazine Technical is a restricted use pesticide, and its import and sale are restricted to certain importers registered with CIB, the domestic industry cannot plead ignorance.
- d. There is a need for disclosure with regard to imports from subject countries in SEZ, sales of domestic industry in SEZ and demand of subject goods excluding sales and imports made in SEZ, as such information had formed basis of conclusions in Textured Tempered Glass.
- e. Imports have increased in line with increase in demand. Further, the sales of domestic industry, captive consumption and sales of other domestic producer have increased significantly.
- f. If there was any deficiency in information required, the Authority ought to have called for additional information. The Authority is required to give ample opportunity to all interested parties to provide all evidence they consider relevant, in line with the ASCM and findings of Appellate Body. Rejection of response, without providing such an opportunity, is in violation of principles of natural justice.
- g. The discrepancy in documents was due to the negligence of sales manager and by mistake, the invoices provided were not the final ones.
- h. It is not reasonable to reject the whole response of Zhongshan Group due to the reason mentioned in the Disclosure Statement, especially as the verification report mentioned that the team verified relevant records for all transactions of exports.

J.3. Examination by the Authority

103. With regard to inclusion of SEZ unit within subject imports, the Authority notes that the SEZ unit of the petitioner has been excluded from the scope of domestic industry, in line with the consistent practice of the Authority.
104. As regards the arguments on countervailability of export credit and equity infusion programs, the Authority notes that sufficient evidence is not available to conclude that the exporters have benefitted under these programs.
105. With regard to the argument that threat of injury must be examined, the Authority finds that it has already concluded that the domestic industry has suffered material injury and therefore there is no need to examine threat of injury.
106. With regard to the argument that the non-injurious price is higher than the net sales realization, it is noted that for appropriate comparison of NIP with NSR, the comparison has to be made at the same level. It is noted that the net sales realization after same level of adjustment (i.e. Rs. *** per MT), as made in the NIP, is less than the Non-Injurious price and therefore the entire argument for termination of the investigation on this ground loses its merit.
107. With regard to the argument of other interested parties that there are substitutes of the product under consideration, the Authority finds that the interested parties have not adduced any evidence to demonstrate that the products listed are viable substitutes. For a product to be considered as a viable substitute, it must not only be technically substitutable, but also should be readily available at comparable prices and capable of being used in the same manner.
108. Regarding the argument that the domestic industry had not given names of importers/users, the Authority notes that the domestic industry has indeed furnished names of some importers in the petition and these importers have been found to be listed in the public domain as importers of Atrazine. These entities are also shown in the public domain as producers of atrazine formulations and can, therefore, be reasonably construed as users of the subject goods. Furthermore, the importers other than the ones listed in the petition have also participated in the investigation. Moreover, the initiation notification is also published on the DGTR website and notified in the Gazette for information of all concerned. Therefore, the Authority does not find any merit in the argument that the names of importers/users were suppressed with mala-fide intention.
109. As regards the argument that imports by all SEZ units must be segregated for analysis of volume and price injury, the Authority finds no basis for such a request. The Authority notes that the facts of the case relied upon by the interested parties, that is, Textured Tempered Glass, were different from the present case. In the investigation into Textured Tempered Glass, majority of imports were found to be made by SEZ units, prompting the need for segregated analysis of injury. However, such is not the case in the facts of the present investigation.
110. The opposing interested parties have argued that the imports have increased in line with increase in demand. However, the Authority finds that the imports increased by 168%, while the demand increased by only 68%. Therefore, the increase in imports cannot be considered to be in line with the increase in demand.
111. As regards the discrepancies in the responses, the Authority notes that the invoices presented by the exporter during the verification had been provided to the officers by the sales manager of the company. It cannot be considered that the sales manager was not a competent person to provide the sales invoices. The documents provided clearly showed that the information submitted by the Zhongshan Group was unreliable and the exporter was maintaining multiple invoices, bearing the same invoice number. Furthermore, no explanation was provided by the exporter, when called upon by the verification team to explain the discrepancy. Therefore, the argument of the exporter cannot be accepted.
112. As regards to the contention of not being provided adequate opportunity it is noted that it was not only a case of discrepancy in the information submitted. Rather, the information filed itself was found to be misleading and unreliable. Further, the Authority had provided ample opportunity to the exporter to explain the issuance of

multiple invoices with the same number. Therefore, the rejection of response is justified and does not violate the obligations of Authority under ASCM or the principles of natural justice.

K. CONCLUSIONS

113. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings, the Authority concludes that

- The product under consideration has been exported to India from China PR at subsidized value, thus resulting in subsidization of the product.
- The domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the product under consideration.
- The material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES

114. The Authority notes that the purpose of imposition of countervailing duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of subsidization so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of countervailing duty would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

115. It is recognized that the imposition of countervailing duty might affect the cost of the subject goods. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of the countervailing measures, particularly if the levy of the countervailing duty is restricted to an amount necessary to redress the injury caused to the domestic industry by the imports of subsidized subject goods. On the contrary, imposition of countervailing measures would remove the unfair advantages gained by subsidization and create level playing field.

M. RECOMMENDATION

116. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties including the Government of China PR and adequate opportunity was given to provide information/evidence on the aspect of subsidization, injury and causal links in favour or against thereof. Having initiated and conducted the investigation into subsidization, injury and causal links in terms of the Rules laid down and having established positive subsidy margin as well as material injury to the domestic industry caused by such subsidized imports, the Authority is of the view that imposition of definitive countervailing duty is required to offset subsidization and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive countervailing duty on the imports of the subject goods from China PR in the form and manner described hereunder.

117. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive countervailing duty equal to the lesser of margin of subsidy and margin of injury for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the definitive countervailing duty as mentioned in Col 7 of the duty table below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of the subject goods, originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/sub heading	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Duty amount as a % of CIF Value
1	38089199, 38089390 and	Atrazine Technical*	China PR	Any other country, including	Any	9.52

	38089990			China PR		
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	9.52

*The product is also known under the following names:

6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-Methylethyl)-Triazine-2,4-Diamine;

2-Chloro-4-Ethylamino-6-Isopropylamine-S-Triazine;

2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-S-Triazine;

2-Chloro-4-(Ethylamino)-6-(Isopropylamino)-Triazine;

Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine;

Chloro-4-(Propylamino)-6-Ethylamino-S-Triazine, etc.

118. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority